आरआईएस

वार्षिक रिपोर्ट 2014 – 15

अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यसूची को स्वरूप प्रदान करने के लिए नीतिगत अनुसंधान

आरआईएस
विकासशील देशों की अनुसंधान
एवं सूचना प्रणाली

आरआईएस विकासशील देशों का थिंक टेंक

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस), नई दिल्ली स्थित एक स्वायत्तशासी नीतिगत अनुसंधान संस्थान हैं जोकि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास, व्यापार, निवेश एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित मामलों में विशेषज्ञ है। आरआईएस प्रभावशाली नीतिगत वार्ता को बढ़ावा देने एवं वैश्विक एवं क्षेत्रीय आर्थिक मामलों के संबंध में विकासशील देशों में क्षमता निर्माण के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

आरआईएस की कार्य योजना का मुख्य केन्द्र बिन्दु दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना और विभिन्न मंचों पर बहुपक्षीय बातचीत में विकासशील देशों के साथ समन्वय करना है। आरआईएस क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के कई प्रयासों की अंतः सरकारी प्रक्रियाओं में कार्यरत है। आरआईएस अपने विचारकों के गहन नेटवर्क के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों एवं विकास भागीदारी के कैनवस से संबंधित नीतिगत सुसंगतता को सुदृढ़ करता है।

आरआईएस एवं इसकी कार्ययोजना के संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया इसकी वेबसाइट www.ris.org.in देखें।

– अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यसूची को स्वरूप प्रदान करने के लिए नीतिगत अनुसंधान

आरआईएस
विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

कोर 4-बी, चौथा तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड,
नई दिल्ली - 110 003, भारत
दूरभाष: 91-11-24682177-80 फैक्स: 91-11-24682173-74
ई-मेल: dgoffice@ris.org.in वेबसाइट: http://www.ris.org.in

विषय वस्तु

अध्यक्ष का संदेश		*iii*
महानिदेशक की रिपोर्ट		*v*
I	नीतिगत अनुसंधान	1
II	नीति शोध पत्र	19
III	नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ	21
IV	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम	63
V	प्रकाशन कार्यक्रम	68
VI	आकंड़ा एवं सूचना केंद्र	77
VII	मानव संसाधन	79
VIII	वित्तीय विवरण	85

आरआईएस संचालन परिषद

अध्यक्ष

श्री श्याम सरन
पूर्व विदेश सचिव
विदेश मंत्रालय

उप–अध्यक्ष

डॉ. वी.एस. शेषाद्री

पदेन सदस्य

डॉ. एस. जयशंकर
विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय

सुश्री रीता ए. तेवतिया
वाणिज्य सचिव
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

श्री शक्तिकांत दास
सचिव
आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

प्रो. आशुतोष शर्मा
सचिव
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

सुश्री सुजाता मेहता
सचिव (ईआर एव डीपीए)
विदेश मंत्रालय

अपदेन सदस्य

प्रोफेसर बी बी भट्टाचार्य
पूर्व उपकुलपति
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

प्रो. दीपक नैयर
मानद प्राध्यपाक, अर्थशास्त्र
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

कमोडोर सी उदय भास्कर, वीएसएम
निदेशक
सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज

***सदस्य सचिव* (पदेन)**

प्रो. सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक (10 सितंबर 2014 से)

अनुसंधान सलाहकार परिषद

अध्यक्ष

राजदूत एस. टी. देवारे
पूर्व सचिव
विदेश मंत्रालय

सदस्य

राजदूत ए. एन. राम
पूर्व सचिव
विदेश मंत्रालय

प्रो. एन. एस. सिद्धार्थन
मानद प्राध्यापक
मद्रास स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स

प्रो. पुलिन बी. नायक
दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स

प्रो. रथिन रॉय
निदेशक
राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान

श्री चरनजीत सिंह
संयुक्त सचिव (एमईआर)
विदेश मंत्रालय

विशेष आमंत्रित

डा. नागेश कुमार
प्रमुख, यूएन–ईएससीएपी दक्षिण और
दक्षिण–पश्चिम एशिया कार्यालय, नई दिल्ली

सदस्य सचिव

प्रो. सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक, आरआईएस

अध्यक्ष का संदेश

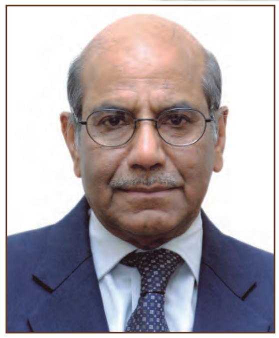

श्री श्याम सरन
अध्यक्ष, आरआईएस

भारतीय विदेश नीति क्षेत्रीय तथा वैश्विक, दोनों स्तरों पर भारत के आर्थिक सहयोग और एकीकरण को अधिक सुदृढ़ और गहन बनाने का लक्ष्य रखते हुए आगे परिवर्तन के साथ आगे बढ़ रही है, इस परिप्रेक्ष्य में आरआईएस की भूमिका भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। आरआईएस को विविध क्षेत्रीय और बहुपक्षीय आर्थिक मुद्दों पर भारत सरकार को नीतिगत शोध पत्र और टिपिणीया ंप्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्थान ने अपनी शोध कार्यसूची को तदनुसार समायोजित किया है ताकि तेज़ी से बदलते अंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिदृष्य का आंकलन और विश्लेषण हो सके। आरआईएस राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर कार्यरत अन्य शोध संस्थानों के साथ भी सक्रिय और प्रभावी संवाद करता रहा है ताकि नीतिगत संवाद को बढ़ावा दिया जा सके। इसका लक्ष्य विभिन्न महत्त्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों पर नीतिगत एकजुटता और महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों पर विकासशील देश का एक विशिष्ट दृष्टिकोण सृजित करना है। इसके संकाय और अनुसंधान सहयोगियों ने इन विचार–विमर्षों में भरपूर योगदान किया है। इस प्रतिवेदन में इनका विषयवार विवरण दिया गया है।

वैसे तो अनेक दशकों से दक्षिण–दक्षिण सहयोग के प्रयास होते रहे हैं परंतु इधर कुछ वर्षों से अंतरराष्ट्रीय विमर्श और व्यवहार में इसका महत्व बढ़ गया है। दक्षिण की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विकास और विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित विकासपरक सहयोग के प्रसार को देखते हुए अब इसे पारंपरिक उत्तर–दक्षिण सहयोग से भिन्न एक अलग प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। 'विकास समझौते' की एक नवीन संकल्पना का उदय हुआ है, जो व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, कौशल उन्नयन, ऋण व्यवस्थाओं तथा रियायती अनुदानों के पांच विभिन्न स्तरों पर कार्य करती है। आरआईएस–भारत विकास सहयोग मंच (एफआईडीसी) इन क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यसूचियों को बढ़ावा देने

में पूरे ज़ोर से लगा हुआ है। इसी प्रकार आरआईएस के आसियान–भारत केंद्र ने अपने कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए अथक परिश्रम किया है, जिसमें गतिविधियों तथा शोध अध्ययनों की एक संपूर्ण वार्षिक योजना समाहित है। इस वार्षिक प्रतिवेदन में इन का विस्तृत वर्णन किया गया है।

आरआईएस संचालन परिषद् के मेरे साथियों ने आरआईएस अनुसंधान कार्यसूची बनाने में अमूल्य सुझाव दिए तथा इसके कार्यों का मार्गदर्शन किया, जिसके लिए मैं उनका आभारी हूं। उपाध्यक्ष राजदूत वी. एस. शेषाद्रि समय–समय पर न केवल अपने अमूल्य सुझावों और विचारों से हमें लाभान्वित करते रहे हैं बल्कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय व्यापार विषयों पर महत्वपूर्ण शोधपत्र भी प्रदान किए हैं। आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने नवीन ऊर्जा और सराहनीय पहलकदमी से संस्थान का नेतृत्व किया है। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ और वरिष्ठ शोध संकाय सदस्यों तथा संकाय के अन्य सभी सदस्यों, कर्मियों की एक टीम के रूप में उनके नेतृत्व में उच्च स्तरीय काम करने केलिए भी प्रशंसा करता हूं। आरआईएस सरकार को अपेक्षित विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान करते हुए और क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के मंचों पर सामयिक मुद्दों के संबंध में सुविज्ञ सार्वजनिक बहस कराते हुए सतत अपना योगदान देता रहेगा।

श्याम सरन

महानिदेशक की रिपोर्ट

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक

तेज़ी से बदलती अंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थिति के संदर्भ में आरआईएस की कार्ययोजना में तीव्र वृद्धि हुई है। अनुसंधान कार्यसूची में चार व्यापक विषयों पर ध्यान जारी रहाः वैश्विक आर्थिक मुद्दे तथा दक्षिण–दक्षिण सहयोग, व्यापार और निवेश संबंधी क्षेत्रीय पहलें, क्षेत्रीय सहयोग, व्यापार सुगमीकरण और संयोजकता, तथा प्रौद्योगिकी और विकास संबंधी नए मुद्दे। इन व्यापक विषयों की परिधि के अंतर्गत पूरे हो चुके और चल रहे अध्ययनों का विस्तृत वर्णन इस वार्षिक प्रतिवेदन में किया गया है।

आरआईएस कार्य–योजना सतत विकासमान अंतरराष्ट्रीय आर्थिक कार्यसूची को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इस दिशा में आरआईएस ने अनेक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया ताकि विभिन्न विषयों पर सुविज्ञ नीतिगत प्रतिक्रिया निर्मित हो सके। इस प्रतिवेदन में इनमें से कुछ विषयों की चर्चा की गई है। जिनमें शमिल हैं सातवां दक्षिण एशिया शिखर सम्मेलन, भारत तथा हिंद महासागर पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनः समुद्री व्यापार तथा सभ्यतामूलक संपर्कों का नवीनीकरण, बल्क औषधियों के क्षेत्र में आयात पर भारत की बढ़ती निर्भरता, नई कृषि प्रौद्योगिकियों में भारत–अफ्रीका साझेदारी, ब्रिस्बेन जी–20 शिखर सम्मेलन के मुद्दे, ड्राफ्ट आईपी नीति, विज्ञान राजनय, भारत–चीन संबंध इत्यादि। जैसा बताया गया है, संस्थान ने इस तथा अन्य संबंधित मुद्दों पर अनेक पुस्तक–पुस्तिकाएं भी प्रकाशित की हैं।

दक्षिण–दक्षिण सहयोग का संवर्धन और सुदृढ़ीकरण आरआईएस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आरआईएस का यह कार्य इसके द्वारा आरंभ किए गए भारतीय विकास सहयोग मंच (एफआईडीसी) की संगति में आगे बढ़ रहा है। अपनी गतिविधियों के अंतर्गत एफआईडीसी ने नए विकास बैंक व दक्षिण–दक्षिण सहयोग और उत्तर–2015 विकास कार्यसूची विषयक महत्वपूर्ण बैठकों और दक्षिण–दक्षिण सहयोग पर एक विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया है। एफआईडीसी ने दक्षिण–दक्षिण सहयोग के संवर्धन के क्षेत्र में काम करने वाले समाजिक संगठनों की भूमिका पर चर्चा करने के लिए क्षेत्रीय परामर्शों का भी आयोजन किया।

आरआईएस ने विविध नेटवर्कों के माध्यम से अन्य शोध संस्थानों के साथ अपने संपर्कों का विस्तार किया है। जी–20 प्रक्रिया को आगत प्रदान करने के लिए आरआईएस टी–20 नेटवर्क में सम्मिलित हआ। आरआईएस अन्य नेटवर्कों जैसे आसियान और पूर्व एशिया के लिए आर्थिक अनुसंधान संस्थान ईरिया (ERIA), बंगाली की खाड़ी बहु–क्षेत्रक तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (BIMSTEC); इब्सा (IBSA): भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका; ब्रिक्स (BRICS): ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण

अफ्रीका, हिंद महासागर परिसीमा संघ (आइयोरा) (IORA), आदि के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। वैश्विक स्तर पर, आरआईएस ने दक्षिणी शोध संस्थानों के संजाल (नेटवर्क ऑफ सदर्न थिंक टैंक्स/NeST) की संकल्पना और स्थापना की ताकि दक्षिणी शोध संस्थानों से सामूहिक सरोकारों को उठाना सुगम किया जा सके।

संस्थान ने दक्षिण के राजनयिकों तथा व्यवहर्ताओं के लिए 'दक्षिण–दक्षिण सहयोग अध्ययन' पर क्षमता निर्माण के नए कार्यक्रम भारतीय तकनीकी आर्थिक सहयोग (ITEC) की भी शुरुआत की। इस वर्ष यह कार्यक्रम केवल आरंभिक 30 प्रतिभागियों के साथ चलाया गया। संस्थान अपने 'अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दे और विकास नीति' (आईईआईडीपी) विषय पर विशेष आइटेक क्षमता निर्माण कार्यक्रम का सतत आयोजन जारी रखे हुए हैं।

आरआईएस का व्यापार और निवेश संपर्कों के क्षेत्रीय तथा उभयपक्षीय विश्लेषण संबंधी कार्य का और विस्तार हुआ है और वह गहनतर हुआ है। क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संबंधी अपनी कार्य–योजना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आरआईएस, दक्षेस (सार्क) जैसे प्रमुख नेटवर्कों के साथ भी सक्रिय रूप से संवाद करता आ रहा है। संस्थान ने अपना प्रसिद्ध प्रतिवेदन दक्षिण एशिया विकास और सहयोग (एसएडीसीआर) भी प्रकाशित किया है। इसी प्रकार आरआईएस के आसियान–भारत केंद्र ने भी अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों में आसियान–भारत थिंक टैंकों के नेटवर्क विषयक तृतीय गोलमेज, दिल्ली संवाद VII: आसियान–भारत द्वारा उत्तर–2015 कार्यसूची का निर्धारण, आसियान–भारत संयोजकता पर गोलमेज, भारत–आसियान साइबर सुरक्षा सम्मेलन, आसियान–भारत के विशिष्ठ व्यक्तियों के व्याख्यान, वैश्विक उत्पादन नेटवर्कों से जुड़ने पर आसियान–भारत संगोष्ठी आदि सम्मिलित हैं। केंद्र के आसियान–भारत आर्थिक सहयोग मज़बूत करने के विभिन्न विषयों पर प्रकाशन भी सामने आ चुके हैं। इनमें आसियान–भारत विकास सहयोग रिपोर्ट 2015 भी शामिल है।

आरआईएस की अनुसंधान गतिविधियों का वेबसाइट, मुद्रण तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों और सामाजिक माध्यमों के द्वारा भी प्रचार–प्रसार किया जाता है।

मैं इस अवसर पर आरआईएस अध्यक्ष, राजदूत श्याम सरन और आरआईएस संचालन परिषद् के सभी सदस्यों को आरआईएस की कार्य–योजना के क्रियान्वयन में उनके मार्गदर्शन महत्तवपूर्ण और सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। हम विदेश मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य विभागों जैसे आर्थिक मामलों के विभाग वाणिज्य मंत्रालय तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रति भी उनके निरन्तर सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं। विविध गतिविधियों में हमारे साथ सहयोग करने के लिए हम अपने साझीदार संस्थानों के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं।

आरआईएस संकाय के अपने वरिष्ठ सहकर्मियों और अनुसंधान तथा प्रशासनीक टीमों के अन्य सभी सदस्यों से मुझे मिले सहयोग के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। हम आरआईएस के सभी लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं ताकि विकासशील देशों की सेवा कर सकें।

सचिन चतुर्वेदी

I

नीतिगत अनुसंधान

वर्ष 2014–15 के दौरान आरआईएस का अनुसंधान कार्यक्रम मुख्यता क्षेत्र चार स्तंभों के आधार पर व्यवस्थित हैंः (क) वैश्विक आर्थिक मुद्दे और दक्षिण–दक्षिण सहयोग; (ख) व्यापार और निवेश पर क्षेत्रीय पहलें; (ग) क्षेत्रीय सहयोग, व्यापार सुगमीकरण और संयोजकता; (घ) नई प्रौद्योगिकियां और विकास के मुद्दे। इन वृहत्तर विषय वस्तुओं के अंतर्गत विशिष्ट अध्ययन हैंः

अ. वैष्विक आर्थिक मुद्दे और दक्षिण–दक्षिण सहयोग

देशों का वर्गीकरण और जी–20

प्रो. सचिन चतुर्वेदी / प्रो. मनमोहन अग्रवाल

जी–20 के लिए तुर्की की अध्यक्षता ने समावेशन को अपने फोकस की मुख्य विषय वस्तु घोषित किया है। इससे पहले कि हम तुर्की की अध्यक्षता के प्रस्ताव पर आगे बढ़ें, पर्चे ने ऐसे अनेक संकल्पनात्मक मुद्दे उठाए हैं जिनकी विस्तृत पड़ताल की ज़रूरत है। भारत को निम्न आय के विकासशील देशों (एलआईडीसी) के समूह से बाहर रखने से, जैसा कि तुर्की प्रेसीडेंसी ने सुझाया है, विकासशील देशों से संबंधित कई वैश्विक मुद्दों पर भारत का नेतृत्व छिन जाएगा। इस मुद्दे पर एक नीति सार लाने के अलावा आरआईएस इस पर और काम करने की पेशकश करता है। अध्ययन के अंग के रूप में एक नीति सार भी प्रकाशित किया गया है।

नैरोबी विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) मंत्रिमंडलीय के समक्ष मुद्दे

प्रो. सचिन चतुर्वेदी / प्रो. एस. के. मोहंती / प्रो. राम उपेन्द्र दास / डा. रवि के. श्रीनिवास / प्रो. टी. सी. जेम्स

(i) विश्व व्यापार संगठन (WTO) महानिदेशक रॉबर्टो आजेवेडो ने नैरोबी, केन्या, में 15–18 दिसम्बर को होने वाले 10वें मंत्रिमंडलीय सम्मेलन से पहले दोहा विकास कार्यसूची के बचे हुए मुद्दों का समाधान करने का आवाहन किया है। फिर भी,

आरआईएस ने उन तमाम डब्ल्यूटीओ मुद्दों पर काम करना जारी रखा है जो आने वाले नैरोबी मंत्रिमंडलीय सम्मेलन के लिए विशेष तौर पर प्रासंगिक हैं। ऐसा एक मुद्दा है कृषि समझौते (एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर) की परिधि के भीतर विकासशील देशों के खाद्य सुरक्षा सरोकारों का एक 'स्थाई समाधान' तलाशना। आरआईएस में इस समय इस मुद्दे पर मौजूदा ठहराव का आकलन करने और आगे बढ़ने का कोई मार्ग सुझाने पर काम चल रहा है।

दूसरी ओर, खबरें सुझाती हैं कि हो सकता है भारत ने नैरोबी सम्मेलन से पहले ही व्यापार सुगमीकरण समझौते (टीएफए) की संपुष्टि कर दी हो। इसका अर्थ होगा टीएफए के तहत 130 से अधिक प्रावधानों सहित लगभग 13 अनुच्छेदों का अनुपालन। यह आवश्यक है कि इस अनुपालन–लागत का आकलन किया जाए, अल्प और दीर्घ दोनों अवधियों मेंय और सुधरी हुई टीएफए अवसंरचना के कारण संभावित व्यापार लाभों के बरक्स उन्हें तौला जाए।

(ii) जहां तक बौद्धिक संपदा मामलों का संबंध है निम्नलिखित मुद्दो पर चर्चा की उम्मीद हैः

- सदस्य इस पर चर्चा करेंगे कि सौदेबाजियों को वाइन और स्पिरिट्ज के लिए जीआई (भौगोलिक संकेतकों) तक ही सीमित रखा जाए या इन सौदेबाजियों को वाइन और स्पिरिट्ज के अलावा वस्तुओं के जीआई तक बढ़ाया जाए। इस पर सर्वानुमति है।
- व्यापार और टेक्नॉलॉजी अंतरण में, संभावित बौद्धिक संपदा (आईपी) मुद्दे जो ट्रिप्स (TRIP) के अनुच्छेद 66.2 के क्रियान्वयन से निकलते हैं।
- बौद्धिक संपदा और नवाचार
- बौद्धिक संपदा और जलवायु परिवर्तन
- अनुच्छेद 27.3(बी) की समीक्षा, तथा ट्रिप्स समझौते और जैव विविधता तथा पारम्परिक ज्ञान व लोकज्ञान के रक्षण समझौते के बीच सम्बन्ध।
- एलडीसीज (न्यूनतम विकसित देश) द्वारा ट्रिप्स समझौते का क्रियान्वयन तथा उनके लिए अंतरण अवधि का विस्तार।
- ट्रिप्स समझौते के तहत अनुल्लंघन और स्थिति शिकायतों पर अधिस्थगन का विस्तार।
- तम्बाकू उत्पादों के लिए सादी पैकेजिंग आवश्यकताएं।

(iii) एलडीसीज (न्यूनतम विकसित देश) को ड्यूटी मुक्त और कोटा–मुक्त बाजार पहुंच देने के बारे में आरआईएस मुद्दे के कई आयामों का परीक्षण कर रहा हैः

- इस मुद्दे पर हांगकांग मंत्रिमंडलीय (2005) से बाली मंत्रिमंडलीय (2013) की बहस का विश्लेषण।
- एलडीसीज की बाजार पहुंच पर भारत की ड्यूटी मुक्त व्यापार पसंद योजना के प्रभाव का परीक्षण।
- अपनी कुल 2014 टैरिफ लाइनों के 97ः तक लाइनों तक की कवरेज बढ़ाने के भारत के फैसलों के निहितार्थों का परीक्षण।

- डीएफक्यूएफ योजना के बारे में कुछ विकासशील देशों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा, विशेषतः चीन, ब्राजील और रूस जैसे देशों की।
- सभी विकासशील देशों की डीएफक्यूएफ नीतियों के निहितार्थों का अनुभवपरक परीक्षण, विशेषतः उन देशों का जिनका वैश्विक निर्यात 200 अरब डालर प्रति वर्ष से अधिक हैं।

यदि विकसित और विकासशील देश अपनी उत्पाद लाइनों के 97 प्रतिशत तक एलडीसीज को बाजार पहुंच देने के समझौते तक पहुंच जाते हैं तो वैश्विक व्यापार का ढंग अलग होगा।

जी–20 प्रस्तावः जी–20 के अंतर्गत व्यापार और निवेश के मुद्दे

प्रो. सचिन चतुर्वेदी / प्रो. राम उपेंद्र दास

व्यापार और निवेश अपने आप में एक लक्ष्य नहीं बल्कि रोज़गार सृजन, ग़रीबी उन्मूलन आदि जैसे विकास के लक्ष्य प्राप्त करने के महत्त्वपूर्ण उपकरण हैं। व्यापार और निवेश प्रवाह वैश्वीकरण और राष्ट्रों तथा क्षेत्रों के बीच बढ़ी हुई पारस्परिक अन्तर्निर्भरता के युग में बहुत महत्त्वपूर्ण हो गए हैं। इन प्रवाहों की प्रकृति और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय नीति व्यवस्थाओं और संस्थानों ने, जो इस तरह के प्रवाहों का नियंत्रण करते हैं, जबर्दस्त अभिशासन अंतराल को रेखांकित किया है। इसके महत्त्वपूर्ण वैश्विक निहितार्थ हैं और वे उच्चस्तरीय नीति तवज्जह की मांग करते हैं। चूंकि व्यापार और निवेश के प्रगति और विकास संबधी महत्त्वपूर्ण निहितार्थ हैं इसलिए इन पर उच्चस्तरीय वैश्विक ध्यान सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि राष्ट्र स्तरीय सफल परिणामों द्वारा समेकित वैश्विक आर्थिक निश्पादन को सुनिश्चित किया जा सके। ऐसा हो सके इसके लिए कुछ कार्य बिन्दुओं का निश्चय करके उन्हें जी–20 नेताओं के सामने रखना होगा।

गैट और सेवओं में व्यापार समझौता (टीआईएसए)

प्रो. राम उपेंद्र दास

संयुक्त राज्य अमेरिका और आस्ट्रेलिया द्वारा शुरू किए गए सेवाओं में व्यापार समझौते (टीआईएसए) पर इस समय डब्ल्यूटीओ में 50 भागीदारों के साथ वार्ता चल रही है ये देश सेवाओं में दुनिया के कुल व्यापार के 70 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। सितंबर 2013 तक टीआईएसए के भागीदारों में आस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली, चीनी ताईपेई (ताइवान), कोलंबिया, कोस्टारिका, यूरोपीय संघ, हांगकांग, आइसलैंड, इस्राईल, जापान, लीख्टेंस्टाइन, मेक्सिको, न्यूज़ीलैंड, नार्वे, पाकिस्तान, पनामा, पेराग्वे, पेरू, रिपब्लिक ऑफ़ कोरिया, तुर्की, और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। यह बहुपक्षीय समझौता है सेवाओं में व्यापार का विस्तार जिसका उद्देश्य है। भारत अभी तक इसका अंग नहीं रहा है।

यह अध्ययन भारत पर इस निहितार्थों पड़ने वाले असर पर भी कार्य कर रहा है। यह इस तथ्य की जांच कर रहा है कि क्या भारत के बहुपक्षीय व्यवस्था के साथ जुड़ने से यह बहुपक्षीय प्रणाली कमज़ोर होगी। आईटी, श्रव्य–दृश्य सेवाओं आदि सहित सेवा व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों में भारत के निर्यात हितों को सुनिश्चित करने की सबसे अच्छी रणनीति क्या हो सकती है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि समझौते का सबसे अच्छा रास्ता क्या होगा जो भारत को प्राकृतिक व्यक्तियों के अस्थाई प्रवास की प्रणाली मोड–IV के अंतर्गत अधिक और प्रभावी लोच प्रदान करेगा।

उत्तर-2015 वैष्विक विकास कार्यसूची

प्रो. सचिन चतुर्वेदी/डॉ रवि के. श्रीनिवास/प्रो. टी सी जेम्स/डॉ सब्यसाची साहा/श्री अमित कुमार/श्री प्रत्यूश

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सितंबर 2015 में संवहनीय विकास की 2030 की कार्यसूची का अनुमोदन किया जिसमें कार्यान्वयन के साधन (एमओआई) और 2030 तक के फ़ालोअप और पुनरीक्षण के साथ–साथ संवहनीय विकास लक्ष्य (एसडीजी) शामिल हैं। एसडीजी 17 उद्देश्यों और 169 लक्ष्यों का एक सेट हैं जिसमें विकास के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणी आयाम शामिल हैं। संकल्पनात्मक और प्रचालनात्मक स्तर पर एसडीजी महज़ आठ एमडीजी (सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों) के विस्तार भले न हों लेकिन उन्हें विकास की मुख्य रुकावटों को दूर करने के लिए विश्व भर की व्यवस्थाओं में सुधार लाने और संवहनीय विकास के लिए एक समावेशी अंतरराष्ट्रीय परिवेश हासिल करने के लिए तैयार किया गया है।

आरआईएस भारत में यूएन के समर्थन से इस कार्य सूची में निहित प्रासंगिक लक्ष्यों को भारत में लागू करने के लिए जल्दी ही एक मार्ग मानचित्र तैयार करने के लिए भारत में विधि निर्माताओं, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, निजी क्षेत्र और समाजिक संगठनों के साथ परामर्शों के एक कार्यक्रम की अगुआई कर रहा है। यह मुहिम आरआईएस के भारतीय विकास सहयोग मंच (एफआईडीसी) के अंतर्गत चलाई जा रही है। अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण पर वैशिविक शासन को प्रभावित करने में भारत की स्थिति और उसकी भूमिका का पता लगाना भी इस प्रक्रिया का उद्देश्य है। यह कार्यक्रम यूएन की प्रमुख बैठकों में सहायक आयोजनों के रूप में अपने दक्षिणी भागीदारों के साथ व्यापकतर परामर्श की भी कल्पना करता है। आरआईएस सभी 17 एसडीजी और भारत के संदर्भ में परस्पर संबंधित विषयों पर स्थिति प्रपत्र भी लाएगा।

वैष्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत-आसियान क्षेत्रकीय सहयोग

प्रो. एस के मोहंती

यह अध्ययन विशेष रूप से उत्पादन क्षेत्रों में भारत की एकीकरण प्रक्रिया पर काम कर रहा है, विशेषतः शुरुआती तौर पर विनिर्माण में, मसलन मशीनरी, विद्युतीय और ऑप्टिकल उत्पादों और वाहन क्षेत्र, पुरजों और उपांगों सहित। इन क्षेत्रों पर विशेश ध्यान सिर्फ़ इसलिए ही नहीं है कि वे भारत और आसियान के बीच प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र हैं, बल्कि इसलिए भी कि ये अन्य क्षेत्रों के अलावा उन थोड़े से महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में से हैं जिनमें एफटीए के फलस्वरूप आईपीएन निर्माण प्रक्रिया लघु और मध्यम उद्योगों (एसएमई) पर भरपूर प्रभाव डालती है। यह अध्ययन उन उद्योगों में, जिनमें भारत के पास विनिर्माण क्षमताएं और पूरकताएं हैं जो आसियान और भारत की मांग और आपूर्ति क्षमता से मेल खाती हैं और सीमा के आर–पार संजालों (नेटवर्कों) के निर्माण की संभावनाओं का पता लगाता है। इसके अतिरिक्त यह अध्ययन उत्पादन संजालों के विकास की चुनौतियों की भी पहचान कर रहा है। यह अध्ययन विशेष रूप से आसियान और भारत के बीच उत्पादन संजालों को प्रोत्साहन देने में संयोजकता और व्यापार सुगमीकरण के अंतरालों की पहचान कर रहा है और संभावित समाधान भी सुझा सके।

दक्षिण–दक्षिण सहयोगः भारत–अफ्रीका विकास सहयोग

प्रो. सचिन चतुर्वेदी/प्रो. एसके मोहंती/प्रो. टी सी जेम्स/श्री अमित कुमार

डीपीए के सहयोग से आरआईएस–एफआईडीसी अफ्रीका में भारत के विकास सहयोग की कुछ सफल कहानियों पर एक अध्ययन करेगा। यह अध्ययन 2015 में दिल्ली में होने वाले तीसरे भारत–अफ्रीका फ़ोरम शिखर सम्मेलन की कार्यसूची के लिए इनपुट प्रदान करेगा। अध्ययन इस क्षेत्र में भारत द्वारा सफलतापूर्वक कार्यान्वित ज़मीनी क्षमता–निर्माण परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा जो विकासशील देशों में भारत के विकास सहयोग कार्यक्रमों की रूपान्तरकारी प्रकृति का प्रभावी ढंग से निरूपण करती हैं।

दक्षिणी भागीदारियों की प्रवृत्तियों पर वैष्विक डेटाबेस

प्रो. सचिन चतुर्वेदी/प्रो मिलिंदों चक्रवर्ती/श्री सुशील कुमार/श्री प्रत्यूश/सुश्री श्रुति शर्मा

दक्षिण से विकास सहयोग संबंधी सूचनाओं के संकलन, संग्रह, प्रसंस्करण, विश्लेषण और प्रकीर्णन का साझा मंच निश्चित रूप से संभव है, लेकिन शर्तों के साथ। एसएससी न तो एक सर्वसमावेशी संकल्पना है और न ही इसके कार्यकलाप सख़्त है। दक्षिणी देश कोई एक विकास पहल करते हैं जो एसएससी के व्यापक दायरे में आती है, और वह एक देश से दूसरे देश में उनकी ज़रूरतों, सहयोग के मौजूदा क्षेत्रों के अनुसार बदलती है। सभी दक्षिणी देश समान प्रकृति के दक्षिण–दक्षिण सहयोग (एसएससी) में संलग्न नहीं हैं और प्रत्येक दक्षिणी देश विकास सहयोग संबंधी सूचनाओं के संग्रह और विश्लेषण की अपनी व्यवस्था बना सकता है। इस तरह, कोई मानक एसएससी सांख्यिकीय प्रबंधन प्रणाली नहीं हो सकती जो सभी दक्षिणी देशों को समाहित कर सके। इधर विगत में दक्षिणी भागीदारियों में काफ़ी वृद्धि हुई है। लेकिन ऐसी कोई एक जगह नहीं है जहां ब्योरे जुटाए और व्यवस्थित विश्लेषित किए जाते हों। साक्ष्य–आधारित विश्लेषण नीति और रणनीति विकास के लिए शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है और उनका लाभ ज्यादा ध्यान देकर उठाया जाना चाहिए। फिलहाल, व्यापार, एफडीआई, जैसे कुछ क्षेत्रों में अच्छे डेटा सेट उपलब्ध हैं लेकिन वे सेवाओं और विकास सहयोग में सीमित हैं या कमज़ोर आर्थिक संस्थाओं वाले देशों में। एसएससी की संवृद्धि और प्रभाव के समर्थन के लिए, समर्थन संस्थानों के विकास पर विशेष तवज्जह देते हुए, एक मांग–प्रेरित और संगठित डेटा संग्रह और सूचना विश्लेषण प्रणाली की आवश्यकता है। डेटा संकलन और संग्रह की यह चुनौती प्रमाण आधारित विश्लेषण की संभावना को सीमित करती है। एसएससी के लिए शोध आधार का निर्माण और साथ ही शोध के लिए समर्पित एसएससी कोश का सृजन एसएससी की क्षमता को अधिकतम सीमा तक ले जाने में काफ़ी सहायक हो सकता है।

विकासशील देशों में निर्यात का परिष्करणः उभरती प्रवृतियां और चुनौतियांः

प्रो. प्रवीर डे/सुश्री श्रेया पान

इस अध्ययन में हमारे दो प्रमुख लक्ष्य हैं। यह हम निर्यात परिष्करण को मापता हैं और दूसरा, निर्यात परिष्करण के प्रमुख निर्धारकों को समझने के प्रयास करता हैं। इस अध्ययन के नतीज़े बताएंगे कि विकासशील देश निर्यात परिष्करण में विकसित

देशों के मुकाबले कहां खड़े हैं। यह विकासशील देशों को अपनी निर्यात टोकरी का उन्नयन करने के लिए नीतिगत दिशानिर्देश भी प्रदान करता है।

ख. व्यापार और निवेश पर क्षेत्रीय पहलें

वैश्वीकृत होते मध्य एशिया के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के सबक़

प्रो. राम उपेंद्र दास

एशिया–प्रशांत में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण की परिधि के भीतर मध्य एशियाई क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण स्थान है। यही नहीं, यह क्षेत्र ऐतिहासिक रेशम मार्ग का नियंत्रक रहा है। इसकी भौगोलिक स्थिति पूर्वी, दक्षिण–पूर्वी, दक्षिणी–उत्तरी और पश्चिमी एशिया के एकीकरण की आर्थिक कुठाली है। संक्षेप में, मध्य एशिया वैश्विक एकीकरण का नया केंद्र है, ख़ास कर तब जबकि आर्थिक गुरुत्व केंद्र खिसक कर एशिया में आ गया है। जहां मध्य एशियाई देश प्रचुर प्राकृतिक, खनिज और मानव संसाधनों से संपन्न हैं, और बड़ी आर्थिक संभावनाएं अपना लाभ उठाए जाने की प्रतीक्षा कर रही है, वहीं पुराने आर्थिक प्रतिमानों से उनका संक्रमण अभी पूर्णता से कोसों दूर है। इसके अलावा, क्षेत्रीय एकीकरण की आर्थिकी के उनके अनुभव सापेक्षतः कम हैं। इस पृष्ठभूमि में यह परचा मध्य एशियाई आर्थिक विकास के आकार–प्रकार का विश्लेषण करता है और क्षेत्र के सामने खड़ी कुछ चुनौतियों को रेखांकित करता है। इस संदर्भ में भारत की आर्थिक प्रगति और विकास से कुछ निश्कर्ष निकालने के भी प्रयास किए गए हैं। यह मध्य एशियाई क्षेत्र के वैश्वीकरण की तलाश में उसकी पूरी क्षमता के उपयोग के लिए भविष्य में भारत–और मध्य एशिया के बीच के आर्थिक सहयोग के कुछ पहलुओं की भी चर्चा करता है।

एक रणनीतिक क्षेत्र के रूप में 'ब्लू इकोनॉमी' का उदयः अवसर और चुनौतियां

प्रो. एस के मोहंती/डॉ प्रियदर्शी दास/सुश्री आस्था गुप्ता

समुद्री संसाधनों की बढ़ती मांग के मद्देनजर विश्व का ध्यान ब्लू इकोनॉमी की ओर तेजी से अग्रसर हुआ है। ब्लू इकोनॉमी उत्पादन और मानव उपभोग के लिए समुद्री संसाधनों की आवर्धित मांग और पर्यावरणीय क्षति के बीच विद्यमान दुविधा की जटिलता के मद्देनज़र मानवता के कल्याण के लिए समुद्री संसाधनों के टिकाऊ और कुशल दोहन की संभावना तलाश करती है। यह समावेशी विकास की रणनीति के साथ समुद्री संसाधनों के संवहनीय उपयोग पर ध्यान केंद्रित करती है।

ब्लू इकोनॉमी के दृष्टिकोण का महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि ग़रीबी कम करने और समाजिक–आर्थिक अरक्षितता के उन्मूलन में उसका योगदान है। सागर प्राकृतिक संसाधनों के समृद्ध कोषागार हैं जिनका उसकी जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से पुनर्चक्रण और पुनर्भंडारण किया जा सकता है। दरअसल, सागर सागरी संसाधनों के अति उपयोग के जोखिमों को सोख सकते हैं बशर्ते उपयुक्त संरक्षण और अनुकूलन उपाय अपनाए जाएं। ब्लू इकोनॉमी का दायरा बढ़ा कर ग़रीब और अरक्षित लोगों के आर्थिक दृष्टि से ऊपर उठने की अवसरहीनता को पीढ़ी दर पीढ़ी कम किया जा सकता है।

जहां ब्लू इकोनॅमी को संवहनीय विकास का महत्त्वपूर्ण घटक माना जाता है वहीं अलग मुहिम के रूप में इसे लोकप्रिय बना कर वैश्विक अर्थव्यवस्था को समुद्री और तटवर्ती संसाधनों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सकता है और संसाधन–सघन भूरे विकास भूरे का आशय खनिजों से है मॉडल की ख़ामियों को रेखांकित किया जा सकता है जिसका रुझान स्वाभाविक रूप से संसाधनों के दोहन की तरफ़ होता है और जो पुनर्संग्रह और समुद्री संसाधनों की लोच पर आनुपातिक रूप से कम ध्यान देता है। राष्ट्रीय विकास नीति को ब्लू इकोनॅमी की विशेषताओं के अनुकूल ढाल कर अर्थव्यवस्था–पारिस्थितिकी की अंतःक्रिया और टकरावों को स्पष्ट किया जा सकता है और उच्च समावेशी प्रगति और संवहनीय विकास दोनों लक्ष्यों का समन्वय तैयार करने की उपयुक्त व्यवस्था विकसित की जा सकती है।

ब्लू इकोनॅमी कई क्षेत्रों में फैल रही है। इस क्षेत्र के लिए नई रणनीति विकसित करने के लिए ब्लू इकोनॅमी का प्रतिचित्रण और शेष अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन महत्त्वपूर्ण है। आरआईएस अपने व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान आकर्षित करेगाः (i) जीवित संसाधनः फ़िशिंग, एक्वाकल्चर, सीफ़ूड प्रॉसेसिंग, समुद्री घास, शैवाल, जलीय पौधे, मत्स अंड उत्पत्तिशालाएं, इत्यादि; परिवहन (ii) गहरे सागर के माल परिवहन, अंतर्देशीय जल परिवहन, समुद्री यात्री परिवहन, तटीय और विशाल झीलों में यात्री परिवहन, समुद्री माल गोदाम और भंडारण, जल परिवहन के लिए अन्य समर्थक कार्य–कलाप, इत्यादि; (iii) जल आधारित पर्यटन और मनोरंजन समुद्र विश्रामः दर्शनीय और दर्शनीय स्थल देखने के लिए परिवहन, मनोरंजन सामग्री को भाड़े पर देना, खेल और मनोरंजन निर्देश, नाव विक्रेता, पूर्ण सेवा रेस्तरां, होटल, मोटल और लॉज़िंग की जगहें, मेरिना, मनोरंजक वाहन पार्क और कैंप साइटें, सुरम्य जलीय यात्राएं, इत्यादि; (iv) समुद्री औद्योगिक गतिविधियोंः जहाज़ और नौका निर्माण, तलाश और नौकायन उपकरण, नौकाचालन जाल का उत्पादन, मेरीन स्पोर्टिंग गुड्स, इत्यादि (v) ऊर्जाः समुद्री अक्षय ऊर्जा, पवन, लहर, ज्वार, तापीय रूपांतरण, बायोमॉस, इत्यादि (vi) हाइड्रोकार्बन की खोजः प्रतितट तेल और गैस की खोज; पाइप लाइन और संबंधित संरचनाओं का निर्माण इत्यादि (vii) शिक्षाः समुद्र विज्ञान और प्रशिक्षण, ख़ास तौर से समुद्री अभियांत्रिकी, जैव सूचना तंत्र, परामर्श, जल सर्वेक्षण इत्यादि (viii) समुद्र तल में खनिजों की खोजः कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्खन्न, बहुधात्वीय पिंड, कोबाल्ट पटल, सल्फ़ाइड, यिट्रियम, डिस्प्रोसियम और टर्बियम, औद्योगिक और खनन, भौतिकीय जांच और मानचित्रण सेवाएं, इत्यादि; (ix) बंदरगाह संबंधी कार्य–कलापः तल कर्षण, रो रो रो पैक्स, लो लो, जहाज़ रंगाई, बंदरगाह और पत्तन के कामकाज, समुद्री माल का प्रबंधन, पोत और नौका की मरम्मत इत्यादि (x) समुद्री सेवाएंः उच्च तकनीक की समुद्री सेवाएं, समुद्री वित्तीय सेवाएं, समुद्री बीमा और समुद्री कानूनी सेवाएं, समुद्र संबंधी शोध और परिवर्धन, आमोद–प्रमोद और मनोरंजन सेवाएं, नौकायन के लिए नौकाचालन, इत्यादि (xi) और समुद्री निर्माण और अभियांत्रिकी भारी निर्माणःमेरीन, पुल और टनेल मेरीन इत्यादि।

आईओआरए क्षेत्र में मात्स्यकी के आर्थिक पहलू

प्रो. एसके मोहंती / डॉ प्रियदर्शी दास

पिछले दशक के दौरान आईओआरए अफ्रीकी–एशियाई क्षेत्र में जीवंत क्षेत्रीय समूह बन कर उभरा है। हालांकि क्षेत्र का अंतर–क्षेत्रीय व्यापार (आईआरटी) वर्ष 2013 में 29.2 प्रतिशत दर्ज किया गया लेकिन उस क्षेत्र में पांच कस्टम्स यूनियनों की उपस्थिति के कारण उसे 'खुला क्षेत्रवाद' अपनाना होगा। यह आईओआरए में एफटीए (मुक्त व्यापार क्षेत्र) की संभावना को सीमित करता है। एक वैकल्पिक नीतिगत रणनीति के रूप में, क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रकीय स्तर पर संकेन्द्रित किया जा सकता है। अतीत में इस क्षेत्र के दूरदृष्टाओं ने मात्स्यकी क्षेत्रक की क्षेत्रीय सहयोग के प्राथमिक क्षेत्र के रूप में पहचान की है। सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था में मात्स्यकी क्षेत्रक का योगदान कई मायनों में महत्त्वपूर्ण रहा है, ख़ास कर भोजन, पोषण, रोज़गार सृजन, और विदेशी मुद्रा कमाने में। मात्सयकी क्षेत्रक पर आरआईएस के काम का वर्तमान कार्यक्रम इस क्षेत्रक के आर्थिक आयाम पर ध्यान आकर्शित करता है। वर्तमान अध्ययन मात्स्यकी क्षेत्रक की आजीविका सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, उत्पादन ढांचे, व्यापार के आयाम और क्षेत्रीय मंच को आगे ले जाने के लिए आईओआइए में क्षेत्रीय संस्थानिक यांत्रिकी की वहनीयता जैसे क्षेत्रकीय समस्याओं की पड़ताल करता है। कई और आर्थिक मुद्दे भी हैं जो विस्तृत शोध की मांग करते हैं जैसे मछली की कीमतों में अस्थिरता, इस क्षेत्र को रिआयत देने संबंधी मुद्दे (हालांकि इनकी चर्चा डब्लूटीओ में की जाती है), एनटीबी के मुद्दे, मात्स्यकी में क्षेत्रीय मानक पर चर्चा, खाद्य संसाधन, इत्यादि। मात्स्यकी पर आरआईएस के काम का भावी कार्यक्रम अधिक विश्लेषण के लिए इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

अफ्रीका में मुक्त व्यापार क्षेत्रों (एफटीए) के एकीकरण के संदर्भ में भारत–अफ्रीका आर्थिक सहयोग

प्रो. एस के मोहंती

पिछले दो दशक में अफ्रीका के साथ भारत का व्यापक आर्थिक सहयोग काफ़ी बढ़ा है। हालांकि भारत अफ्रीका से शुद्ध रूप से आयात करता है लेकिन कई देशों में उसकी निर्यात उपस्थिति महत्त्वपूर्ण है। अफ्रीका भारत के लिए भारत में आने वाले एफडीआई का प्रमुख स्रोत रहा है। भारत और सीओएमईएसए के साथ चल रही समझौता वार्ताओं से इस वर्ष कुछ सकारात्मक निश्कर्ष की अपेक्षा है। लेकिन सीओएमईएसए, एसएडीसी और एफएसी के एक अकेले बाज़ार के रूप में समेकन के साथ अफ्रीका में मेगा–आरटीए का उभरना महत्त्वपूर्ण आयाम रहा है जो भारत के लिए एकबड़ी उपलब्धि हो सकता है। आरआईएस में इस तरह की व्यवस्था के आर्थिक प्रभाव की छान–बीन चल रही है।

भारत के एफटीए/सीईसीए: प्रभाव और भविष्य की दिशाएं

प्रो. राम उप्रेंद दास

इस मौजूदा भाव के मद्देनज़र कि भारत के एफटीए के प्रभाव दूर दूर तक सकारात्मक नहीं रहे हैं, इस अध्ययन का लक्ष्य विभिन्न संबंधित पहलुओं का मूल्यांकन करना है।

सिल्क रोड–'एक परिधी और एक सड़क' (ओबीओआर) पहल

प्रो. एस के मोहंती

राष्ट्रपति शी जिनपिंग का प्रशांत और हिंद महासागर तक को समेटने वाले नये समुद्री रेशम मार्ग के साथ 'एक परिधी एक सड़क' (ओबीओआर) का प्रस्ताव चीन की ओर से अब तक प्रस्तावित सबसे महत्त्वपूर्ण और दूरगामी प्रस्ताव हैः प्रशांत महासागर से बाल्टिक सागर तक फैली ट्रांस–यूरेशियाई परियोजना। चीन द्वारा प्रस्तावित रेशम सड़क एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना है जो लगभग पूरे यूरेशियाई भू–भाग को समेट लेगी। उत्तरी सड़क ज़मीन पर बनी सड़क होगी और मुख्य रूप से उत्तर भारत से गुज़रेगी। दक्षिणी सड़क समुद्री मार्ग है और भारत को स्पर्श करेगा।

यह परियोजना मूलतः दो आर्थिक मुद्दे उठाती है। पहला मुद्दा है सड़क की सारी आनुषंगिक सुविधाओं के साथ उसकी स्थापना के लिए संगठन। दूसरा महत्त्वपूर्ण मुद्दा है व्यापार पर परियोजना का क्या प्रभाव होगा। प्रस्तावित पहलों ने भारत में मिली–जुली प्रतिक्रिया उत्पन्न की है। एक है परियोजना के संभावित भौगोलिक–राजनीतिक निहितार्थों को लेकर आशंका और दूसरा अच्छे अवसर से वंचित होना।

इस पृष्ठभूमि में, इस समय आरआईएस विश्लेषण कर रहा है कि भारत के लिए इस परियोजना के निहितार्थ क्या हैं, और इसीलिए आरआईएस एक सुविचारित समाधान तैयार करेगा। ओबीओआर के दायरे में आने वाले क्षेत्र में भारत के आर्थिक संबंध का बड़ा हिस्सा समाहित है; यह क्षेत्र भारत के लिए सामरिक दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है और ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध रहे हैं। प्रश्न हैं कि क्या यह परियोजना भारत के मुकाबले चीन के हितों के अधिक अनुकूल है और इसका प्रारूप और ढाँचा भारत के हितों के अनुकूल कैसे बनाए जा सकते हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तीन 'एक साथ' का प्रस्ताव रखा था, पहला परियोजनाओं की पहचान करना, और दूसरा, साझा हितों के आधार पर परियोजनाओं को लागू करना ताकि तीसरा, इस सारे प्रयास के लाभों की भागीदारी की जा सके और उनका आनंद लिया जा सके। परियोजना को समावेशी बनाने का प्रस्ताव भारत के लिए कार्यान्वयन को प्रभावित करने का ढांचा प्रदान करता है। भारत की भागीदारी को ठोस बनाने के लिए परियोजना के विश्लेषण का काम चल रहा है।

ईएईयू और भारत के बीच मुक्त व्यापार अनुबंध (एफटीए) का संयुक्त वहनीयता अध्ययन

प्रो. राम उपेंद्र दास/सुश्री हरप्रीत कौर

एक ओर भारत और दूसरी ओर आर्मेनिया, बेलारूस, कज़ाकिस्तान, किरगिज़िस्तान के आर्थिक संघ और रूसी महासंघ (ईएईयू) की संभावित संपूरकता को स्वीकार करते हुए एक संयुक्त अध्ययन समूह की स्थापना की गई है जो इस आर्थिक संघ के साथ भारत के आर्थिक सहयोग अनुबंधों के लिए दृष्टिकोण और प्रक्रिया का सुझाव देगा। भारत की हालिया आर्थिक गतिशीलता और इस समूह के आर्थिक निष्पादन को देखते हुए यह अनिवार्य जान पड़ता है कि माल के व्यापार, सेवा व्यापार और निवेश के साथ–साथ आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में उनके साथ व्यापक रूप से जुड़ा जाए। इस अध्ययन की ज़रूरत इस तथ्य से पैदा होती है

कि अतीत में इस क्षेत्र के अब से ज्यादा मज़बूत आर्थिक जुड़ाव रहे हैं और ऊर्जा सुरक्षा की अनिवार्यता के लिए भी इस जुड़ाव को मज़बूत किया जा सकता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जेएसजी में शामिल होने और अध्ययन करने के लिए आरआईएस को आमंत्रित किया है।

ग. क्षेत्रीय सहयोग, व्यापार सुगमीकरण और संयोजकता

आर्थिक गलियारों के प्रभावों का आकलन

प्रो. प्रवीर डे/श्री मनमीत सिंह अजनामी

यह अध्ययन उप–राष्ट्रीय डाटा के साथ एक आर्थिक भूगोल का मॉडल विकसित करता है और संवृद्धि के संदर्भों में भारतीय राज्यों के विशेष संदर्भ के साथ भारत में आर्थिक गलियारों के आर्थिक (परिवहन) प्रभावों का आकलन करता है। पूर्व के पड़ोसियों के साथ भारत को जोड़ने वाले चार महत्त्वपूर्ण गलियारे चुने गए हैं जिनके नाम हैंः (i) बांगलादेश चीन भारत और म्यांमार (बीसीआईएम)–आर्थिक गलियारा, (ii) पूर्व–पश्चिम गलियारा (स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का अंग), (iii) ट्राईलेटरल हाइवे, और (iv) कलादान मल्टीमोडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट परियोजना।

म्यामार में विकास गलियारे

राजदूत वी एस शेषाद्रि/प्रो. प्रबीर डे

'संयोजकता गलियारों का विकास गलियारों में रूपांतरण' पर सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी गई थी। 12 अगस्त 2014 को आयोजित एक कार्यक्रम में विदेश मंत्रालय में सचिव सुश्री सुजाता मेहता ने इसका लोकार्पण किया था। उसके बाद यह रिपोर्ट पूर्वोत्तर भारत में गुवाहाटी और शिलांग सहित कई समारोहों में प्रस्तुत की गई। आईएलएफ ऐंड एस के साथ एक फॉलोअप अध्ययन का प्रस्ताव सरकार को सौंपा गया है।

भारत–म्यांमार सीमा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की नीति और कार्यान्वयन कदम

प्रो. राम उपेंद्र दास/सुश्री नित्या बत्रा

उत्तर–पूर्व क्षेत्र की सीमा का लगभग 98 प्रतिशत हिस्सा भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है। उत्तर में उसकी सीमाएं चीन के साथ, दक्षिण–पूर्व में बांगलादेश के साथ, उत्तर–पश्चिम में भूटान के साथ, और पूर्व में म्यांमार के साथ लगती हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र का स्थितिजन्य लाभ और समृद्ध प्राकृतिक संसाधन न केवल आसियान, यानी असोसिएशन ऑफ़ साउथईस्ट एशियन नेशन्स (एएसईएएन), के साथ बल्कि बांगलादेश, भूटान और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों के साथ सहयोग के आधार के रूप में इसके विकास की पृष्ठभूमि प्रदान करता हैं। इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह कि म्यांमार के रास्ते 'पूर्व की ओर देखें' और 'पूर्व में काम करें'

की भारत की नीति के अंग के रूप में कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम जैसे आसियान के अनेक देशों के साथ क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को संभव बनाया जा सकता है। भारत के साथ सीमा व्यापार पर, जो म्यांमार की अर्थ व्यवस्था का मुख्य आधार है, ध्यान देते हुए भारत को न केवल म्यांमार के साथ एकीकृत करने बल्कि भारत–सीएलएमवी सहयोग की व्यापक रणनीति के अंग के रूप में एक शुरुआत की जा सकती है। इन संभावनाओं का लाभ उठाने और नीतिगत व्यवस्थाएं विकसित करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने आरआईएस से इस विषय पर अध्ययन करने का अनुरोध किया है।

बीसीआईएम–आर्थिक गलियारे की वहनीयता

प्रो. प्रबीर डे/सुश्री श्रेया पान

यह अध्ययन विदेश मंत्रालय के पूर्वी एशिया प्रभाग के लिए जेएसजी रिपोर्ट तैयार करने और बांगलादेश, चीन, भारत और म्यांमार आर्थिक गलियारे (बीसीआईएन–ईसी) की परियोजना के लिए शोध में उनकी सहायता करने के लिए किया जा रहा है। इस परियोजना के अंग के रूप में हमने तीन प्रमुख अध्याय लिखे हैं जिनके नाम हैं संयोजकता, व्यापार और व्यापार सुगमीकरण, और निवेश तथा वित्त, और जेएसजी के तीन और अध्यायों के लिए महत्त्वपूर्ण शोध सामग्रियां प्रदान की हैं। पहला मसौदा जनवरी 2015 में मंत्रालय को सौंपा दिया गया है। सम्प्रति, अध्यायों का संशोधन चल रहा है।

आसियान–भारत व्यापार में सीमाशुल्क विहीन कदम (एनटीएम)

प्रो. प्रबीर डे

यह अध्ययन आसियान में भारत द्वारा और भारत में आसियान द्वारा सामना किए जाने वाले एनटीएम का विश्लेषण करता है। 16 वर्गीकृत एनटीएमों में से इस अध्ययन ने एसपीएस और टीबीटी पर विचार किया है। यह अध्ययन प्राथमिक और द्वितीयक दोनों तरह के आंकड़ों पर आधारित है। और यह अध्ययन जारी है।

भारत और आसियान के बीच उभरते उत्पादन संजाल

प्रो. प्रबीर डे/डॉ. दुरईराज कुमार स्वामी/श्री सुनंदो बासू

यह अध्ययन भारत और आसियान देशों के बीच उभरते उत्पादन संजाल परिदृष्य की पड़ताल करता है, ख़ास तौर से मशीनरी, विद्युतीय और आप्टिकल उत्पादों और वाहन क्षेत्र जैसे विनिर्माण के क्षेत्रों में। यह अध्ययन उत्पादन संजालों के निर्माण की चुनौतियों की पहचान करने के भी प्रयास करता है। यह अध्ययन विशेष रूप से भारत और आसियान के बीच उत्पादन संजालों को प्रोत्साहन देने में संयोजकता और व्यापार सुगमीकरण के बीच के अंतराल की पहचान करता और संभावित समाधान उपलब्ध कराता है।

आसियान–भारत हवाई संयोजकता का अध्ययन

प्रो. प्रबीर डे/डॉ. दुरईराज कुमार स्वामी/श्री सुनंदो बासू

आसियान–भारत व्यापार (विशेष रूप से सेवा व्यापार) को सुगम बनाने के लिए आसियान–भारत के बीच अधिक मज़बूत हवाई संयोजकता महत्त्वपूर्ण है। इस अध्ययन के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य आसियान के देशों और भारत के बीच हवाई संयोजकता को मज़बूत करने की रणनीति तैयार करना है, विशेष रूप से भारत के श्रेणी II और श्रेणी III के शहरों के साथ। अध्ययन का मसविदा तैयार कर लिया गया है और रिपोर्ट को अंतिम रूप हितधारकों के साथ विचार–विमर्श के बाद दिया जाएगा।

भारत–मंगोलिया आर्थिक संबंध

प्रो. प्रबीर डे/सुश्री श्रेया पान

यह अध्ययन मंगोलिया स्थित भारतीय दूतावास के अनुरोध पर चलाया जा रहा है। संयोजकता पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए भारत और मंगोलिया के बीच के आर्थिक संबंधों का अध्ययन करना इसका उद्देश्य है।

पूर्व और दक्षिण–पूर्व एशिया के साथ घनिष्ठतर आर्थिक सहयोग की पड़ताल

राजदूत वी एस. शेषाद्रि

भारत और एपीईसीः एक आकलन' पर एक रिपोर्ट फ़रवरी 2015 में सरकार को सौंपी गई थी। आरआईएस फिक्की (एफआईसीसीआई) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित समारोह में सचिव (पूर्व) ने औपचारिक रूप से इस रिपोर्ट का विमोचन किया जाएगा। उसके बाद भारत और कोरिया के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी अनुबंध (सीईपीए) के एक अध्ययन पर काम शुरू किया गया है। इस समय जापान–भारत के एक सीईपीए पर भी अध्ययन जारी है। यह अध्ययन सिंगापुर और मलेशिया के साथ सीईपीए के कार्यान्वयन की भी समीक्षा करेगा।

पूर्वोत्तर भारत के बंगलादेश और म्यांमार के साथ व्यापार और निवेश में वृद्धि

प्रा. प्रवीर डे

आरआईएस के आसियान–भारत केंद्र ने सितंबर 2014 को शिलांग में आसियान–भारत संयोजकता पर पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) और इंडियन चैंबर ऑफ़ कामर्स (आईसीसी) के सहयोग से एक बड़े सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, म्यांमार और बांगलादेश के बीच सीमा पार के उत्पादन संजाल पर एक रिपोर्ट का विमोचन हुआ। मार्च 2015 में सम्मेलन का सारांश भी प्रकाशित हुआ। एआईसी इस वर्ष की दूसरी छमाही में पूर्व में काम करें की नीति और पूर्वोत्तर भारत पर एक सम्मेलन के आयोजन की योजना बना रहा है।

आरआईएस की दक्षिण एशिया विकास और सहयोग रिपोर्ट 2015

आरआईएस शोध टीम

दक्षिण एशियाई आर्थिक समेकन को अभी तक जिस नज़रिये से देखा जाता रहा है, दक्षिण एशिया विकास और सहयोग रिपोर्ट 2015 उसे उससे अलग दृष्टिकोण से देखती है। यह रिपोर्ट विचारों और दृष्टिकोणों का आर्थिक शिखर सम्मेलन है। यह क्षेत्रीय समृद्धि से शांति के 'प्रतिलोम कार्यकारण संबंध' का सिद्धांत प्रस्तुत करती

है। यह पर्याप्त वस्तुनिष्ठता और नई अंतदृश्टि के साथ अधिक संतुलित परिदृश्य प्रस्तुत करती है इसलिए अकादमीय और नीति अभिमुख अध्ययनों और उनके लिए प्रयुक्त होने वाली शोध प्रणाली के लिए बहुत उपयोगी है। यह रिपोर्ट इस तथ्य को रेखांकित करती है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र 'सबसे कम समेकित क्षेत्र' नहीं हैं। यह इस तथ्य को भी रेखांकित करती है कि दूसरे क्षेत्रीय आर्थिक समूहों की सफलताओं का महिमा मंडन और दक्षिण एशियाई आर्थिक एकीकरण में केवल ख़ामियां निकालने के रवैए को बदला जाना चाहिए। यह दक्षिण एशियाई आर्थिक एकीकरण की पहलों की सफलताओं को स्वीकारने के साथ–साथ दूसरे क्षेत्रीय समूहों की पहलों की नाकामियों से सबक़ सीखने को भी आवश्यक मानती है।

एसएडीसीआर 2015 की केंद्रीय विषय वस्तु 'शांति–निर्मात्री समृद्धि के लिए आर्थिक एकीकरण' दक्षिण एशियाई आर्थिक एकीकरण प्रक्रिया के परिणामों, क्षेत्र में शांति स्थापना के अनिवार्य तत्व और दक्षिण एशिया को समृद्ध क्षेत्र बनाने की संभावना को देखने का एक नया नज़रिया है। हालांकि शांति और समृद्ध के बीच का कार्यकारण संबंध उभयमुखी हो सकता है लेकिन यह रिपोर्ट दक्षिण एशियाई आर्थिक एकीकरण के ज़रिए समृद्धि को जो प्रकारांतर से 'शांतिकारक' है, प्रमुख लक्ष्य बनाने पर ज़ोर देती है, इस प्रयास में यह रिपोर्ट अपने दृष्टिकोण में अनूठी है और इसकी सामग्री सारगर्भित है जो दक्षेस क्षेत्र और इससे बाहर के क्षेत्रों के भी, विभिन्न हितधारकों के लिए उपयोगी हो सकती है।

सीएलएमवी के साथ आर्थिक एकीकरण के लिए भारत की रणनीति

प्रो. राम उपेंद्र दास

ऐतिहासिक दृष्टि से भारत और कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम (सीएलएमवी) क्षेत्र के बीच प्राचीन काल से ही सभ्यता, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध रहे हैं। लंबे अरसे तक भारत और सीएलएमवी देशों के बीच लोगों, माल, पूंजी और विचारों का आवागमन होता रहा है। लेकिन, इन जुड़ावों की विशेषता आज यह है कि उनकी संभावनाओं का लाभ नहीं उठाया गया। यह देखने में आया है कि सीएलएमवी क्षेत्र और शेष आसियान क्षेत्र के बीच विकास संबंधी खाई है। भारत की 'पूर्व की ओर देखें', 'पूर्व में काम करें' की नीति ने भी भारत सीएलएमवी आर्थिक एकीकरण के अर्थों में इस क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है।

कुल मिलाकर सशक्त उत्पादन संजाल और क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाएं (आरवीसी) आसियान के भीतर और उसके बाहर, दोनों जगह, उसकी विशेषताएं हैं। दूसरी ओर, भारत अपने पड़ोस की किसी भी महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला से अलग–थलग पड़ा है। क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाएं शेष आसियान की तुलना में एक हद तक सीएलएमवी क्षेत्र को भी दरकिनार कर गई हैं।

इस तथ्य के मद्देनज़र कि आरवीसी क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के महत्त्वपूर्ण वाहन के रूप में उभर कर सामने आई हैं, यथेष्ट नीतिगत अनुक्रिया द्वारा उनके सुगमीकरण की ज़रूरत है ताकि रोज़गार सृजन, ग़रीबी उन्मूलन और जीवन की गुणवत्ता सुधारने के विकास के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।

इस विषय पर प्रमुख सामग्री देकर यह रिपोर्ट सीएलएमवी क्षेत्र के साथ भारत

के आर्थिक एकीकरण का विश्लेषणात्मक और तथ्यात्मक आधार प्रस्तुत करती है, और यह संबंध व्यवसाय और विकास की जो बड़ी संभावनाएं मुहैया कराता है उन संभावनाओं को साकार करने के कुछ नीतिगत कदम भी सुझाती है।

घ. नई प्रोद्योगिकियां और विकास के मुद्दे

कृषिक्षेत्र में एलएमओस के मूल्यांकन के दिशा निर्देश और कार्यप्रणालियों का विकास

प्रो. सचिन चतुर्वेदी/प्रो. मनमोहन अग्रवाल/डॉ. रवि के. श्रीनिवास/श्री अमित कुमार/सुश्री पायल चटर्जी

जैव सुरक्षा पर यूएनईपी–जीईएफ क्षमता निर्माण चरण–II परियोजना के अंतर्गत इस परियोजना पर काम चल रहा है। लिविंग माडीफाईड आरगानीसिग (एलएमओएस) जिन्हें जैनिटिकटी मोडीफाइड आरगानीसिम (जीएमओएस) भी कहा जाता है पर मानक प्रश्नपत्र तैयार करना सामाजिक–आर्थिक मूल्यांकन के दिशा–निर्देश, उपकरण और कार्यविधियां विकसित करना और लागत लाभ विश्लेषण के लिए दिशा निर्देश और प्रश्नपत्र तैयार करना इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य है।

वैश्विक उत्तरदायी शोध और सामाजिक–वैज्ञानिक नवाचार को प्रोत्साहन

प्रो. सचिन चतुर्वेदी/डॉ. रवि के. श्री निवास/श्री अमित कुमार

प्रोगेस 2013–2016 की अवधि के लिए ईयू एफपी–7 द्वारा प्रायोजित परियोजना है। भारत के आईआरएस सहित दुनिया भर के दस परियोजना भागीदार इसमें भाग ले रहे हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षाविदों, एसएमईज़, अंतरराष्ट्रीय प्रतिशठानों, नीति सलाहकारों, शोध वित्तपोषकों, गैर सरकारी संगठनों और उद्योग को शामिल करके उत्तरदायी शोध और नवाचार (आरआरआई) पर वैश्विक तंत्र की स्थापना करना है। यह आरआरआई के वर्तमान वैश्विक तंत्र का उपयोग करने के प्रयास करेगी। इससे साथ–साथ यह परियोजना सामाजिक वांछनीयता पर नवाचारों का ध्यान केंद्रित करने के लिए वैश्विक स्तर पर सामाजिक कर्ताओं को भी जोड़ने के प्रयास करेगी। यूरोप, अमरीका, चीन, जापान, भारत, आस्ट्रेलिया और दक्षिण एशिया में विज्ञान के निधीयन की रणनीतियों और नवाचारी नीतियों की तुलना करते हुए एक प्रमुख तथ्य अन्वेशी अभियान को पूरा करना; वैश्विक स्तर पर आरआरआईज़ के लिए एक मॉडेल योरपीय प्रतिमान की वकालत करना; प्रचालक के रूप में संवैधानिक मूल्यों का प्रयोग करते हुए सामाजिक वांछनीयता को आकार देना, और वैश्विक स्तर पर क्षेत्रीय नवाचार प्रणालियों की सहक्रियता को प्रोत्साहित करने की रणनीति विकसित करना भी इस परियोजना का लक्ष्य है।

एफटीएज़, बौधिक संपदा तथा प्रस्तावित भारतीय मसौदा

प्रो. सचिन चतुर्वेदी/प्रो. टी सी जेम्स/डॉ. रवि के. श्री निवास

नये महा एफटीएज़ (क्षेत्रीय व्यापार समझौते) के उदय को देखते हुए संभावित सदस्यों के लिए आईपीआर से संबंधित मुद्दे अत्यंत महत्त्वपूर्ण होते जा रहे हैं। चूंकि भारत अपनी आईपीआर नीति के मूल ढांचे में बदलाव की पेशकश करते हुए नई नीति का मसौदा लेकर सामने आया है, इसलिए आरआईएस आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में अपने काम को और गहरा करेगा। यहां तक कि क्षेत्रकीय स्तर पर

भी आइपीआर के नए प्रावधान है, विशेष रूप से स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में। आरआईएस और दक्षिण केन्द्र (साउथ सेन्टर) ने एक साथ मिलकर काम किया है और विशष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। दक्षिण सेन्टर के साथ अपने अतीत के संबंधों को मज़बूत करके आईपी संबंधी मुद्दों, दवाओं तक पहुंच जैसे कई क्षेत्र हैं जिनमें दक्षिण केन्द्र और आरआईएस ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार और संवहनीय विकास विभाग (आईसीटीएसडी) और डब्ल्यूआईपीओ के साथ मिलकर आईपी के मुद्दे पर काम करने की पेशकश करता है।

शोध-परिवर्धन गतिविधियों को मज़बूत करने के लिए नीतिगत बदलाव

प्रो. सचिन चतुर्वेदी / डॉ रवि के. श्री निवास / श्री अमित कुमार

रिवार्ड (REWARD) एक 2014–2015 की अवधि के लिए ईयू एफपी–7 प्रायोजित परियोजना है। यूक्लान (यूके) और आरआईएस इस परियोजना के भागीदार हैं। यह परियोजना अंतराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) प्रणाली को प्रोत्साहन देने में नए क्षितिज खोलने के प्रयास करेगी। परियोजना का महत्वाकांक्षी परिणाम भेषजीय (फार्मास्यूटिकल) नवाचार के लिए निष्पादन आधारित नैतिक और कानूनी दृष्टि से सुदृढ़ पुरस्कार व्यवस्था है, जो वर्तमान पेटेंट पद्धति की संपूरक है लेकिन दुनिया भर के ग़रीबों के लिए उसके भरपूर हानिकारक प्रभावों का शमन भी करती है। नैतिकवादियों, वकीलों, अर्थशास्त्रियों तथा सांख्यकीविदों के, औषधि, विज्ञान और प्रोद्योगिकी नीति और लैंगिक अध्ययन के विशेषज्ञों के साथ, एक अन्तर–अनुशासनीय सहयोग में चुनी गई व्यवस्था का एक विकसित और एक विकासशील देश में परीक्षण किया जाएगा।

विकासषील देशों में व्यापार, प्रौद्योगिकी और संवृद्धि

प्रो. राम उपेंद्र दास

व्यापार और विकास और व्यापार और प्रौद्यिगिकी के बीच के संबंध और कार्य–कारणताओं को प्रायः सैद्धांतिक और अनुभव मूलक सन्धानों के युग्मक ढांचे के तहत विश्लेशित किया जाता है। यह अध्ययन व्यापार, प्रौद्योगिकी और विकास के बीच के पारस्परिक जुड़ावों के अनुभव मूलक प्रमाण से प्रमाणित संकल्पनात्मक ढांचे के निर्माण के प्रयास करता है। इसका उद्देश्य दक्षिण और दक्षिण–पूर्व एशिया के विकसित देशों में नीतिगत निहितार्थ निकालना है, और उसके माध्यम से इन देशों के विकास सीमांतों को बदलने के लिए व्यापार, प्रौद्योगिकी और विकास के आर–पार सहक्रियताओं का इस्तेमाल किया जा सकता है।

खाद्य सुरक्षा और गरीबी न्यूनीकरण के लिए बीजः भारत और अफ्रीका के बीज उद्योग के बीच सहयोग

प्रो. सचिन चतुर्वेदी / श्री अमित कुमार

यह आईडीएस के नेतृत्व वाली परियोजना है, जिससे आरआईएस, केन्या की सीएबीई, इथियोपिया की ईआईएआर और यूके की आईडीएस संबद्ध हैं। इस परियोजना का उद्देश्य ऐसे अनुसंधान की संभावनाओं का पता लगाना और उसका मानचित्र तैयार करना है जो इस सुझाव की छानबीन करता है कि अफ्रीकी अभिकर्ताओं के साथ सहयोग करके भारतीय बीज उद्योग कम खर्च वाली बीज प्रौद्योगिकी और छोटे

धारकों के लिए विपणन क्षमता मुहैया करा सकता है, जो कम खर्च पर अच्छे कृषि उत्पादन के ज़रिए ग़रीबी में कमी लाएगा, बशर्ते वित्त–पोषण, क्षमता एवं नीति अंतरालों/अवरोधों को दूर कर दिया जाए। यह इस बात का परीक्षण करेगा कि क्या प्रदान की जाने वाली बीज प्रौद्योगिकियां अफ्रीका के ज़्यादा गरीब किसानों की खाद्य सुरक्षा की ज़रूरतों को पूरा करती हैं और क्या खाद्य सुरक्षा और ग़रीबी न्यूनीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए अफ्रीकी बीज प्रणालियों की उत्पादकता और लचीनेपन को बेहतर बनाने के लिए अनुसंधान और विकास से लेकर विपणन तक भारत की व्यापक बीज प्रणाली से कोई सबक लिए गए हैं। अन्वेषण के निश्कर्षों पर हित–धारक संवाद का उपयोग भागीदारियों को मजबूती प्रदान करने और भारतीय कंपनियों के संभाव्य विकास प्रभाव को उत्प्रेरित करने के लिए तैयार की गई आगे की कार्रवाइयों की पहचान के लिए किया जाएगा।

विज्ञान राजनय

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी/डॉ. रवि के. श्रीनिवास/श्री अमित कुमार

विज्ञान राजनय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग के क्षेत्र में एक अहम गतिविधि है और यह अन्य देशों के साथ जुड़ने के लिए रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने विज्ञान राजनय का उपयोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और अंतरराष्ट्रीय सहायता एवं क्षमता निर्माण के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों के हिस्से के रूप में किया है। रॉयल सोसाइटी, और अमेरिकन एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंस विज्ञान के उन निकायों में से हैं जो विज्ञान राजनय पर काम कर रहे हैं और उन्होंने रिपोर्टें प्रकाशित की हैं और इस पर बैठकों का आयोजन किया है। ज्यादा बड़े ढांचे, देशों और राष्ट्रों के क्षेत्रीय समूहों और वैश्विक खिलाड़ी बनने की उनकी आकांक्षाओं के साथ भारत के जुड़ाव को देखते हुए विज्ञान राजनय विज्ञान को भारत के आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने और विकासशील देशों एवं एलडीसी'स के साथ जुड़ावों को गहरा बनाने के उपकरण के रूप में उपयोग करने के रणनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा हो सकता है। एक गतिविधि और भविष्यमुखी पहल के रूप में विज्ञान राजनय को नियोजन, विभिन्न योजनाओं के संवर्धन और गतिविधियों की तथा नीति के लिए प्रासंगिक आगतों तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और विदेश नीति के साथ सतत जुड़ाव की जरूरत होती है। अमेरिकन एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंस (AAAS) ने विज्ञान राजनय के क्षेत्र में तीन प्रक्रियाओं की पहचान की है– राजनय में विज्ञान, विज्ञान के लिए राजनय और राजनय के लिए विज्ञान। तीनों प्रक्रियाएं परस्पर संबंधित हैं। 'राजनय में विज्ञान' में शामिल है वैज्ञानिक समुदाय से प्राप्त विदेश नीति निर्माताओं को आगत (इनपुट) मुहैया कराना। इसमें एमओयू, संधियां और विदेश विकास सहायता के अंग के रूप में रणनीतिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम शामिल हैं। 'विज्ञान के लिए राजनय' वैज्ञानिक आदान–प्रदान और वैज्ञानिक सहयोग को संभव बनाती है। 'राजनय के लिए विज्ञान' में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के जरिये राजनय आता है और यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग की संभावना प्रदान करता है। आरआईएस के विज्ञान राजनय कार्यक्रम में उन प्रक्रियाओं के लिए आगत मुहैया कराना शामिल है और यह आर्थिक एवं विदेश नीति पर आधारित योजनाओं के साथ और इसके उलट बहु–पक्षीय एवं द्विपक्षीय स्तर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी गतिविधियों के और

अधिक एकीकरण को सुगम बनाएगा।

प्रस्तावित कार्यक्रम विज्ञान, अर्थशास्त्र और अंतरराष्ट्रीय मामलों पर ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यक्रम के तहत चार प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार से हैंः (i) बाह्य भीतर की ओर बहाव (एक्सटर्नल इनफ्लो); (ii) अंतरराष्ट्रीय आधार का निर्माण; (iii) नेटवर्कों का विकास और (iv) रणनीतिक चिंतन। उपर्युक्त के अतिरिक्त, यह कार्यक्रम डीएसटी और एमईए के साथ परामर्श करके अन्य प्रासंगिक गतिविधियों को अपने हाथ में लेगा और बहु–पक्षीय एवं द्विपक्षीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग से संबद्ध विज्ञान अकादमियों समेत अन्य संगठनों एवं निकायों के साथ भी काम करेगा। इसे आरआईएस के अन्य संबद्ध कार्य कार्यक्रमों और परियोजनाओं के साथ भी जोड़ा जाएगा।

ट्रिप्स व्यवस्था में भारतीय दवा उद्योग एवं दवा तक पहुंच पर अध्ययन

प्रो. टी सी जेम्स / सुश्री पायल चटर्जी

भारत ने 1 जनवरी, 2005 से प्रभावी ट्रिप्स की शर्तों को पूरा तरह से क्रियान्वित किया। इसका दवा उद्योग पर अधिकतम असर पड़ा है क्योंकि 1972-2004 की अवधि के दौरान भारत ने दवाओं के क्षेत्र में उत्पादों के लिए पेटेंट नहीं प्रदान किये थे। इसके फलस्वरूप, भारत नवीनतम दवाओं के जेनेरिक संस्करणों को पेंटेंट वाले संस्करणों की तुलना में कम कीमतों पर बनाने और मुहैया कराने में समर्थ था। भारतीय दवा उद्योग ने इस अवधि के दौरान विनिर्माण क्षमता का विकास किया और जबर्दस्त वृद्धि का गवाह बना। तथापि, दवाओं के क्षेत्र में उत्पाद पेटेंट व्यवस्था के पहली जनवरी, 2005 को शुरू होने के साथ भारतीय जेनेरिक दवा कंपनियों ने इस लाभ को गँवा दिया। भारतीय दवा उद्योग और दवा तक पहुँच पर ट्रिप्स व्यवस्था के 10 वर्षों के असर पर कोई भी अनुसंधान अध्ययन नहीं किया गया है।

यह अध्ययन इस बात ध्यान केंद्रित करता है कि किस प्रकार से नयी बौद्धिक संपदा व्यवस्था ने दवा उद्योग और भारत एवं अन्य विकासशील देशों में सस्ती दवा तक पहुंच को प्रभावित किया है। अध्ययन का दायरा आजादी के पहले के दिनों से लेकर 1972 तक, 1972 से लेकर 2005 तक, जब किसी भी उत्पाद का पेटेंट नहीं था, और 2005 से लेकर वर्तमान तक भारतीय दवा उद्योग के इतिहास एवं वृद्धि; 2005 के उपरांत इस क्षेत्र में दृष्टिगोचर प्रवृत्तियों, उद्योग की वर्तमान स्थिति, वर्तमान परिदृष्य में भारत एवं अन्य विकासशील देशों में दवाओं तक पहुँच का मुद्दा, दवा उद्योग में नवाचार, जैसा पेटेंटिंग में प्रतिबिंबित होता है; तक विस्तारित है।

यह अध्ययन निम्नलिखित पर विशेष ध्यान देगाः दवा उद्योग को प्रभावित करने वाले नियम और विनियम; उद्योग में वृद्धि के आंकडे; दवा की कीमतों के आंकड़े; आयात–निर्यात के आंकड़े; वर्तमान स्थिति का स्वॉट (एसडब्ल्यूओटी) विश्लेषण; और वृद्धि के प्रमुख संकेतक तथा आगे का रास्ता। यह अध्ययन ऐसे विभिन्न नीति वक्तव्यों का भी परीक्षण करता है जिनका किफायती स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, जैसे–विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति, चिकित्सा उपकरण नीति और स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, भारत में निर्माण अभियान के साथ–साथ आयुष (AYUSH) क्षेत्र के प्रति सरकार का रुख। भारत द्वारा अफ्रीका में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में विकास सहयोग गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। थोक दवाओं की अपनी अधिकांश जरूरतों के लिए एक ही स्रोत पर भारत की अत्यधिक

निर्भरता के खतरों पर नीतिगत बयान पहले ही प्रकाशित और सरकार को मुहैया किया जाएगा। चिकित्सा उपकरण नीति पर दूसरा वक्तव्य भी जल्द तैयार हो रहा है।

विष्व स्वास्थ्य संगठन के लिए भारत में चिकित्सकीय (क्लिनिकल) परीक्षणों पर अध्ययन

प्रो. टी सी जेम्स/सुश्री निवेदिता सक्सेना/श्री जखीर थामस

स्वास्थ्य अधिकार मंच बनाम भारत सरकार एवं अन्य में सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद हाल के वर्षों में भारत में चिकित्सा परीक्षण के विनियम व्यापक रूप से सुधरे हैं। विशेषज्ञ समिति के सुझावों के बाद विनियम में कई परिवर्तन किये गये। पिछले दो वर्षों में इन परिवर्तनों को ज़मीन पर क्रियान्वित किया गया। इन परिवर्तनों के असर का अभी पता नहीं चला है।

इस अध्ययन का उद्देश्य चिकित्सा परीक्षण विनियमों में परिवर्तनों और ज़मीन पर उनके असर को समझना है। अध्ययन में निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल करना प्रस्तावित हैः भारत में चिकित्सकीय परीक्षणों से संबंधित कानून, स्वास्थ्य अधिकार मंच बनाम भारत सरकार एवं अन्य में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णयः सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले भारत में चिकित्सकीय परीक्षणों से संबंधित विनियमों के संदर्भ, अन्तर्वस्तु तथा निर्देश, और इस निर्णय के बाद किये गये परिवर्तन। अध्ययन के प्रमुख घटक हैंः

वर्तमान नैदानिक परीक्षण दिशा–निर्देशों का सिंहावलोकन, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSO) के पास पंजीकृत नैदानिक परीक्षण और पिछले वर्षों के दौरान उनकी संख्या, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पहले और बाद में भारत में मंजूर हुए नैदानिक परीक्षणों की संख्याओं का परीक्षण नये विनियमों का कामकाज, अस्पतालों, नैदानिक अनुसंधान संगठनों, विशेषज्ञों और सीडीएसओके प्रतिसादों को प्राप्तकरने के लिए क्षेत्र अध्ययन करना। भारतीय कानून का अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA), यूरोपीय मेडिसिन्स एजेंसी (EMA) और यूके तथा आसियान देशों के रुखों के संदर्भ में तुलना, अच्छे नैदानिक परीक्षण संचालन के सिद्धांत कौन से हैं और क्या इन तत्वों को भारत की दृष्टि में शामिल किया गया है? क्या उपेक्षित बीमारियों के लिए विनियमों में विशेष रुख की आवश्यकता है तथा कार्य के लिए क्षेत्रों की पहचान करना।

II

नीति शोध पत्र

वर्श 2014–15 में, अपनी कार्ययोजना के अन्तर्गत आरआईएस ने नीति शोध पत्र और प्रतिक्रियाएं प्रदान किए हैं। मंत्रालयों, अन्य विभागों तथा गैर–सरकारी संगठनों को प्रदान किए गए पत्र और प्रतिक्रियों की सूची नीचे दी गई हैः

- क्षेत्रीय संगठन और पहलकदमियां उनके विभिन्न प्रयास आरआईएस की कार्ययोजना में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते रहे। माइक्रो–क्रेडिट, स्वास्थ्य क्षेत्र और कार्य दलों के पुनर्निमाण के क्षेत्रों में नए कार्यक्रम विकसित करने के लिए आईबीएसए प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए नीति आगत शोध पत्र किए गए।
- विदेश मंत्रालय के लिए 'नील अर्थव्यवस्था' (ब्लू इकॉनॉमी) का एक आख्यान विकसित करने के लिए इंडियान ओशन रीजनल एसोसिएशन हेतु शोध पत्र प्रदान किए गए।
- ब्रिक्स वैश्विक तकनीक फ्रेमवर्कों के क्षेत्र में और ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी पर भी शोध पत्र दिया गया। 'संवृद्धि के इंजिन के रूप में व्यापार' के तहत वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को जी–20 प्रक्रिया के लिए भी टिपिप्णीयें दिए गए।
- द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर मुफ्त व्यापार समझौतों के लिए वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को कई शोध पत्र दिए गए। इनमें शामिल हैं सार्क, सीएलएमवी, भारत–आसियान, आरसीईपी और यूरेशियन आर्थिक समुदाय।

- औषधि विभाग को बल्क दवाओं के आयात पर भारत की बढ़ती निर्भरता पर नितिगत शोध पत्र दिए गए। इस नोट में ठोस नीति प्रतिसादों और तदुपरांत भारत के निर्यात के लिए निहितार्थों की चर्चा थी। भारत की बल्क दवाओं के क्षेत्र में आयात पर बढ़ती निर्भरता पर एक नीति सार भी निकाला गया जिसमें भारत सरकार के संबंधित विभागों के विचारार्थ और कार्यान्वयनार्थ कई सुझाव तथा संस्तुतियां दी गई थीं।
- आरआईएस ने ड्राफ्ट आईपीआर नीति पर भी काम किया और इसके औषधि क्षेत्र पर विशेष प्रभाव का विशलेषण किया।
- आरआईएस ने एफआईडीसी (फोरम फॉर इंडियान डेवेलपमेंट कोऑपरेशन) की अपनी पहल के अंश के रूप में डेवेलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनरशिप के साथ घनिष्ठ रूप से काम किया। उत्तर–बुसान प्रक्रिया, डीएसी सदस्यों के अनुभवों, सीएसओ की नियुक्ति और उत्तर–2015 विकास कार्यसूची के लिए नीति आगत प्रदान किए गए। इसी तरह, वित्त मंत्रालय को ऑफिशल डेवेलपमेंट असिस्टेंट (ओडीए) की नई परिभाषा पर भी नितिगत शोध पत्र दिए गए। इसी विषय पर नीति शोध सामग्री प्रधान मंत्री को भी प्रदान किए गए।
- वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने एचएस वर्गीकरण के अनुसार उच्च टेक्नॉलॉजी वस्तुओं को परिभाषित करने का एक नया उपक्रम किया। आरआईएस ने वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को इसकी परिकल्पना और कार्यप्रणाली की एक संक्षिप्त समीक्षा प्रदान की। इस नोट ने टेक्नॉलॉजी तीव्रता के एक उद्योग–आधारित वर्गीकरण की सीमाओं को सामने लाते हुए कार्यप्रणाली में हालिया प्रगति को दृष्टि में रखते हुए उत्पाद–आधारित वर्गीकरण की संस्तुति की। आरआईएस ने इस क्षेत्र में अन्तरराष्ट्रीय वर्गीकरण तंत्रों के बीच समाभिरूपता (कन्वर्जेंस) की ओर महत्वपूर्ण योगदान किए हैं और विकासशील देश परिप्रेक्ष्यों से व्यापक उत्पाद कैटालॉग विकसित किए हैं। इन नोट ने उच्च टेक्नॉलॉजी वस्तुओं को परिभाषित करते हुए टेक्नॉलॉजी तीव्रता के साथ साथ दक्षता तीव्रता को भी विचारगत रखने की संस्तुति की।

III

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

सातवाँ दक्षिण एशिया आर्थिक शिखर सम्मेलन

आरआईएस ने, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के साथ संयुक्त रूप से, 7वें दक्षिण एशिया आर्थिक शिखर सम्मेलन (एसएईएस) का 5–7 नवम्बर 2014 को नई दिल्ली में आयोजन किया। विदेश मंत्रालय के सार्क विभाग और लोक राजनय विभाग ने भी आरआईएस के साथ सहयोग किया था। भारत के महामहिम उप–राष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी ने, जिन्होंने शिखर सम्मेलन का उद्‌घाटन किया, समारोह की शोभा बढ़ाई। शिखर सम्मेलन का विशय था "दक्षिण एशिया आर्थिक संघ की ओर"।

एसएईएस के सह आयोजकों में शामिल थे सेंटर फिर पालिसी डायलॉग (सीपीडी), बांग्लादेश, साउथ एशिया वॉच ऑन ट्रेड, आर्थिकी और पर्यावरण (एसएडब्ल्यूटीईई), नेपाल साउथ एशिया सेंटर फॉर पालिसी स्टडीज (एसएसीईपीएस), नेपाल सस्टेनेबल डेवेलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट (एसडीपीआई), पाकिस्तान और इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज ऑफ श्री लंका (आईपीएस), कोलम्बो। कॉनफेडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई), विश्व बैंक और युनाइटेड नेशन्स इकॉनॉमिक एंड सोशल कमिशन फॉर एशिया एंड दि पैसिफकि (यूएनईएससीएपी) शिखर में भागीदार थे।

भारत के माननीय उप–राष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी ने उद्‌घाटन भाषण दिया। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, ने स्वागत भाषण दिया राजदूत श्याम सरन, अध्यक्ष, आरआईएस, ने आरम्भिक वक्तव्य दिया प्रो.रहमान सोभान, अध्यक्ष, सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग, बांग्लादेश ने विशेष वक्तव्य दिया और प्रो. प्रबीर डे, आरआईएस ने धन्यवाद ज्ञापन किया। तीन दिन के इस सम्मेलन में पुस्तक लोकार्पण, दक्षिण एशिया क्षेत्र से प्रसिद्ध अकादमिक विद्वानों तथा नीतिनिर्माताओं के प्रस्तुतिकरण तथा पैनल चर्चाएँ हुईं।

उद्‌घाटन भाषण दे रहे भारत के माननीय उप–राष्ट्रपति एम हामिद अंसारी। तस्वीर में निम्न लोग (बाएं से दाएं) दिखाई दे रहे हैंः प्रो. सचिन चतुर्वेदी, राजदूत श्याम सरन प्रो. रहमान सोभन और प्रो. प्रबीर डे।

मुख्य सत्र 1 की "दक्षिण एशिया क्षेत्रीय एकीकरण अतीत, वर्तमान और भविष्य" पर पैनल चर्चा में सम्मिलित थे मोहम्मद मुस्तफा मस्तूर, माननीय वित्त उप मंत्री, अफगानिस्तान श्री गौहर रिजवी, बांग्लादेश माननीय प्रधानमंत्री के अंतरराष्ट्रीय मामलों के सलाहकार श्री ल्योन्पो नाम्गे दोरजी, माननीय वित्त मंत्री, भूटानय श्री राम शरण महत, माननीय वित्त मंत्री, नेपालय और श्री सरथ अनुमुगामा, माननीय अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग मंत्री, श्री लंका। राजदूत श्याम सरन, अध्यक्ष, आरआईएस, ने मुख्य सत्र की अध्यक्षता की। मीडिया से बातचीत के अतिरिक्त, 7वें एसएईएस की कार्यसूची में शामिल थीं सघन चर्चाएँ इन विशयों पर–दक्षिण एशिया आर्थिक संघरू चुनौतियाँ और आगामी कार्यय दक्षिण एशिया संयोजकताय तथा दक्षिण एशिया निवेश ब्लॉक के लिए सहयोग। समान्तर सत्रों के विषय थे–मानकों और विनिमयों सहित गैर–शुल्क कदमय वृहदअर्थशास्त्रीय निश्पादन, संभावनाएँ तथा नीति समन्वयय वित्तीय और मौद्रिक। सहयोगय सीमा शुल्क सहयोग सहित व्यापार सुगमीकरणय तथा सेवा व्यापार, पारस्परिक मान्यता और व्यापार सुधार। विस्तृत कार्यक्रम और दिए गए प्रस्तुतिकरण आरआईएस वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

एसएईएस में भाषण देते राजदूत श्याम सरन तस्वीर में निम्न लोग (बाएं से दाएं) दिखाई दे रहे हैंः माननीय श्री मोहम्मद मुस्तफा मस्तूर, उप वित्त मंत्री, अफगानिस्तान, माननीय श्री गौहर रिजवी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के अंतरराष्ट्रीय मामलों के सलाहकारय माननीय श्री ल्योनपो नैमगे दोरजी, वित्त मंत्री, भूटानय माननीय राम शरण महत, वित्त मंत्री, नेपालय और माननीय श्री सरत अमुनुगामा, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहयोग मंत्री, श्रीलंका।

आसियान–भारत के थिंक टैंक नेटवर्क (एआईएनटीटी) पर तीसरी गोलमेज बैठक

आरआईएस के आसियान–भारत केंद्र ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय, आसियान सचिवालय, वियतनामी समाज विज्ञान अकादमी (वीएएसएस) और वियतनामी भारतीय और दक्षिण पश्चिम एशियाई अध्ययन संस्थान (वीआईआईएसएएस) के साथ मिलकर आसियान–भारत एकीकरण और विकास विषय पर 25–26 अगस्त 2014 को हनोई, वियतनाम में आसियान–भारत थिंक टैंक नेटवर्क (एआईएनटीटी) की तीसरी गोलमेज बैठक का आयोजन किया। वियतनाम के माननीय उप–प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री श्री फ़ाम बिन मिन ने मुख्य वक्तव्य दिया। भारत की माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने उद्घाटन भाषण दिया। आईआरएस के उपाध्यक्ष राजदूत वी एस शेषाद्रि और राजदूत अनिल वाधवा, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व), ने विशेष भाषण दिए। आरआईएस के आसियान–भारत केंद्र के संयोजक डॉ प्रबीर डे ने इस गोलमेज बैठक का संयोजन किया और धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम का विस्तृत ब्योरा आरआईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

सुश्री सुषमा स्वराज, माननीय विदेश मंत्री, भारत सरकार आसियान–भारत नेटवर्क ऑफ थिंक–टैंक्स (एआईएनटीटी) पर तृतीय चक्र की गोलमेज वार्ता में उद्घाटन भाषण देते हुए।

भारत और हिंद महासागर पर अंतरराश्ट्रीय सम्मेलनः समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों का नवीनीकरण

आरआईएस ने सामाजिक एवम सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान (आईएससीएस), कोलकाता के साथ मिल कर 20–22 मार्च 2015 को भुवनेशवर, उड़ीसा में भारत और हिंद महासागरः समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों का नवीनीकरण विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। भारत की माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने सम्मेलन का शुभारंभ किया। उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने विशेष अतिथि के रूप में समारोह की शोभा बढ़ाई। उद्घाटन सत्र के सम्मानित अतिथियों में भारत सरकार के माननीय पेट्रोलियम राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेंद्र प्रधान, बीआईएमएसटीईसी, ढाका, बांगलादेश के महासचिव श्री सुमित नकंदला शामिल थे। माननीय श्रीमती सुषमा स्वराज ने हिंद महासागर संसाधन केंद्र का लोगो भी जारी किया। उड़ीसा सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री अशोक चंद्र पांडा ने हिंद महासागरः समुद्री यात्रा की विरासत विषय पर

श्रीमती सुषमा स्वराज, माननीय विदेश मंत्री, भारत सरकार श्री नवीन पटनायक, माननीय मुख्यमंत्री, ओडिशा और श्री धर्मेंद्र प्रधान, माननीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री, भारत सरकार के साथ आरआईएस प्रकाशनों को को जारी करते हुए। तस्वीर में इनके अलावा (दाएं से बांए) श्री आर.एन. रवि, प्रधानमंत्री कार्यालय, श्री सुमित नाकान्डाला, महासचिव, बिमस्टेक ढाका, प्रो सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, श्री अरिंदम मुखर्जी, सचिव, आईएससीएस, कोलकाता और प्रो. एसके मोहंती, आरआईएस भी दिखाई दे रहे हैं।

एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। भारत सरकार ने इस अवसर पर हिंद महासागर और राजेंद्र चोला पर एक डाकटिकट भी जारी किया। आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की।

तीन दिवसीय सम्मेलन के अंत में भारत सरकार के माननीय रक्षामंत्री श्री मनोहर पणिक्कर ने समापन भाषण दिया। भारत सरकार की माननीय वाणिज्य और उद्योग राजमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती निर्मला सीतारामन ने भी समापन सत्र को संबोधित किया। उड़ीसा के माननीय राज्यपाल माननीय डॉ एस सी जमीर समापन सत्र के मुख्य अतिथि थे। भारत सरकार के माननीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धमेंद्र प्रधान भी समापन सत्र में उपस्थित थे। स्वागत समिति के अध्यक्ष डॉ एच पी दास ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। आरआईएस के प्रो. एस के मोहंती ने भुवनेश्वर घोषणा पत्र प्रस्तुत किया।

सम्मेलन के दूसरे दिन की शुरुआत इंडियन ओशन रिम असोसिएशन (आईओआरए) में ऐतिहासिक संपर्कों और सांस्कृतिक संजालों पर पहले मुख्य सत्र के साथ हुई। भारत सरकार के माननीय संस्कृति और पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ महेश शर्मा ने इस सत्र की अध्यक्षता की।

हिन्द महासागर में क्षेत्रीय सामुद्रिक और ऊर्जा सुरक्षा विषय पर दूसरे समग्र सत्र की सह अध्यक्षता भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव राजदूत ए एन राम और भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री उपेंद्र प्रताप सिंह ने की। दूसरे दिन के समानान्तर सत्रों थेः 'व्यापारिक संपर्क मार्ग, जिन्स और व्यापारी', जिनकी अध्यक्षता इंस्टीट्यूट डी चंद्रनगौर, हैदराबाद विश्वविद्यालय, भारत की प्राध्यापक रिला मुखर्जी ने की; 'धर्म और साहित्यः बौद्ध धर्म, ब्राह्मणवाद, महाकाव्य और संस्कृत में धर्मनिरपेक्ष साहित्य'—अध्यक्ष, जेएनयू, नई दिल्ली, भारत के प्रोफेसर रणवीर चक्रवर्ती; 'हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवास और जन

प्रसार (डायस्पोरा)'–अध्यक्षता बांगलादेश के विदेश सचिव श्री मोहम्मद शाहिदुल हक़; 'सामुद्रिक और मानवीय मुद्दे'–अध्यक्षता आईसीडब्ल्यूए, नई दिल्ली के महानिदेशक, राजदूत राजीव भाटियाा; 'ग़ैर–पारंपरिक सुरक्षा मुद्दे'–अध्यक्षता एमिटी ला स्कूल, एमिटी विशविद्यालय, नोएडा, भारत, के निदेशक मेजर जनरल (प्रोफेसर) नीलेंद्र कुमार द्वारा, तथा 'संसाधन, जलवायु परिवर्तन और संवहनीय विकास'– अध्यक्षता बांगलादेश में भारत के उप–उच्चायुक्त श्री संदीप चक्रवर्ती द्वारा।

'आईओआरए में व्यापार और निवेश में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग' विषय पर तीसरे दिन तीसरे मुख्य सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने की। तीसरे दिन भारत सरकार के पूर्व विदेश सचिव राजदूत ए एन राम की अध्यक्षता में 'सेक्टरों में सहयोग'; बांगलादेश के विदेश सचिव श्री मोहम्मद शाहिदुल हक़ की अध्यक्षता में 'ब्लू इकोनॅमी'; दक्षिण अफ्रीकी अंतरराष्ट्रीय मामले संस्थान (एसएआईआईए), जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका की मुख्य कार्यकारी डॉ एलिज़ाबेथ सिडिरोपुलोस की अध्यक्षता में 'बी 2 बी' पर समांतर सत्र भी आयोजित हुए।

अनेक ज्ञान सत्रों, के अतिरिक्त दो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए: खंडागिरि में ओडिसी फ़्यूज़न और शाम को म्यांमार की नर्तक मंडली के नृत्य। आरआईएस के सलाहकार प्रो. टी सी जेम्स, डॉ प्रियदर्शी दास, शोध सहयोगी; श्री महेश सी. अरोड़ा, निदेशक (वित्त और प्रशासन); और सुश्री आस्था गुप्ता, शोध सहायक ने भी सम्मेलन में हिस्सा लिया।

दिल्ली संवाद VII: 'आसियान–भारतः उत्तर–2015 कार्यसूची को आकार देना'

आसियान–भारतः उत्तर–2015 कार्यसूची को आकार देना' विषय पर दो दिवसीय दिल्ली संवाद VII का शुभारंभ भारत सरकार की माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 11 मार्च 2015 को नई दिल्ली में किया। इस वार्तालाप का आयोजन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने आरआईएस, नयी दिल्ली के आसियान–भारत केंद्र (एआईसी); रक्षा अध्ययन और विशलेषण संस्थान; इंडियन चैंबर्स ऑफ़ कामर्स ऐंड इंडस्ट्री; इंडियन काउन्सिल ऑफ़ वर्ल्ड अफ़ेयर्स; दि इन्स्टीट्यूट ऑफ़ साउथ

श्री मनोहर परिकर, माननीय प्रतिरक्षा मंत्री, भारत सरकार, डॉ एस.सी. जमीर, ओडिशा के माननीय राज्यपाल और श्री धर्मेंद्र प्रधान, माननीय पेट्रोल राज्य मंत्री तथा (बाएं से दाएं) समापन सत्र में प्रो. किशोर बासा, उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, डॉ. एच पी दास, अध्यक्ष, स्वागत समिति, प्रो. एस.के. मोहंती, आरआईएसय और प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस।

एशिएन स्टडीज़, सिंगापुर; दि एसएईए ग्रुप रिसर्च, सिंगापुर; दि इन्सटीट्यूट ऑफ़ स्ट्रेटजिक ऐंड इंटरनेशल स्टडीज़, मलेशिया; दिल्ली संवाद VII: आसियान–भारतः उत्तर–2015 कार्यसूची को आकार देना; दि इकोनॉमिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट ऑफ आसियान (एएसईएएन) ऐंड ईस्ट एशिया, जकार्ता; दि इन्स्टीट्यूट ऑफ़ सिक्यूरिटी ऐंड इंटरनेशल स्टडीज़, थाईलैंड; की भागीदारी और भारतीय उद्योग महासंघ सहित बहुत से संगठनों के सहयोग से आयोजित किया।

दिल्ली वार्तालाप आसियान–भारत संबंध के सभी पहलुओं पर सामूहिक रूप से मंथन के लिए वार्षिक ट्रैक 1.5 वार्तालाप प्रक्रिया पर आधारित है और आसियान–भारत की रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना इसका उद्देश्य है। भारत और आसियान देशों के राजनेता, नीतिनिर्माता, वरिष्ठ अधिकारी, राजनयिक, व्यापारिक नेता, थिंक टैंक, शिक्षाविद इस दो दिवसीय समारोह के लिए इकट्ठा हुए। इस समारोह के दौरान 'ज्ञान समाजों और अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण; उपाधियों की पारस्परिक स्वीकृति सहित शिक्षा और कौशल विकास','सांस्कृतिक संबंधों और जनता से जनता संपर्कों को सुदृढ़ करने', 'भारत और आसियान के बीच अवसंरचना और संयोजकता का निर्माण करने', क्षेत्रीय उत्पादन संजाल और मूल्य श्रृंखला का एकीकरण करने', 'आसियान–भारत संबंधों की भावी दिशाएं' सहित शिक्षा और कौशल विकास पर उल्लेखनीय पैनल चर्चाएं हुईं। वार्तालाप में एक समर्पित व्यापार सत्र भी रखा गया था जिसमें आसियान आर्थिक समुदाय की चर्चा की गई। भारत सरकार का 'भारत निर्माण' कार्यक्रम भी पेश किया गया। आरआईएस के आसियान–भारत केंद्र में आर्थिक मुद्दों पर एक सत्र का आयोजन किया गया जिसमें अवसंरचना और संयोजकता, ऊर्जा और क्षेत्रीय उत्पादन संजाल और मूल्य श्रृंखलाओं के एकीकरण की चर्चा की गई। आरआईएस के अध्यक्ष राजदूत श्याम सरन ने सत्र की अध्यक्षता की। मलेशिया इंस्टीट्यूट ऑफ़ इकोनॉमिक रिसर्च क्वालालम्पुर के वरिष्ठ फेलो डॉ शंकरन नांबियार और आईआरएस के आसियान–भारत केंद्र के संयोजक प्रोफेसर प्रबीर डे प्रमुख वक्ता थे। आसियान अध्ययन केंद्र के प्रमुख और चुला ग्लोबल नेटवर्क,

श्रीमती सुषमा स्वराज, माननीय विदेश मंत्री, भारत सरकार दिल्ली संवाद–7 में अन्य महानुभावों के साथ।

राजदूत श्याम सरन, अध्यक्ष, आरआईएस आर्थिक मुद्दों पर सत्र की अध्यक्षता करते हुए। तस्वीर में इसके अलावा (बाएं से दाएं) डा नागेश कुमार, प्रो. सुथिफांड चिरोथिवैट, डॉ शंकरन नांबियार, और प्रो. प्रबीर डे।

चुलालोंगकोर्न विश्वविद्यालय, बैंकौक के निदेशक प्रो. सुतिफंद चिरातिवट; और संयुक्त राष्ट्र के एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग के दक्षिण और दक्षिण–पश्चिम कार्यालय के प्रमुख डॉ नागेश कुमार पैनल के सदस्य थे।

बल्क दवाओं के लिए आयात पर भारत की बढ़ती निर्भरता पर परिचर्चा

भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'मेक इन इंडिया' ('भारत में बनाएं') आंदोलन की घोषणा के बाद आरआईएस ने 'भारत में बनाएं और बाहरी क्षेत्रः उत्पादन, रोज़गार और निर्यात' पर एक श्रृंखला शुरू की है। इस श्रृंखला के अंतर्गत आरआईएस ने 23 दिसंबर 2014 को नई दिल्ली में बल्क ड्रग्स क क्षेत्र में आयात पर भारत की बढ़ती निर्भरता पर परिचर्चा आयोजित की। भारत सरकार के माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री अनंत कुमार ने समापन भाषण दिया। भारत सरकार के फ़ार्मास्यूटिकल्स विभाग के सचिव डॉ. वी के सुभुराज ने उद्घाटन भाषण दिया। भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर सुदीप चौधरी ने मुख्य वक्तव्य दिया। आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी और आईआरएस के सलाहकार प्रो. टी सी जेम्स ने भी उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।

श्री अनंत कुमार, माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री, भारत सरकार विदाई भाषण देते हुए। तस्वीर में निम्न लोग (बाएं से दाएं) दिखाई दे रहे हैंः डॉ अश्विनी गुप्ता, प्रो. सचिन चतुर्वेदी और प्रो. टीसी जेम्स ।

भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव श्री सुधांशु पांडे ने पहले कामकाजी सत्र की अध्यक्षता की जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और भेषजीय रसायनों (फार्मास्युटिकल्स) के व्यापार पर चर्चा हुई। प्रो. सुदीप चौधरी ने भारत में बल्क दवा उद्योग की अवस्था पर हुए सत्र की अध्यक्षता की। भारतीय चिकित्सा शोध परिषद के महानिदेशक और दवा नीति कमेटी के अध्यक्ष डॉ वी एम कटोच ने नवाचार और उद्योगः दवा नीति की चुनौतियां पर हुए तीसरे सत्र में विशेष वक्तव्य दिया। भारत सरकार के वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध विभाग के सलाहकार/वैज्ञानिक 'जी' डॉ. अश्विनी गुप्ता ने इस सत्र और इसके बाद के फ़ार्मास्यूटिकल्स और औशधियों तक पहुंच पर आयोजित सत्र की सदारत की।

विभिन्न सत्रों के महत्वपूर्ण वक्ताओं की सूची में जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी, वाशिंगटॅन डीसी, के स्कूल ऑफ़ पब्लिक पॉलिसी के प्रो. रामकिशन एस राजन; इंडियन ड्रग ऐंड फ़ार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) की पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ (श्रीमती) जयश्री गुप्ता; सेंटर फ़ार डब्ल्यूटीओ स्टडीज़, इंडियन इस्टीट्यूट ऑफ़ फ़ारेन ट्रेड (आईआईएफटी), नई दिल्ली के प्रमुख डॉ. अभिजीय दास, की गैड बॉयोजेन प्रा. लि के प्रबंध निदेशक और भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पूर्व सलाहकार डॉ पीके घोष; इन्स्टीट्यूट ऑफ़ स्टडीज़ इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट (आईएसआईडी), नयी दिल्ली के प्रो. दिनेश अबरोल; भारत सरकार के वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध परिषद (सीएसआईआर) के अंतर्गत ओपन सोर्स ड्रग डिस्कॅवरी (ओएसडीडी) के पूर्व निदेशक श्री ज़ाकिर थामस; केंद्रीय औशधि मानक नियंत्रण प्रतिष्ठान (सीडीएससीओ) के उप–औषधि नियंत्रक डॉ. ए आर कृष्णन, सेंटर फ़ॉर डब्ल्यूटीओ स्टडीज़, आईआईएफटी के डॉ. मुरली कल्लुम्मल; पीपल्स हेल्थ मूवमेंट इंडिया के डा. अमित सेनगुप्ता; ऑल इंडिया ड्रग ऐक्शन नेटवर्क की संस्थापक, संयोजक और सहसंचालक, इनिशिएटिव फ़ॉर हेल्थ ऐंड इक्विटी ऐंड सोसायटी की संयोजक और हेल्थ ऐक्शन इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक की पूर्व अध्यक्ष डॉ. मीरा शिवा; और सेंट्रल युनिवर्सिटी ऑफ़ गुजरात के डॉ. रेज़ी के. जोसफ शामिल थे। आरआईएसके महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी और आरआईएसके विजिटिंग फेलो डॉ. एन चंद्रमोहन ने समापन सत्र को संबोधित किया।

आरआईएस में मलेशिया के व्यापार मंत्री दातो श्री मुस्तपा बिन मोहमद

आरआईएस ने 15 जनवरी 2015 को नई दिल्ली में भारत की आर्थिक गतिशीलता और भारत की पूर्व में काम करो की नीति के संदर्भ में भारत–मलेशिया व्यापार और आर्थिक सहयोग विषय पर आर्थिक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में मलेशिया के माननीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार और उद्योद मंत्री दातो श्री मुस्तपाबिन मोहमद ने विशेष वक्तव्तय दिया। आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत वक्तव्य दिया। आरआईएस के प्रो. राम उपेंद्र ने भी अपनी टिप्पणियां दीं। संगोष्ठी के वक्ताओं की सूची में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री रवि कपूर और प्रणीति शोध केंद्र, (सेंटर फॉर पालिसी रिसर्च) नई दिल्ली के प्रोफेसर डा. राजीव कुमार शामिल थे। मलेशिया के उच्चायुक्त महामहिम दातुक नैमुन अशकलि मोहम्मद ने भी संगोष्ठी में हिस्सा लिया। इस अवसर पर विभिन्न देशों के राजनयिक और उद्योग के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

श्री दातो सिरी मुस्तपा बिन मोहम्मद, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उद्योग मंत्री, मलेशिया विशेष भाषण देते हुए। इसके अलावा चित्र में (बाएं से दाएं) श्री ऐनुल एजात अहमद इशक, मंत्री कार्यालय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उद्योग मंत्रालय, मलेशिया, दातुक नैमुन अशोकलि मोहम्मद, भारत में मलेशिया के उच्चायुक्त, प्रो. राम उपेंद्र दास, आरआईएस और प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस।

माननीय डॉ. मनमोहन सिंह आरआईएस सभागार का जी. पार्थसारथी सभागार के रूप में लोकार्पण किया

आरआईएस ने 20 फ़रवरी 2015 को आरआईएस सभागार के जी. पार्थसारथी सभागार के रूप में लोकार्पण का आयोजन किया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और आरआईएस के पूर्व अध्यक्ष माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अत्यंत विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में शिलालेख का अनावरण किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने संबोधन में उत्कृष्टता केंद्रों के निर्माण में जी. पार्थसारथी की भूमिका याद की। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में पूर्व राजनयिक जी. पार्थसारथी (आरआईएस के संस्थापक अध्यक्ष) के व्यापक योगदानों को भी याद किया। उन्होंने यह भी कहा कि जीपी (जी. पार्थसारथी इसी नाम से लोकप्रिय थे) का मानना था कि आरआईएस को दक्षिण–दक्षिण आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विकासशील

पट्टिका का अनावरण करते माननीय डॉ. मनमोहन सिंह। तस्वीर में (बाएं से दाएं) दिखाई दे रहे हैं: राजदूत श्याम सरन, अध्यक्ष, आरआईएस, राजदूत एम. रासगोत्रा और प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस।

देशों के लिए अग्रणी और प्रभावी वैश्विक थिंक टैंक के रूप में काम करना चाहिए। इसे हमेशा आरआईएस के कार्यों का मार्गदर्शक सिद्धांत बने रहना चाहिए।

डॉ. सिंह के अतिरिक्त आरआईएस के अध्यक्ष राजदूत श्याम सरन और अवकाश प्राप्त कमोडोर सी. उदय भास्कर ने भी जीपी को श्रद्धांजलि दी। भारत सरकार के पूर्व सचिव और उनके बेटे अशोक पार्थसारथी ने भी उत्कृष्टता संस्थानों के निर्माण में अपने पिता का योगदान याद किया। आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया और आरआईएस के निर्माण में जी. पार्थसारथी के योगदानों और दूसरी जगहों पर काम करने के प्रलोभन के बावजूद आरआईएस में रुके रहने वाले शोधकर्ताओं के लिए उनके प्रोत्साहन को स्मरण किया। उन्होंने इस तथ्य को रेखांकित किया कि श्री जी. पार्थ सारथी ने आरआईएस को जो महान दृष्टि प्रदान की उसके लिए यह संस्थान उनका ऋणी है; इनमें सामूहिक आत्मविश्वास, उद्देश्य की एकता और सूचना के आदान–प्रदान और विश्व अर्थव्यवस्था में मूलभूत संरचनात्मक बदलावों और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों और विकासशील देशों के लिए उनके निहितार्थों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोगात्मक शोध के माध्यम से विकासशील देशों के बीच उद्देश्य की एकता और बेहतर समझदारी को प्रोत्साहन देना शामिल है। राजदूत श्याम सरन ने आरआईएस के उन योगदानों को रेखांकित किया जिन्होंने न केवल भारत बल्कि व्यापक रूप से पूरी विकासशील दुनिया की नीति निर्धारण प्रक्रिया को प्रभावित किया है।

समारोह में उपस्थित महत्वपूर्ण अतिथियों में राजदूत एन. रसगोत्रा, डॉ वी आर पंचमुखी, राजदूत अर्जुन असरानी, राजदूत अरुंधती घोष, राजदूत जयंत प्रसाद, श्री चरणजीत सिंह, प्रो. एस आर हाशिम, डॉ. नागेश कुमार, डॉ. रामगोपाल अग्रवाल, प्रो. सुनंदा सेन, डॉ. एस आर राव, डॉ. वी एल राव, डॉ. संतोश महरोत्रा और राजदूत सी. गुरुराज राव शामिल थे।

भारत–आसियान संयोजकता (कनेक्टिविटी) पर गोलमेज बैठक

आरआईएस के आसियान–भारत केंद्र ने 29–30 सितंबर 2014 को शिलांग में इंडियन चैंबर ऑफ़ कामर्स (आईसीसी) और नार्थ ईस्टर्न काउंसिल (एनईसी) के साथ मिल कर 'भारत–आसियान संयोजकताः उत्तरपूर्वी क्षेत्र के लिए चुनौतियां और संभावनाएं' विषय पर गोलमेज चर्चा का आयोजन किया। आरआईएस के आसियान–भारत केंद्र के संयोजक प्रो. प्रबीर डे ने स्वागत भाषण दिया और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) राजदूत अनिल वाधवा ने मुख्य भाषण दिया। भारत में इंडोनेशिया के राजदूत माननीय श्री रिज़ाली विल्मर इंद्रकेसुमा ने विशेष वक्तव्य दिया। भारत में राजनयिक प्रमुखों, राजनयिकों, उत्तर–पूर्व के वरिष्ठ प्रशासकों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इस गोलमेज सभा में आरआईएस के शोध प्रबंध "भारत के उत्तर–पूर्वी क्षेत्र, बांगलादेश और म्यांमार के बीच सीमा पार के उत्पादन तंत्र का विकास" का लोकार्पण भी किया गया। इस सम्मेलन के अधिक विवरण आरआईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

राजदूत अनिल वधवा, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, राजदूत वी एस शेषाद्री, वाइस चेयरमैन, आरआईएस, श्री रूपेन रॉय, इंडियन चौंबर आप कामर्स के चेयरमैन के साथ आशियान देशों के मिशन प्रमुख भारत–आसियान कनेक्टिविटी पर गोलमेज मेंः 29 सितम्बर 2014 को शिलांग में आयोजित आयोजित उत्तर–पूर्व के लिए चुनौतियां और अवसर।

कृषि में नई प्रौद्योगिकी में भारत–अफ्रीका की साझेदारी पर सम्मेलन

आरआईएस ने 12 फ़रवरी 2015 को नई दिल्ली में कृषि में नई प्रौद्योगिकी में भारत–अफ्रीका की साझेदारी पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। आरआईएस के प्रो. एस के मोहंती ने स्वागत भाषण दिया। भारत सरकार के पूर्व विदेश सचिव राजदूत शशांक ने उद्घाटन भाषण दिया। इस सम्मेलन में शिक्षा, जगत सरकार, उद्योग और अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चर्चाओं में व्यापक रूप से दो विषयों, यानी मुख्य क्षेत्र में भारत–अफ्रीका सहयोग; और अफ्रीका में कृषि मशीनरी, कृषि और खाद्य क्षेत्र में संभावनाएं पर प्रस्तुतिकरण और बातचीत हुई। सम्मेलन के दो सत्रों ने कृषि क्षेत्र में भारत–अफ्रीका अनुंबध की संभावनाओं का व्यापाक परिदृश्य प्रस्तुत किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि उन्होंने अफ्रीका में खाद्य, पोषण और आय सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों के समाधान के लिए कृषि क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आगे की चर्चा की ज़मीन तैयार की।

सम्मेलन से कृषि के क्षेत्र में भारत और अफ्रीका के बीच भागीदारी को और भी गहरा बनाने के लिए कई महत्तवपूर्ण सुझाव उभर कर सामने आए। प्रतिनिधियों ने संस्थानों और उपयुक्त नीतियों का महत्व रेखांकित किया। अफ्रीकी किसानों को बेहतर ढंग से नई कृषि प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए प्रसंग–आधारित हस्तक्षेपों और प्रासांगिक क्षमता निर्माण उपायों के प्रावधान की आवश्यकता पर बल दिया गया। अफ्रीकी देशों को वहनीय और समंजनीय कृषि प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने की भारत की क्षमता के मद्देनज़र सुझाव दिया गया कि परिवर्धित बीजों, बेहतर कृषि मशीनों और सिंचाई प्रौद्योगिकियों की स्थानीय मांग पूरी करने के लिए अधिक से अधिक अच्छी भारतीय कंपनियों को अफ्रीकी देशों में अपने उद्यम लगाने पर भी बल दिया गया। चर्चाओं में

प्रो. एस के. मोहंती, आरआईएस स्वागत टिप्पणियां करते हुए। इसके अलावा तस्वीर में हैं (बाएं से दाएं) श्री संजीव चोपड़ा, संयुक्त सचिव, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, कृषि और सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकारय राजदूत शषांक, पूर्व विदेश सचिव, भारत सरकार, श्री एडगर वावोम्बा, अफ्रीकी कृषि प्रौद्योगिकी फाउंडेशन (एएटीएफ), और डॉ पार्थ दासगुप्ता, सलाहकार, टिकाऊ कृषि के लिए सिनजेंटा फाउंडेशन।

पशुओं के लिए चारा और आहार देने वाली फ़सलों की खेती करने; खाद्य संसाधन, छोटे किसानों को तर्कसंगत दरों पर भाड़े पर कृषि मशीनें देने; जर्मप्लाज़्मकी साझेदारी करने; जीनोटाइपिंग करने के साथ–साथ साझा प्रोद्योगिकी मूल्यांकन और जैव सुरक्षा प्रयोगों इत्यादि जैसे अनेक विचार उभर कर सामने आये।

ब्रिसबेन जी–20 शिखर सम्मेलन के समक्ष उपस्थित मुद्दों पर संगोष्ठी

आरआईएस ने 30 अक्तूबर 2014 को नयी दिल्ली में ब्रिसबेन जी–20 शिखर सम्मेलन के समक्ष उपस्थित मुद्दों पर संगोष्ठी आयोजित की। जी–20 शिखर सम्मेलन में भारत के शेरपा माननीय डॉ. सुरेश प्रभु ने मुख्य वक्तव्य दिया। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की सचिव (ईआर और डीपीए) सुश्री सुजाता मेहता ने संगोष्ठी की अध्यक्षता की। सामाजिक विकास परिषद् (सीएसडी) के अध्यक्ष प्रो. मुचकुंद दुबे ने वैश्विक व्यापार और वित्तीय प्रणाली, ऊर्जा और विकास के मुद्दों पर आयोजित पहले सत्र की अध्यक्षता की। इस सत्र के वक्ताओं में आरआईएस महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी, प्रो. एस के मोहंती; तथा सलाहकार प्रो. मनमोहन अग्रवाल; और टेरी (टीईआरआई) विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. लीना श्रीवास्तव शामिल थीं। आरआईएस के प्रो. राम उपेंद्र दास ने वैश्विक विकास और अवसंरचना के वित्तपोषण पर आयोजित दूसरे सत्र की अध्यक्षता की। इस सत्र के वक्ताओं में राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) के निदेशक और मुख्य कार्यकारी प्रो. रथिन रॉय; और एनआईपीएफपी की प्रो. डॉ. आर. कविता राव शामिल थीं। इन सभी सत्रों में खुली चर्चाएं भी हुई।

माननीय डॉ सुरेश प्रभु, भारत सरकार के शेरपा जी –20 शिखर सम्मेलन में मुख्य भाषण देते हुए। इसके अलावा तस्वीर में सुश्री सुजाता मेहता, सचिव (ईआर और डीपीए), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस भी हैं।

दक्षिण एशिया विकास और सहयोग रिपोर्ट 2014 का विमोचन

आरआईएस ने अट्ठारहवें दक्षेष शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर काठमांडु, नेपाल, में साउथ एशिया वाच ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक्स ऐंड एन्वायरनमेंट (एसएडब्ल्यूटीईई) के सहयोग से दक्षिण एशिया विकास और सहयोग रिपोर्ट 2014 का विमोचन किया। इस रिपोर्ट में आर्थिक समेकन के माध्यम से परिष्कृत आर्थिक गतिविधियों द्वारा रोज़गार सृजन पर बल दिया गया है। यह प्रकारांतर से शांतिकारक होगा। यह दृश्टिकोण इस मामले में अनूठा है कि यह क्षेत्रीय सहयोग पहल करने के पहले शांति स्थापना की प्रतीक्षा करने के ख़िलाफ़ तर्क देता है। यह 'शांति से समृद्धि' की बजाय 'समृद्धि से शांति' के 'प्रतिलोम कार्य कारण संबंध' पर बल देता है।

प्रो. राम उपेंद्र दास, आरआईएस और डॉ पोश राज पांडेय, के साथ दक्षिण एशिया विकास और सहयोग रिपोर्ट जारी करते हुए।

साइबर सुरक्षा पर भारत–आसियान सम्मेलन

आरआईएस के आसियान–भारत केंद्र (एआईसी) ने 19 जनवरी, 2015 को नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। आरआईएस के अध्यक्ष राजदूत श्याम सरन ने स्वागत भाषण दिया। भारत में इंडोनेशियाई राजदूत महामहिम श्री रिज़ाली विल्मर इंद्रकेसुमा ने विशेष भाषण दिया। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) अनिल वाधवा ने उद्घाटन भाषण दिया। राजनीतिक और सुरक्षा निदेशालय के आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय विभाग, सचिवालय आसियान, जकार्ता के निदेशक श्री प्रताप परमेश्वरन ने विशेष टिप्पणियां कीं। नैसकॉम (नेशनल असोसिएशन ऑफ़ सॉफ़्टवेयर ऐंड सर्विसेज़ कंपनीज़), नई दिल्ली के अध्यक्ष श्री आर चंद्रशेखर ने भी विशेष भाषण दिया। आरआईएस के आसियान–इंडिया केंद्र (एआईसी) के संयोजक प्रो. प्रबीर डे ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। साइबर सुरक्षा के अंतर्गत इंटरनेट गवर्नेंस संबंधी मुद्दे, महत्वपूर्ण सूचना, अवसंरचना, साइबर युद्ध, और साइबर हथियार, साइबर जासूसी, साइबर अपराध और आतंकवाद आते हैं। भारत ने 2013 में साइबर सुरक्षा नीति तैयार और प्रकाशित की थी और ऐसा करने वाले चंद देशों में से एक था। आसियान और भारत के बीच साइबर सुरक्षा गतिविधियों को मजबूत करने और प्रोत्साहित करने के लिए रणनीति की पहचान करना इस सम्मेलन के उद्देष्यों में से एक था।

पहले सत्र की, जिसने साइबर सुरक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत की, अध्यक्षता आरआईएस के उपाध्यक्ष राजदूत वी एस शेषाद्रि ने की। भारत सरकार के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राजदूत अरविंद गुप्ता ने सत्र को विशेष रूप से संबोधित किया। 'साइबर सुरक्षा की वर्तमान चुनौतियां' पर आयोजित दूसरे सत्र को नैसकॉम के पूर्व महानिदेशक डॉ. अनुपम खन्ना ने संचालित किया और भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की इंडियन कंप्यूटर इमर्जेंसी रिस्पॉन्स टीम (सीईआरटी–आइएन) के महानिदेशक डॉ. गुलशन राय ने सत्र को विशेष

राजदूत अनिल धवा, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के उद्घाटन भाषण देते हुए। तस्वीर में (बाएं से दाएं) प्रो. प्रबीर डे, राजदूत श्याम सरन, माननीय श्री रिजाली विल्मर इंद्राकेसुमा, भारत में इंडोनेशिया के राजदूत, श्री आर चंद्रशेखर, अध्यक्ष, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (नैसकॉम) और श्री प्रताप परमेश्वरन, निदेशक, राजनीतिक और सुरक्षा निदेशालय, आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय विभाग, आसियान सचिवालय।

प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस साइबर सुरक्षा पर आसियान प्रतिनिधिमंडल के साथ गोलमेज चर्चा में हिस्सा लेते हुए।

रूप से संबोधित किया। भावी मार्ग की चर्चा करने वाले समापन सत्र का संचालन आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने किया। पूर्व उप–राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की सचिव (पूर्व) सुश्री विजया लता रेड्डी ने सत्र में विशेष वक्तव्य दिया। आरआईएस के उपाध्यक्ष राजदूत वी एस शेषाद्रि ने समापन टिप्पणी की और प्रो. प्रबीर डे ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

इस सम्मेलन के बाद साइबर सुरक्षा पर आसियान के शिष्टमंडल के साथ एक गोलमेज चर्चा हुई जिसका आयोजन 20 जनवरी 2015 को आरआईएस में किया गया। इस गोलमेज बैठक में आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद् (डीएससीआई), नई दिल्ली के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कमलेश बजाज ने उद्घाटन भाषण दिया। आसियान के जकार्ता स्थित सचिवालय के आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय विभाग के राजनीतिक और सुरक्षा निदेशालय के निदेशक श्री प्रताप परमेश्वरन ने गोलमेज को विशेष रूप से संबोधित किया। साइबर सुरक्षा पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष और एनआईआईटी टेक्नॉलॉजीज़के ग्लोबल प्रैक्टिस हेड, सीआईएसओ, एनआईआईटी टेक्नॉलॉजीज़, कर्नल अरुण कुमार आनंद; ईएक्सएल सर्विसेज़ के ग्लोबल सीआईओ श्री बलजिंदर सिंह और डेटा रिजॉल्व के सीईओ श्री ध्रुव खन्ना; टेक महिंद्रा के एवीपी और फ़ंक्शन हेड श्री के एस पोनिया; एचसीएल टेक्नॉलॉजीज़, सीआईएसओ श्री मनोज सारंगी; आईआरएमसी विप्रो, के सीआईएसओ और प्रमुख श्री सुनिल वार्के; टीसीएस के उपाध्यक्ष श्री तन्मय चक्रवर्ती और टीसीएस के ई सुरक्षा लीडर श्री प्रसेनजित दास ने व्याख्यान दिए। इसके बाद खुला सत्र चला। प्रो. प्रबीर डे ने धन्यवाद दिया।

इस सम्मेलन में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध ज्ञान की वर्तमान स्थिति और इस क्षेत्र में और क्षमता के निर्माण के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा करने के लिए आसियान और भारत के विशेषज्ञ इकट्ठा हुए। विस्तृत कार्यक्रम और उसमें दिए गए व्याख्यान आरआईएस की वेब साइट पर उपलब्ध हैं।

एफआईडीसी की क्षेत्रीय परामर्श बैठकें

फ़ोरम फ़ॉर इंडियन डेवलॅपमेंट कोऑपरेशन (एफआईडीसी) संगोष्ठियों, चर्चा बैठकों, और नीति सार पत्रों सहित प्रकाशनों के ज़रिये विकास सहयोग नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी बढ़ाने की दिशा में काम करता है। लेकिन चूंकि एफआईडीसी की अधिकतर संगोष्ठियां और सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित होते थे, इसलिए इस आशय के सुझाव आते रहते थे कि एक प्लेटफ़ार्म मंच की हैसियत से एफआईडीसी का विस्तार किया जाना चाहिए और फ़ोरम के रूप में उसकी पहुंच को दूसरे शहरों तक फैलाया जाना चाहिए। इस धारणा को आगे बढ़ाते हुए 10–11 फ़रवरी, 2015 के बीच पुणे और 23–24 मार्च को कोलकता में विकास सहयोग पर क्षेत्रीय परामर्श सभाएं आयोजित हुई। सिंबायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और कलकत्ता विश्वविद्यालय, क्रमशः पुणे और कोलकाता के लिए क्षेत्रीय परामर्श के भागदारी संस्थान थे।

इन विचार–विमर्श सभाओं में शिक्षाविदों, नागर समाज संस्थाओं, उद्योगों के प्रतिनिधियों, निजी क्षेत्र और नीति निर्मातओं सहित अनेक भागीदार जमा हुए और दक्षिण–दक्षिण सहयोग (एसएससी) पर उनकी वचनबद्धता पर चर्चा को साकार किया। विकास सहयोग पर पहली परामर्श बैठक सिंबोयसिस यूनिवर्सिटी, पुणे में आयोजित हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ सिंबोयसिस यूनिवर्सिटी, पुणे के कुलाधिपति डॉ. एसबी मजूमदार और आरआईएस के महानिदेशक प्राध्यापक सचिन चतुर्वेदी के स्वागत भाषण से हुआ। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (डीपीए–II) श्री कुमार तुहिन ने उद्घाटन भाषण दिया। किर्लोस्कर ब्रदर्स लि. के अध्यक्ष–सह प्रबंध निदेशक श्री संजय किर्लोस्कर ने मुख्य वक्तव्य दिया। सिंबोसिस, पुणे की प्रधान निदेशक डॉ. विद्या येरावदेकर ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस परामर्श बैठक में विकास सहयोग को बढ़ावा देने के साधन के रूप में उच्च शिक्षा और क्षमता

(बाएं से दाएं) डॉ. विद्या येरावडेकर, प्रमुख निदेशक सिम्बायोसिस, पुणे, प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, श्री संजय किर्लोस्कर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड, डॉ. एसबी मजूमदार, कुलपति, सिम्बायोसिस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, पुणेय श्री कुमार तुहिन, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, और डॉ. ज्योति चंडीरमानी, डीन, मानविकी और सामाजिक विज्ञान, सिम्बोसिस अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, पुणे में एफआईडीसी क्षेत्रीय परामर्श में भाग लेते हुए।

निर्माण की भूमिका सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। चूंकि विचार–विमर्श का केंद्र व्यापार सहयोग में नागरिक समाज की जुड़ाव के रहस्य को तोड़ना था इसलिए भारत और भारत के बाहर अनेक क्षेत्रों में काम कर रही नागरिक समाज संस्थाओं के अनुभवों और सफलता की कहानियों की बाबत तरह–तरह के विचार जुटाने के लिए विकास सहयोग पर समांतर सत्रों का आयोजन किया गया।

दूसरे चक्र की परामर्श बैठक कलकत्ता विश्वविद्यालय के विदेश नीति अध्ययन संस्थान के सहयोग से आयोजित हुई। सभा का शुभारंभ कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति प्राध्यापक सुरंजनदास के स्वागत भाषण से हुआ। पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकता के उच्चशिक्षा विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री श्री पार्थ चटर्जी ने उद्घाटन भाषण दिया। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (डीपीए ।) श्री आलोक के. सिन्हा ने मुख्य विंदुओं पर प्रकाश डाला। आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। जहां पुणे की परामर्श बैठक में हुए समांतर सत्रों में नागरिक समाजों और विकास सहयोग पर सर्वसमावेशी चर्चाएं हुईं वहीं कोलकता के सत्र अधिक विशिष्ट थे और क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्षेत्र आधारित विकास संबंधी हस्तक्षेपों और परियोजना की डिज़ाइन तैयार करने और मूल्यांकन की निगरानी सहित तीन प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित थे। विशेष सत्र 'शिक्षा और दक्षिण–दक्षिण सहयोग' की गतिशीलता पर केंद्रित था और उसमें दक्षिण–दक्षिण सहयोग में प्राथमिक शिक्षा की भूमिका पर बल दिया गया।

क्षेत्रीय परामर्श बैठकें भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक भागीदारों के बीच दक्षिण–दक्षिण सहयोग की धारणा के प्रसार में सफल रहीं। इसे स्वीकार किया गया कि सीएसओ की डायरेक्टरी की टेंपलेट 'प्रोफ़ाइल ऑफ़ इंडियन वालंटरी ऑर्गनाइज़ेशन्स' को और संक्षिप्त लेकिन अधिक सूचना परक बनाने के लिए उसमें संशोधन करने की ज़रूरत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि क्षेत्रीय परामर्श बैठकों के चलते देश के विभिन्न क्षेत्रों की समाजिक संस्थाओं का एक संजाल तैयार हो गया है। क्षेत्रीय परामर्श बैठकों के मुख्य सुझाव हैंः विकासशील देशों में नागर समाज संस्थाओं के सफल हस्तक्षेपों के अध्ययनों को समेटते हुए एफआईडीसी के नीति सारों की श्रृंखला जारी की जाएगी। सीएसओ सदस्यों के सुझावों को शामिल करते हुए सीएसओ की डायरेक्टरी का नवीनीकरण किया जाएगा। क्षेत्रीय परामर्श बैठकों से उभर कर आए अनेक पहलुओं के समाधान के लिए एफआईडीसी की उप–समिति का गठन किया जाएगा। आगे चल कर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी की योजना बनाई जा सकती है जिसमें सभी क्षेत्रों के सीएसओ (नागर समाज संस्थाएं) भाग लेंगे और व्यक्तिगत अनुभवों की चर्चा करेंगे।

जी. पार्थसारथी और आरआईएस पर विशेष व्याख्यान

आरआईएस ने जी. पार्थसारथी के जन्मशती वर्ष में 16 अक्तूबर 2014 को नई दिल्ली में 'जी. पार्थसारथी और आरआईएस' पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया। जी. पार्थसारथी ने विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक और उल्लेखनीय काम किए। वह विकासशील देशों के बीच विकास सहयोग को बढ़ावा देने के प्रति बहुत ही प्रतिबद्ध थे। 1980 के दशक के मध्य में आरआईएस का गठन, जिसके वह संस्थापक अध्यक्ष थे, एवम्

प्रो. वी. आर. पंचमुखी, आरआईएस के संस्थापक महानिदेशक और पूर्व अध्यक्ष, आईसीएसएसआर स्मारक व्याख्यान देते हुए। इसके अलावा तस्वीर में (बाएं से दाएं) प्रो. राम उपेंद्र दास, आरआईएस, राजदूत श्याम सरन, अध्यक्ष, आरआईएस, प्रो. अशोक पार्थसारथी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पूर्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सलाहकारय प्रो सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएसय और प्रो. एस. के. मोहंती, आरआईएस भी हैं।

दक्षिण–दक्षिण सहयोग के लक्ष्य को सुदृढ़ करने में उनका प्रमुख योगदान था। आरएसआई के संस्थापक महानिदेशक और भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिष्द के पूर्व चेयरमैन प्राध्यापक वी आर पंचमुखी ने इस अवसर पर विशेष व्याख्यान दिया। आरआईएस के चेयरमैन राजदूत श्याम सरन ने महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला। आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी, प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के पूर्व विज्ञान एवं टेक्नॉलॉजी सलाहकार प्रो. अशोक पार्थसारथी, आरआईएस के प्रो. राम उपेंद्र दास ने भी संगोष्ठी को संबोधित किया।

बौधिक संपदा नीति के मसविंदे पर परामर्श बैठक

बौधिक संपदा के पहले मसविदे पर बहस चलाने और उस पर टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए आरआईएस ने 16 जनवरी 2015 को परामर्श बैठक का आयोजन किया। आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया। औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान (आईएसआईडी) के प्रो. दिनेश कुमार अबरोल ने बैठक की अध्यक्षता की। आरआईएस के सलाहकार प्रो. टी सी जेम्स ने टिप्पणियां कीं। फ्रिज्टॉफ नैनसेन इंस्टीट्यूट, नार्वे के डॉ. बालकृष्ण पिसुपति और आरआईएस के सलाहकार डॉ. के. रवि श्रीनिवास ने भी चर्चा में भाग लिया। आरआईएस के उपाध्यक्ष राजदूत वी एस शेषाद्रि; आरआईएस के प्रो. एसके मोहंती; आरआईएस के प्रो. राम उपेंद्र दास; आरआईएस के सहायक प्रोफेसर डॉ. सब्यसाची साहा; आरआईएस के श्री मिलिंदो चक्रवर्ती; थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क (टीडब्लूएन) के स्कूल ऑफ़ सोशल साइन्सेज़ (जेएनयू) के कानूनी सलाहकार और वरिष्ठ शोधकर्ता श्री के एम गोपकुमार; विज्ञान नीति अध्ययन केंद्र (सीएसएसपी) के अध्यक्ष प्रो. पी एन देसाई; डॉ. वी वी कृष्णनन सीएसएसपी, जेएनयू; भारतीय चिकित्सा शोध परिषद (आईसीएमआर) के उप–महानिदेशक डॉ. के. सत्यनारायण; टीईआरआईके डॉ नित्यानंद; और एसकेएस ला असोसिएट्स की सुश्री सुनीता श्रीधरन ने चर्चा में भाग लिया।

प्रो सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस आईपी नीति के पहले मसौदे पर चर्चा में भाग लेते हुए।

विज्ञान और राजनय पर एफआईडीसी की संगोष्ठीः एक भारतीय प्ररिप्रेक्ष्य

जनवरी 2015 में फ़ोरम फ़ॉर इंडियन डेवलपमेंट कोऑपरेशन (एफआईडीसी) ने अपने गठन के दो सफलतापूर्ण वर्ष पूरे किये। भारतीय विकास सहयोग के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल करना एफआईडीसी का उद्देश्य है। यह फ़ोरम शिक्षाविदों, नागरिक समाज और नीति निर्माताओं को एक साथ लाता है। योजना दक्षिण–दक्षिण सहयोग की व्यापक प्रवृत्तियों के विस्तृत विष्लेशण को प्रोत्साहन देने और विभिन्न विषयों और हितधारकों के आरपार चर्चा को सुगम बनाकर भारतीय नीतियों का प्रासंगिकीकरण करने की है। एफआईडीसी की दूसरी वर्षगांठ मनाने के लिए आरआईएस ने 13 जनवरी 2015 को 'विज्ञान राजनयः भारतीय परिप्रेक्ष्य' पर पंद्रहवीं एफआईडीसी

प्रो सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस स्वागत भाषण देते हुए। इसके अलावा चित्र में (दाईं से बाएं) सुश्री सुजाता मेहता, सचिव (एम एंड ईआर), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, प्रो. टी रामासामी, पूर्व सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, और डॉ आरबी ग्रोवर, निदेशक, होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान भी देखे जा सकते हैं।

संगोष्ठी का आयोजन किया। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पूर्व सचिव डॉ. टी. रामाराव मुख्य वक्ता थे। संगोष्ठी की अध्यक्षता भारत सरकार की (एम और ईआर) सचिव सुश्री सुजाता मेहता ने की। संगोष्ठी के बाद एक खुला सत्र चला जिसमें विशिष्ट भागीदारों की मूल्यवान टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं, जिनमें भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (एमईआर) श्री चरणजीत सिंह; वायु शक्ति अध्ययन केंद्र (सीएआईपीएस) के राजदूत शीलकांत शर्मा; जेएनयू के प्रो पी एन देसाई; जेएनयू की प्रो मधुबाला रेंतला; और भारत सरकार के विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग (डीएसटी) की वैज्ञानिक 'जी' डॉ. साधना रेलिया शामिल थीं। मुख्य वक्ताओं में डॉ. आरबी ग्रोवर होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई के निदेशक, राजदूत सौरभ कुमार, भारत की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के फ़ेलो और ईएमपीआई, नई दिल्ली के उपाध्यक्ष (शोध और अकादमीय विकास) डा. अशोक जैन शामिल थे।

आसियान–भारत रणनीतिक भागीदारी पर आसियान प्रतिनिधियों के साथ अन्तःक्रियात्मक सत्र

आरआईएस ने 13 मार्च 2015 को नयी दिल्ली में आसियान–भारत रणनीतिक भागीदारी, पर आसियान प्रतिनिधियों के साथ अन्तःक्रियात्मक सत्र का आयोजन किया। आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत टिप्पणियां कीं। आरआईएस के उपाध्यक्ष राजदूत वी एस शेषाद्रि और आसियान में भारतीय राजदूत सुरेश रेड्डी ने विशेष टिप्पणियां कीं। उसके बाद सांस्कृतिक संयोजकता, साफ़्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यापार और निवेश, उत्पादन नेटवर्कों इत्यादि के विशेष हवाले के साथ आसियान–भारत आर्थिक संबंधों के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की गई। आसियान के उप–महासचिव श्री वी पी हिरुबालन ने भी बैठक में भाग लिया। आरआईएस के आसियान–भारत केंद्र के संयोजक प्रो प्रबीर डे और राजदूत वी एस शेषाद्रि ने भाषण दिए। प्रो. प्रबीर डे ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा।

प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस स्वागत भाषण देते हुए। तस्वीर में (बाएं से दाएं) प्रो. प्रबीर डे, राजदूत वी एस शेषाद्री, और राजदूत सुरेश रेड्डी, आसियान में भारतीय राजदूत।

भारत–चीन आर्थिक सम्बन्ध पर चर्चा सत्र

आरआईएस ने 27 सितंबर 2014 को नई दिल्ली में भारत–चीन आर्थिक अनुबंध पर एक विचारोत्तेजक सत्र का आयोजन किया। यह चर्चा सत्र आरबीआई प्रायोजित आरआईएस अध्ययन ''भारत–चीन द्विपक्षीय व्यापार संबंध'' पर प्रो. एस के मोहंती के मुख्य प्रस्तुतिकरण के गिर्द आयोजित हुआ था। विशिष्ट वक्ताओं में आरआईएस के प्रो. एस के मोहंती; जेएनयू की प्रो. सुनंदा सेन और आरआईएस के प्रो. मनमोहन अग्रवाल शामिल थे।

भारत–म्यांमार के बीच के संयोजकता गलियारों का विकास गलियारों में रूपांतरण

आरआईएस के उपाध्यक्ष राजदूत वी एस शेषाद्रि की रिपोर्ट 'भारत–म्यांमार के बीच के संयोजकता गलियारों का विकास गलियारों में रूपांतरण' का विमोचन 14 अगस्त 2014 को नई दिल्ली में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की सचिव (ईआर और डीपीए) सुश्री सुजाता मेहता ने किया। उन्होंने भारत सरकार के मानननीय विदेश राज्य मंत्री जनरल वी. के. सिंह की अनुपस्थिति में उनका संदेश पढ़ा। आरआईएस के चेयरमैन राजदूत श्याम सरन ने स्वागत भाषण दिया।

प्रो. राम उपेंद्र दास, आरआईएस 14 अगस्त 2014 को नई दिल्ली में विकास गलियारों में भारत और म्यांमार के बीच कनेक्टिविटी कॉरीडोर्स को रूपांतरित करने वाली रिपोर्ट को जारी करने के मौके पर अपनी बात रखते हुए। तस्वीर में (बाएं से दाएं) राजदूत वी. एस. शेषाद्री, राजदूत श्याम सरन, और सुश्री सुजाता मेहता, सचिव (ईआर और डीपीए), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार भी नजर आ रहे हैं।

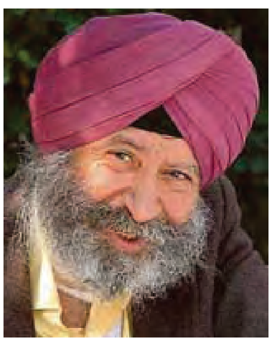

प्रो. अजित सिंह आरआईएस में

आरआईएस ने जलवायु परिवर्तन और एक नए समाज की भूमिका पर 15 नवंबर 2014 को नई दिल्ली में एक संगोष्ठी का आयोजन किया। कैंब्रिज विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के इमेरिटस प्रोफ़ेसर डा. अजित सिंह मुख्य वक्ता थे। आरआईएस के प्रो. एस के मोहंती ने संगोष्ठी की अध्यक्षता की। आरआईएस के महानिदेशक प्रो सचिव चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया। आब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन के संसाधन प्रबंधन केंद्र की मुखिया सुश्री लीडिया पॉवेल ने चर्चा में भाग लिया।

आसियान–भारतः प्रतिष्ठित व्यक्तियों के व्याख्यान

आसियान–भारत प्रतिष्ठित व्यक्तियों की व्याख्यान माला के अंग के रूप में आरआईएस ने विदेश मंत्रालय और आसियान सचिवालय के सहयोग से 12 अगस्त 2014 को नई दिल्ली में वियतनाम एकैडमी ऑफ़ सोशल साइंसेज़ (वीएएसएस) के अध्यक्ष प्रो. न्गुयेन ज़ुआन थांग का व्याख्यान आयोजित किया। आरआईएस के अध्यक्ष राजदूत श्याम सरन ने स्वागत टिप्पणियां कीं। प्रो न्गुयेन ज़ुआन थांग का दूसरा भाषण 13 अगस्त 2014 को आरआईएस के आसियान–भारत केंद्र द्वारा कंफ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई), इंडियन काउंसिल ऑफ़ कल्चरल रिलेशन्स (आईसीसीआर) और मौलाना अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ़ एशियन स्टडीज़ (एमएकेएआईएएस) के संयुक्त तत्वावधान में 13 अगस्त 2014 को कोलकाता में आयोजित हुआ। भारत के पूर्व विदेश सचिव राजदूत कृष्णन श्रीनिवासन ने उद्घाटन टिप्पणियां कीं और आरआईएस के आसियान–भारत केंद्र के संयोजक प्रो प्रबीर डे ने स्वागत भाषण दिया। सीआईआई पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता के पूर्व चेयरमैन श्री आलोक मुखर्जी ने भी समारोह को संबोधित किया।

नयी राजनीतिक स्थिति और आर्थिक व्यवस्था पर भाषण देते माननीय प्रो. नुयेन सुआन थैंग, अध्यक्ष, वियतनाम अकादमी ऑफ सोशल साइंसेस (वीएएसएसएस)।

एशिया में नयी राजनीतिक स्थिति और आर्थिक व्यवस्था पर भाषण देते माननीय प्रो. नुयेन सुआन थैंग।

एलएमओ के सामाजिक–आर्थिक मूल्यांकन के लिए दिशा–निर्देष और कार्यप्रणालियां विकसित करने पर मंत्रणा बैठक

आरआईएस और भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मिलकर 15 जुलाई 2014 को नई दिल्ली में एलएमओ के सामाजिक–आर्थिक मूल्यांकन के लिए दिशा–निर्देश और कार्यप्रणालियां विकसित करने के लिए मंत्रणा बैठक आयोजित की। आरआईएस के चेयरमैन राजदूत श्याम सरन ने स्वागत टिप्पणियां कीं। मंत्रालय की निदेशक डॉ. रंजिनी वारियर ने यूएनईपी परियोजना का परिचय दिया। आरआईएस के प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने परियोजना का संक्षिप्त परिचय दिया। भारत सरकार के विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रोद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के सलाहकार डॉ. एसआर राव ने प्रस्तावना भाषण दिया। इस आयोजन के चार सत्र चले जिनमें औरों के अलावा चर्चा करने वालों में सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन संस्थान (आईएसईसी) बंगलौर के भारतीय कृषि शोध परिष्द के नेशनल प्रोफ़ेसर डॉ. पीजी चेन्गप्पा; एनएसएआई, नई दिल्ली के महानिदेशक श्री संजय कुमार श्रीवास्तव; जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के विज्ञान नीति अध्ययन केंद्र (सीएसएसपी) के प्राध्यापक प्रणव एन. देसाई; ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टीईआरआई) की डॉ. निधि पी. चानना; येल विश्वविद्यालय के श्री अनिकेत आगा; आरआईएस के डॉ. के. रवि श्रीनिवास शामिल थे। कार्यक्रम का विस्तृत ब्योरा आरआईएस की वेब साइट पर उपलब्ध है।

डॉ . रांजिनी वारियर, निदेशक, एमओईएफ सामाजिक–आर्थिक आकलन के लिए दिशानिर्देषों और तरीकों को विकसित करने पर परामर्षदात्री बैठक में यूएनईपी परियोजना का परिचय देते हुए। तस्वीर में इसके अलावा प्रो. सचिन चतुर्वेदी और डॉ एस आर राव, सलाहकार, डीबीटी भी नजर आ रहे हैं।

पुनरुत्पादक औषधियां और भारत में रोगियों की आवश्यकताओं के अभिशासन पर गोल मेज

आरआईएस ने ससेक्स विश्वविद्यालय और डिपार्टमेंट ऑफ़ ईस्ट एशियन स्टडीज़ के साथ मिल कर 2 जुलाई 2014 को नई दिल्ली में पुनरुत्पादक औषधियों और रोगियों की जरूरतों के अभिशासन पर गोल मेज का आयोजन किया। दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के पूर्व एशियाई अध्ययन विभाग की प्रो. श्रीमती चक्रवर्ती ने सत्र की सदारत की और आरआईएस के प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण

दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ़ ससेक्स, यूके के डॉ. प्रसन्ना के. पात्रा ने सत्र की विषय वस्तु का परिचय दिया। चर्चा में भाग लेने वालों में दूसरों के अलावा आईसीएमआर के पूर्व वरिष्ठ उपमहानिदेशक वसंत मुत्तू स्वामी; न्यूरोजेन, मुंबई की उपनिदेशक डॉ. नंदिनी गोकुल चंद्रन; भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के प्राध्यापक पीबी शेशागिरि शामिल थे। आरआईएस के डॉ. रवि श्रीनिवास ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

प्रो. स्रीमती चक्रबर्ती, पूर्व एशियाई अध्ययन, दिल्ली विश्वविद्यालय गोलमेज परिषद में भाषण देते हुए। तस्वीर में (बाएं से दाएं) डॉ. प्रसन्ना के पात्रा, ससेक्स विश्वविद्यालय, यूके, डॉ. वसंत मुथुस्वामी, पूर्व वरिश्ठ उप महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् और प्रो सचिन चतुर्वेदी, आरआईएस भी नजर आ रहे हैं।

सीमा पार संयोजकता पर अंतरराश्ट्रीय सम्मेलन

आरआईएस ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ मिल कर 12 मई 2014 को नई दिल्ली में सीमा पार संयोजकता पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। आरआईएस के चेयरमैन राजदूत श्याम सरन ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) राजदूत अनिल वाधवा ने

राजदूत अनिल वाधवा, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार सीमा पार कनेक्टिविटी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रमुख भाषण देते हुए।

सम्मेलन के महतत्त्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला। अग्रणी नीतिकारों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों; शिक्षाविदों और विश्व बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाषण दिए। सम्मेलन के वक्ताओं में दूसरों के अलावा यूएस ट्रेस ऐंड डेवलपमेंट एजेंसी इंटरनेशनल कांफ्रेंस ऑन क्रॉस बार्डर कनेक्टिविटी (यूएसटीडीए), वाशिंगटन–डीसी के दक्षिण और दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय निदेशक श्री हेनरी स्टिंगास; अमरीका के विदेश विभाग के दक्षिण और मध्य एशियाई कार्य ब्यूरो की उप सहायक सचिव सुश्री फ़ातेमा सुमार; जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जीआईसीए), टोकियो के दक्षिण एशिया विभाग के भारत और भूटान के उप महानिदेशक और निदेशक श्री कात्सुओ मात्युमोटो शामिल थे। प्रो. प्रबीर डे ने सम्मेलन का संयोजन किया। सम्मेलन की विस्तृत कार्यसूची आरआईएस की वेब साइट पर उपलब्ध है।

आसियान–भारत पर गमन परिवहन अनुबंध पर गोलमेज

आरआईएस के आसियान– भारत केंद्र और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने मिलकर में आसियान–भारत पारगमन परिवहन अनुबंध (एआईटीटीए) पर 16 अप्रैल 2014 को नई दिल्ली में एक गोलमेज बैठक का आयोजन किया। आरआईएस के उपाध्यक्ष राजदूत वी एस शेषाद्रि ने उद्घाटन भाषण दिया और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) अनिल वाधवा ने महत्त्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। आरआईएस के आसियान–भारत केंद्र के संयोजक प्रो. प्रबीर डे ने मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला। इस विमर्श में विदेश मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नौकायन मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और योजना आयोग के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। असम, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, नगालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस गोल मेज में भाग लिया। विस्तृत कार्यक्रम आरआईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

राजदूत अनिल वाधवा, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार आसियान–भारत ट्रांजिट परिवहन समझौते पर गोलमेज परिषद् में प्रमुख भाषण देते हुए।

भारत–चीन संबंधों पर कार्यशाला

आरआईएस ने भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मद्रास के साथ मिलकर 17 दिसंबर 2014 को चेन्नई में भारत–चीन संबंधों पर कार्यशाला आयोजित की। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की सचिव (ईआर और पीपीए) सुश्री सुजाता मेहता ने कार्यशाला का उद्‌घाटन किया। आईआईटी– मद्रास के प्रो भास्कर रामामूर्ति; आरआईएस के महानिदेशक प्रो सचिन चतुर्वेदी; आईआईटी मद्रास के ह्यूमैनिटीज़ ऐंड सोशल साइंसेज़ विभाग (एचएसएस) की प्रमुख प्रो डी. मालती ने स्वागत भाषण दिए। सुश्री सुजाता मेहता ने भारत–चीन के बीच व्यापारः समस्याएं और संभावनाएं पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता की जिसमें आरआईएस के प्रो एसके मोहंती मुख्य वक्ता थे। एक्सिम बैंक के मुख्य महा प्रबंधक सैमुएल जोसफ़ और आईआईटी–मद्रास के एचएसएस विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. एस. सुभाष ने चर्चा में हिस्सा लिया। दूसरे सत्र में भारत और चीन में सार्वजनिक स्वास्थ्य, व्यापार, परंपरागत औषधि पर चर्चा की गई। तीसरा सत्र चीन में शहरी विकास और आवास और भारत के लिए सबक़ पर आयोजित हुआ। मुख्य वक्ताओं में आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी; आईआईटी–मद्रास के ह्युमैनिटीज़ ऐंड सोशल साइन्सेज़ (एचएसएस) विभाग के प्रो वीआर मुरलीधरन; और आईआईटी–मद्रास के एचएसएस विभाग के एसोशिएट प्रोफेसर डॉ. सोलोमन जे. बेंजामिन शामिल थे।

प्रो सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस स्वागत भाषण देते हुए। तस्वीर में (बाएं से दाएं) दिखाई : सुश्री सुजाता मेहता, सचिव (ईआर और डीपीए), विदेश मंत्रालय, प्रो भास्कर रामामूर्ति, निदेशक आईआईटी–मद्रास, डॉ. बालकृष्ण पिसुपति, और प्रो.एस.के. मोहंती, आरआईएस।

न्यू डेवलपमेंट बैंक और दक्षिण–दक्षिण सहयोग पर संगोष्ठी

आरआईएस और इंडियन डेवलपमेंट कारपोरेशन (एफआईडीसी) ने 3 सितंबर 2014 को नई दिल्ली में न्यू डेवलपमेंट बैंक और दक्षिण–दक्षिण सहयोग पर संगोष्ठी आयोजित की। आरआईएस के चेयरमैन राजदूत श्याम सरन ने संगोष्ठी की सदारत की। अग्रणी वक्ताओं में राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) के निदेशक डॉ. रथिन रॉय; भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री चरनजीत सिंह; और ऑक्सफ़ाम इंडिया की सुश्री पूजा पार्वती शामिल थीं। नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक श्री अमिताभ बेहर ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

श्री चरनजीत सिंह, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय नए विकास बैंक और दक्षिण–दक्षिण सहयोग पर एफआईडीसी सेमिनार में भाषण देते हुए।

उत्तर–2015 विकास कार्यसूचीः एक भारतीय परिप्रेक्ष्य

आरआईएस ने एफआईडीसी संगोष्ठी माला के अंतर्गत 11 अप्रैल 2014 को नई दिल्ली में उत्तर–2015 विकास कार्यसूचीः एक भारतीय प्ररिप्रेक्ष्य पर संगोष्ठी आयोजित की। आरआईएस के महानिदेशक प्रो. विश्वजीत धर ने संगोष्ठी की अध्यक्षता की। प्रमुख वक्ताओं में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (यूएनईएस) श्री तन्मय लाल, और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (डीपीए–II) श्री कुमार तुहिन शामिल थे।

श्री तन्मय लाल, संयुक्त सचिव (यूएनईएस), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार अपनी बात रखते हुए।

एलएमओ के सामाजिक–आर्थिक मूल्यांकन के लिए दिशा–र्निदेश और कार्य प्रणालियां विकसित करना

आरआईएस ने सामिजिक–आर्थिक परिवर्तन संस्थान (आईएसईसी), बैंगलोर के सहयोग से 11–12 दिसंबर 2014 को आईएसईसी, बैंगलौर में एलएमओ के सामाजिक–आर्थिक मूल्यांकन के लिए दिशा–निर्देश और कार्य प्रणालियां विकसित करने पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की निदेशक और राष्ट्रीय परियोजना संयोजक डॉ रंजिनी वारियर ने पहले दिन की कार्यशाला की सदारत की। आईएसईसी के प्रो पीजी चेंगप्पा ने कार्यशाला के भागीदारों का स्वागत किया। आरआईएस के महानिदेशक प्रो सचिन चतुर्वेदी ने कार्यशाला के उद्देश्यों को रेखांकित करके उसकी कार्यसूची तय की। उन्होंने सामाजिक–आर्थिक मूल्यांकन और लागत–लाभ विश्लेषण दोनों के लिए भागीदार संस्थानों द्वारा किये जाने वाले कामों का उल्लेख किया। आरआईएस के सलाहकार डॉ. के. रवि श्रीनिवास ने इस विषय के साहित्य की गहन समीक्षा से उभर कर आए प्रमुख मुद्दों को रेखांकित करके दिशा–निर्देश दस्तावेज़ में आरआईएस के चल रहे कार्य पर व्याख्यान दिया।

आरआईएस के शोध सहयोगी श्री अमित कुमार ने विशेष रूप से लागत–लाभ विष्लेशण (सीबीए) पर किए गए अध्ययनों पर प्रस्तुतिकरण दिया। भारतीय कृषि शोध अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर), रायपुर के डॉ. टीपी राजेंद्रन ने कार्यशाला के दूसरे दिन की अध्यक्षता की। इस कार्यशाला में परियोजना के सभी भागीदार संस्थानों और विदेशी विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। दूसरों के अलावा भागीदारों में आईआरएस के प्रो मनमोहन अग्रवाल, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के प्रो हरिबाबू; राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी (एनएएआरएम), हैदराबाद के डॉ. के. श्रीनिवास; तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय (टीएनएयू), कोयंबटूर के डॉ. के आर अशोक; कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (यूएएस), रायचूर के डॉ. सुरेश पाटिल; यूएएस रायचूर के डॉ. रेड्डी; भारतीय कृषिशोध संस्थान (आईएआरआई), नई दिल्ली के डॉ. आरएन पडारिया; गुजरात विकास शोध संस्थान (जीआईडीआर), अहमदाबाद की डॉ ललिता; आईएसईसी, बंगलौर के डॉ. मंजूनाथ और आईएसईसी, बंगलौर के डॉ. एलुमलाई ने भाग लिया।

आईएसईसी बैंगलौर में एलएमओ के सामाजिक–आर्थिक आकलन के लिए दिशानिर्देश और तरीकों पर कार्यशाला के प्रतिभागी।

दक्षिण–दक्षिण सहयोग (एएएससी) पर प्रो. वीआर पंचमुखी का व्याख्यान

निकट अतीत में भारतीय विकास सहयोग नीति के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा और ज्ञानसंपन्न बहस चलाने के लिए आरआईएस ने 2013 में फ़ोरम फ़ॉर इंडियन डेवलपमेंट कोऑपरेशन (एफआईडीसी) की शुरुआत की थी। एफआईडीसी की मासिक संगोष्ठी माला के अंतर्गत 17 अक्तूबर 2014 को नई दिल्ली में 'दक्षिण–दक्षिण सहयोगः अतीत से प्रतिबिम्ब' का आयोजन किया गया। आरआईएस के महानिदेशक सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया। यूनाइडेट नेशन्स हाई कमिश्नर फ़ॉर रिफ़्यूजीज़, नई दिल्ली के मिशन प्रमुख श्री डोमिनिक बार्श ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। आरआईएस के पूर्व महानिदेशक प्रो. वी आर पंचमुखी ने व्याख्यान दिया। इंटरनेशनल एकैडमिक फ़ैसिलिटेशन के निदेशक और स्कूल ऑफ़ लॉ ऐंड स्कूल ऑफ़ बिज़नेस स्टडीज़, शारदा विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉ. मिलिंदो चक्रवर्ती ने चर्चा में भाग लिया। आरआईएस के शोध सहायक श्री प्रत्यूश ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा।

प्रो. वी. आर. पंचमुखी व्याख्यान देते हुए। तस्वीर में निम्न लोग (बाएं से दाएं) दिखाई दे रहे हैंः श्री डोमिनिक बार्ट्ज, मिशन के प्रमुख, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त, नई दिल्ली, प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, और प्रो. अशोक पार्थसारथी।

आरआईएस में संयुक्त राज्य की कांग्रेस के कर्मचारियों का आगमन

2010 में भारत और संयुक्त राज्य अमरीका ने यूएस म्यूचुअल एडुकेशनल ऐंड कल्चरल एक्सचेंज ऐक्ट (एमईसीईए) के अंतर्गत भारत सरकार को कांग्रेस के सदस्यों, कांग्रेस के कर्मचारियों और संधीय प्रशासनिक अधिकारियों सहित संयुक्त राज्य के संघीय कर्मचारियों को भारत में अमरीकी आगंतुक कार्यक्रम के (यूएसवीआईपी) के तहत भारत आने का न्योता देने का अधिकार प्रदान करने वाला अनुबंध किया था। प्रभावशाली यूएस कांग्रेस (अमरीकी विधायिका) में भारत के प्रति मित्रतापूर्ण समूह के सृजन और सीनेट फ़ॉरेन रिलेशंस कमेटी (विधायिका के ऊपरी सदन) और हाउस फ़ॉरेन अफ़ेयर्स कमेटी (निचले सदन) में अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर नीति निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। इस कार्यक्रम के अंग के रूप में 16 दिसंबर 2014 को अमरीकी संसद के 10 कर्मचारी आरआईएस में आए थे। इस शिष्टमंडल के सदस्यों में सीनेटॅर मार्क बार्नर (डी–वीए) (को–चेयर ऑफ़ सीनेट इंडिया कॉकस) के वरिष्ठ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री मार्क रॉलिंस; रेप.

जोय क्रॉली (डी–एनवाई) की संचार निदेशक, वाइस चेयर ऑफ़ डेमोक्रेटिक कॉकस तथा को–चेयर ऑफ़ क्रांग्रेशनल कॉकस ऑन इंडिया ऐंड इंडियन अमेरिकन्स सुश्री कूर्टनी गिंडर बैकमेयर; हाउस रूल्स कमेटी के सलाहकार श्री नील जेरार्ड जोर्कमैन; रेप. जॉर्ज होल्डिंग (आरएनसी) के वरिष्ठ विधायी सहायक श्री क्रिस्टोफ़र माइकेल डेंज़ेल; हाउस ओवरसाइट कमेटी के मुख्य सलाहकार श्री अशोक माइकेल पिंटो; हाउस कमेटी ऑन फ़ॉरेन अफ़ेयर्स के व्यावसायिक सदस्य श्री सजित गांधी; रेप. डेव रीचर्ट (आरडब्लूए) की विधायी सहायक सुश्री नेताली ग्रेस कैंफॉस; हाउस मेजॉरिटी लीडर रेप. केविन मैकार्थी (आरसीए) की वरिष्ठ नीति सलाहकार सुश्री एमिली हेनेहन मुरी; रेप. एड रॉयस (आरसीए) के डिप्टी चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ श्री पीटर जेसन फ्रीमैन; हाउस सब कमेटी ऑन कामर्स, मैन्युफ़ैक्चरिंग, ऐंड ट्रेड की मुख्य परामर्शदाता सुश्री मिशेल होप ऐश शामिल थीं। आरआईएस के उपाध्यक्ष राजदूत वी एस शेषाद्रि ने बैठक की अध्यक्षता की। आरआईएस के प्रो. एसके मोहंती; प्रो. मनमोहन अग्रवाल, कन्सल्टेंट; विजिटिंग फेलो डॉ.एन चंद्र मोहन; सलाहकार श्री टीसी जेम्स; शोध सहयोगी डॉ बीना पांडे; सहायक प्राध्यापक डॉ. सब्यसाची साहा और निदेशक (एफऐंडए) श्री महेश सी. अरोड़ा ने बैठक में हिस्सा लिया।

भारत–अमरीका संबंधों पर पैनल चर्चा

आरआईएस ने 12 दिसंबर 2014 को नई दिल्ली में भारत–अमरीका संबंधों पर पैनल चर्चा आयोजित की। आरआईएस के प्रो. राम उपेंद्र की प्रस्तावना टिप्पणियों से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। चर्चा करने वालों में प्रमुख थे सीनियर फ़ेलो और यूएस–इंडिया पॉलिसी स्टडीज़ सेंटर फ़ॉर स्ट्रेटजिक ऐंड इंडरनेशनल स्टडीज़ (सीएसआईएस), वाशिंगटन डीसी के वाधवानी चेयर श्री रिचर्ड एम.रॉसो; ऑब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन (आरआरएफ), नई दिल्ली के लब्ध प्रतिष्ठित सदस्य डॉ. सी. राजामोहन; और समाज विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के निदेशक डॉ यश नारायण रॉय शामिल थे। अमेरिकन सेंटर नई दिल्ली की निदेशक सुश्री एमिली व्हाइट ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

प्रो. राम उपेंद्र दास, आरआईएस उदघाटन भाषण देते हुए। तस्वीर में निम्न लोग (बाएं से दाएं) हैं: सुश्री एमिली वाइट, निदेशक, अमेरिकन सेंटर, डॉ .सी. राजामोहन, विशिष्ट फेलो, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ), श्री रिचर्ड एम रोस्सो, वरिष्ठ फेलो, सीएसआईएस और अमेरिका–भारत नीति अध्ययन में वाधवानी चेयर, डॉ.ऐश नारायण राय, निदेशक, सामाजिक विज्ञान संस्थान, प्रो. राम उपेंद्र दास, आरआईएस, और प्रो एस.के. मोहंती, आरआईएस।

वैष्विक उत्पादन संजालों से जुड़ने पर आसियान–भारत संगोष्ठीः भारत के लिए अवसर और आसियान–भारत सहयोग

आरआईएस के एएसईएएन–इंडिया केंद्र ने आसियान–भारत संगोष्ठी माला के अंतर्गत 11 दिसंबर 2014 को नई दिल्ली में ''वैश्विक उत्पादन संजालों से जुड़नाः भारत के लिए अवसर और आसियान–भारत सहयोग'' पर संगोष्ठी आयोजित की। आसियान–भारत केंद्र के संयोजक प्रो. प्रबीर डे की स्वागत टिप्पणियों के साथ संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। आरआईएस के उपाध्यक्ष राजदूत वी एस शेषाद्रि ने संगोष्ठी की अध्यक्षता की। ऑस्ट्रेलिएन नेशनल यूनिवर्सिटी (एएनयू) कैनबेरा की प्राध्यापक प्रेमा–चंद्रा अतुकोरला ने मुख्य प्रस्तुतिकरण दिया, जिसके बाद खुला सत्र चला।

प्रो. प्रेमा चन्द्र अथुकोराला, एएनयू, कैनबरा प्रस्तुति करते हुए। तस्वीर में निम्न लोग (बाएं से दाएं) हैंः प्रो. एस के. मोहंती, आरआईएस, राजदूत वी .एस. शेषाद्री, और प्रो. प्रबीर डे।

आसियान–नीति एकीकरण प्रक्रिया, आरसीईपी, टीपीपी और एफटीएएपी के लिए संभावना पर पैनल चर्चा

आरआईएस ने 21 अक्तूबर 2014 को नई दिल्ली में आसियान–नीति एकीकरण प्रक्रिया, आरसीईपी, टीपीपी और एफटीएएपी के लिए संभावना पर पैनल चर्चा आयोजित की। वक्ता थेः इन्सटीट्यूट ऑफ़ साउथ–ईस्ट एशियन स्टडीज़ (आईएसईएएस) सिंगापुर के फ़ेलो और अग्रणी शोधकर्ता बसु दास और आरआईएस के प्रो राम उपेंद्र दास। आरआईएस के उपाध्यक्ष राजदूत वी एस शेषाद्रि ने पैनल चर्चा की अध्यक्षता की। आरआईएस के सलाहकार प्रो. टी सी जेम्स ने चर्चा में भाग लिया।

(दाएं से बाएं) डा. संचिता बसु दास, राजदूत वी.एस. शेषाद्री, प्रो राम उपेंद्र दास, प्रो .टी.सी. जेम्स और प्रो. एस के. मोहंती पैनल चर्चा में हिस्सा लेते हुए।

एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक पर पैनल चर्चा

आरआईएस ने 24 अक्तूबर 2014 को नई दिल्ली में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक पर पैनल चर्चा आयोजित की। आरआईएस के चेयरमैन राजदूत श्याम सरन ने चर्चा की अध्यक्षता की। अग्रणी वक्ताओं में इंडियन काउंसिल फ़ॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकॉनॉमिक रिलेशंस (आईसीआरआईईआर) के आरबीआई चेयर प्रोफ़ेसर और पूर्व राजदूत डॉ जेमिनी भगवती; और ब्रुकिंग्स इंडिया के निदेशक और भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व उप–गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण और अंतरराष्ट्रीय सहायता और विकास के स्वतंत्र सलाहकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक में रहे श्री श्याम वाजपेयी शामिल थे।

पेटेंट डेटाबेस सर्च टूल्स पर चर्चा

आरआईएस ने 4 दिसंबर 2014 को नई दिल्ली में पेटेंट डेटाबेस सर्च टूल्स पर चर्चा आयोजित की। आरआईएस के सलाहकार प्रो. टी सी जेम्स ने शोधकर्ताओं के पेटेंट डेटाबेस की खोज करने की वांछनीयता और आवष्यकता बताते हुए विषय का परिचय दिया। सिद्धहस्त इन्नोवेशन्स के श्री रोशन अग्रवाल एमडी ने निःशुल्क और मोल दोनों तरह के विभिन्न पेटेंट डेटाबेसेज़ और सर्च टूल्स पर विस्तृत भाषण दिया।

(बाएं से दाएं)राजदूत वी एस शेषाद्री, डॉ सुबीर गोकर्ण, निदेशक, ब्रूकिंग्स भारत और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर, राजदूत श्याम सरन और श्री श्याम बाजपेयी, स्वतंत्र सलाहकार, अंतरराष्ट्रीय सहायता और विकास एवं पूर्व में एशियाई विकास बैंक और प्रो सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस एशियाई बुनियादी निवेश बैंक पर पैनल चर्चा में हिस्सा लेते हुए।

आरआईएस की ब्रेकफ़ास्ट सेमिनार श्रृंखला

आरआईएस ने अक्तूबर 2014 में एक नई ब्रेकफ़ास्ट सेमिनार श्रृंखला शुरू की। इस प्रक्रिया का उद्देश्य युवा फ़ैकल्टी सदस्यों और कैरियर के शुरुआती दौर में शोध करने वालों को अपने शोध निश्कर्षों के प्रसार और चल रहे शोध कार्य पर चर्चा करने और विशेषज्ञों और समकक्षों से टिप्पणियां/प्रतिपुश्टियां पाने के लिए मंच प्रदान करना है। इस संगोष्ठी श्रृंखला का उपयोग अकादमीय और नीतिगत महत्व के विषयों पर बोलने के लिए अग्रणी विद्वानों को मंच प्रदान करने के लिए किया जाएगा। साथ ही साथ, इस श्रृंखला की अध्यक्षता के लिए विशिष्ट विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जाता है ताकि ये सत्र उनके अनुभव और विद्वता का लाभ उठा सकें। इन सत्रों को अन्तःक्रियात्मक बनाने के लिए कभी–कभी वरिष्ठ शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अभी तक निम्नलिखित संगोष्ठियां आयोजित हुई हैंः

आरआईएस की ब्रेकफ़ास्ट सेमिनार श्रृंखला (अक्टूबर 2014 में शुरू हुई)

संगोष्ठी तिथि	वक्ता	विषय	अध्यक्ष	चर्चा के भागीदार
09 अक्तूबर 2014	डॉ. बीना पांडे, शोध सहयोगी, आरआईएस	आईबीएसए में सामाजिक क्षेत्र की स्थिति	डॉ यश नारायण रॉव निदेशक, समाज विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	श्री विजय नरेश मेहता, सलाहाकार, बहुपक्षीय आर्थिक संबंध विभाग, विदेश मंत्रालय,
11 नवंबर 2014	डॉ. प्रियदर्शी दास, शोध सहयोगी, आरआईएस	एशिया में रिजर्व प्रबंधनः बदलते आकार और चुनौतियां	प्रो. बी बी भट्टाचार्य, पूर्व कुलपति, जेएनयू	डॉ सब्यसाची साहा, सहायक प्रोफेसर, आरआईएस
26 नवंबर 2014	डॉ सब्यसाची साहा, सहायक प्रोफेसर, आरआईएस	विश्वविद्यालय– उद्योग संवाद और प्रौद्योगिकी हस्तांतरणः भारतीय संदर्भ	डॉ अश्विनी गुप्ता भारत सरकार सलाहकार, डीएसआईआर	डॉ नित्यानंद, वरिष्ठ फेलो, टेरी
02 दिसंबर 2014	श्री अमित कुमार, शोध सहयोगी, आरआईएस	भारतीय विज्ञान और प्रौद्यगिकी नीति में आचार नीति और अभिगम, समानता और समावेशन के मुद्दे	डॉ राजेश्वरी रैना, प्रधान वैज्ञानिक, सीएसआईआर एनआईएसटीएडीएस	डॉ प्रवीण अरोड़ा, सलाहकार, भारत सरकार के विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग
09 दिसंबर 2014	श्री सुशील कुमार, सलाहकार, आरआईएस	इथोपिया के साथ भारत का विकास सहयोगः शक्कर उद्योग विशेष	प्रोफेसर एस के मोहंती, आरआईएस	प्रो. मनमोहन अग्रवाल, विज़िटिंग फ़ेलो, आरआईएस
29 जनवरी 2015	सुश्री श्रेया पान, शोध सहयोगी, आरआईएस	ट्रेडसिफ़्ट के साथ व्यापार विश्लेषण	प्रोफेसर राम उपेंद्रा दास, आरआईएस	
17 फ़रवरी 2015	प्रो. मिलिंदो चक्रवर्ती, विज़िटिंग फ़ेलो, आरआईएस	दक्षिण–दक्षिण सहयोग के मूल्यांकन में प्रक्रिया संबंधी समस्याएं	प्रो. मनमोहन अग्रवाल, विज़िटिंग फ़ेलो, आरआईएस	
3 मार्च 2015	श्री जयदेव दुबे, परामर्शदाता, आरआईएस	उत्पादकता व्यापार संबंधः भारत के विनिर्माण क्षेत्र के परिदृश्य	प्रोफेसर राम उपेंद्रा दास, आरआईएस	

बाहरी नीति संवाद में योगदान

प्रो. सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक

- 14 अप्रैल 2014 को मैक्सिको में दक्षिणी थिंक टैंकों के नेटवर्क की उद्‌घाटन बैठक में 'दक्षिणी थिंक टैंकों की भूमिका' पर प्रस्तुतिकरण दिया।
- 16 अप्रैल 2014 को मैक्सिको में प्रभावी विकास सहयोग के लिए वैश्विक भागीदारी की पहली उच्च स्तरीय बैठक में 'संस्थागत स्थापत्य और विकासः उभरती शक्तियों की अनुक्रियाएं' पर प्रस्तुतिकरण दिया।
- 9 मई 2014 को ब्रुकिंग्स इंडिया द्वारा आयोजित 'कार्यसूची निर्धारणः नई सरकार की विदेश नीति प्राथमिकताएं' पर पैनल चर्चा में भाग लिया।
- 24 जून 2014 को नई दिल्ली में 'ब्रिक्स (BRICS) ऐंड ग्लोबल हेल्थ' पर भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सहयोग पर डब्ल्यूएचओ आयोजित उच्चस्तरीय संगोष्ठी में भाग लिया।
- 25 जून 2014 को ओईसीडी द्वारा पेरिस में नया विकास वित्त परिदृश्यः साझीदार देशों के परिप्रेक्ष्य और उत्तर–2015 बहस के लिए निहितार्थ पर आयोजित सम्मेलन में 'विकास वित्तपोषण के पूरक संसाधन' पर व्याख्यान दिया।
- 26–27 जून 2014 को पेरिस में ओईसीडी–डीएसी द्वारा 'एड' (सहायता) की नई परिभाषा पर विशेषज्ञ संदर्भ समूह की बैठक में भाग लिया।
- समाज विज्ञान संस्थान द्वारा 7 जुलाई 2014 को नई दिल्ली में 'समावेशी विकासः छठे बीआरआईएस शिखर सम्मेलन के टिकाऊ समाधानः फ़ोर्टालेज़ा बैठक से अपेक्षाएं' विषय सत्र में 'ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समक्ष मुद्दे' पर भाषण दिया।
- संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक समाजिक परिषद् (ईसीओएसओसी), न्यूयार्क में 10–11 जुलाई 2014 को ''विकास सहयोग के भविष्य को उत्तर–2015 तक लाना'' विषय पर विकास सहयोग मंच (डीसीएफ) की चौथी द्विवर्षीय उच्चस्तरीय बैठक में 'दक्षिण–दक्षिण के सहयोग की गतिकी' पर भाषण दिया।
- 19 जुलाई 2014 को सीपीआर, आईसीआरआईआर,आईडीएफ, एनसीएईआर और एनआईपीएफपी–आईडीएफ द्वारा 'संघीय बजट 2014–2015 सुधार और विकास परिप्रेक्ष्य' विषय पर आयोजित बजट संगोष्ठी में भाग लिया।
- 21 जुलाई 2014 को ऑब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन (ओआरएफ) द्वारा 'दक्षिण–दक्षिण सहयोग का विखंडन' पर प्रस्तुतीकरण दिया।
- 14 अगस्त 2014 को नई दिल्ली में 'ऑब्ज़र्वर्स रिसर्च फ़ाउंडेशन' द्वारा '2015 के बाद के विकास कार्यक्रमः भारत और उससे परे के परिदृष्य' पर आयोजित सम्मेलन में 2015 के बाद के विकास कार्यक्रम के लिए सहयोग और भागीदारी सत्र में 'दक्षिणी परिदृष्य' पर भाषण दिया।
- वानी द्वारा 26–27 अगस्त 2014 को नई दिल्ली में 'दक्षिण–दक्षिण सहयोग' पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में 'भारत की विकास सहयोग नीति के परिदृष्य' पर व्याख्यान दिया।

- 30–31 अगस्त 2014 को नई–दिल्ली में औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान (आईएसआईडी) द्वारा 'ओपन सोर्स सीड सिस्टम' पर आयोजित कार्यशाला में 'बीज के क्षेत्र में भारत–अफ्रीकी सहयोग' पर व्याख्यान दिया।
- 2 सितंबर 2014 को चेन्नई में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा आयोजित एक्सेस ऐंड बेनेफ़िट शेयरिंग फ़ॉर प्रॉसेसिंग दि एप्लीकेशन्स की विशेषज्ञ समिति की उन्नतीसवीं बैठक में भाग लिया।
- यूएई के विदेश मंत्रालय द्वारा 2 सितंबर 2014 को चेन्नई में आयोजित इंडियन ओशन डायलॉग में 'ब्लू इकोनॉमीः इमर्जिंग ट्रेंड्स' पर व्याख्यान दिया।
- 5–7 सितंबर 2014 को नई दिल्ली में सामाजिक विकास परिषद् द्वारा वैश्विक शासन से परेः दक्षिण–दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहन और ब्रिक्स की भूमिका' पर आयोजित सम्मेलन में 'दक्षिण–दक्षिण सहयोगः भारतीय परिदृष्य' पर व्याख्यान दिया।
- 27–28 अक्तूबर 2014 को बीज़िंग में ह्यूमैनिटीज़ ऐंड डेवलपमेंट स्टडीज़ (सीओएसडी) और चाइना एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (सीएयू) द्वारा आयोजित बैठक में 'दक्षिण–दक्षिण सहयोगः थिंक टैंकों के समक्ष कार्य सूची' पर व्याख्यान दिया।
- 29 अक्तूबर 2014 को बीज़िंग में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा दक्षिणी थिंक टैंकों का संजाल' विषय पर आयोजित संगोष्ठी में अग्रणी वक्ता थे।
- आब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन और ज़ेईआईटी स्टिफ़्तुंग एबेलिन और जर्ड बूसेरिएस (हंबर्ग) द्वारा संयुक्त रूप से 30 अक्तूबर 2014 को नई दिल्ली में वैश्विक अभिशासन पर चौथे एशियाई फ़ोरम में '2015 के बाद की कार्यसूची और वैश्विक दक्षिण' पर हुई पैनल चर्चा में भाग लिया।
- 30 अक्तूबर 2014 को नई दिल्ली में क्लब ऑफ़ रोम द्वारा 'राजनीति और कार्रवाई में सुसंगति के लिए समस्त महत्त्वपूर्ण आवष्यकताओं के लिए भोजन सुनिश्चित करने' पर आयोजित वैश्विक सम्मेलन में 'खाद्य नीति और राजनीति' पर व्याख्यान दिया।
- 3 नवंबर 2014 को नई दिल्ली में इंडियन काउंसिल ऑफ़ वर्ल्ड अफ़ेयर्स (आईसीडब्ल्यूए) द्वारा 'दक्षिण अफ्रीका का अफ्रीकी एजेंडाः अफ्रीका के विकास के बदलते परिदृष्य' पर आयोजित चर्चा में पैनेलिस्ट।
- 9 नवंबर 2014 को नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा 'जैव प्रौद्योगिकी में उभरती प्रवित्तियां' (आईसीईटीबी–2014) पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में 'पर्यावरण जैव आचार नीति और आईपीआर के सामाजिक–जीववैज्ञानिक परिदृष्य' वाले सत्र में 'पर्यावरण और जैव आचार नीति और आईपीआर के सामाजिक–जीववैज्ञानिक परिदृष्य' पर व्याख्यान दिया।
- 12 नवंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा न्यूयार्क में 'अंतरराष्ट्रीय अधिकारिक विकास सहायता सहित अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त' पर महासभा के सबस्टैंटिव अनौपचारिक सत्र में भाग लिया जो विकास के लिए वित्तपोषण पर तीसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारी प्रक्रिया का अंग था।

- 15–16 नवंबर 2014 को ऑब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन द्वारा मुंबई में 'भारत की शक्ति और कमियों और उपयोगी रणनीतियों' पर आयोजित अर्थशास्त्रियों की परामर्श बैठक में भाग लिया।
- 20 नवंबर 2014 को यूएनडीपी द्वारा वाशिंगटन डीसी में दक्षिण–दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोगः 2014 की दक्षिण–दक्षिण सहयोग प्रदर्शनी की पार्श्व रेखा पर थिंक टैंकों के लिए उभरते अवसर शीर्शक मिनी फ़ोरम पर 'दक्षिणी थिंक टैंकों का संजाल' पर व्याख्यान दिया।
- 24–25 नवंबर 2014 को नई दिल्ली में ऑब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन द्वारा 'हिंद–प्रशांत में क्षेत्रीय एकीकरणः संभावनाएं और चुनौतियां' पर आयोजित सम्मेलन में 'आर्थिक एकीकरण में सीमाशुल्केत्तर अवरोध' सत्र में 'दक्षिण एशियाई क्षेत्र में व्यापार सुगमीकरण' पर व्याख्यान दिया।
- 25 नवंबर 2014 को सीएवीआई द्वारा 'बीज आंदोलन का सुगमीकरण, विनियम और प्रक्रियाएं पर विशेशज्ञों की विचार–विमर्श सभा' में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया।
- नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी (एनवीए) द्वारा 29 नवंबर 2014 को हैदराबाद में 'अभिगम और लाभ की भागीदारी' पर विशेषज्ञ समिति की बैठक में भाग लिया।
- 3 दिसंबर 2014 को नई दिल्ली में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान द्वारा 'खाद्य विनियम और नीति का अर्थशास्त्र और राजनीतिः भारत, चीन और केन्या में अनुसंधान के परिणाम' पर आयोजित संगोष्ठी में पैनल चर्चा में भाग लिया।
- आर्थिक विकास संस्थान (आईईजी) द्वारा 5 दिसंबर 2014 को नई दिल्ली में 'भारतीय कृषि में नवाचारः भावी मार्ग' पर आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के 'प्रौद्योगिकी सीमांत, बौद्धिक संपदा और उत्पादकता, और उत्पादकता विकास' सत्र की अध्यक्षता की।
- 20 दिसंबर 2014 को लीडरशिप फ़ॉर एनवाइरनमेंट ऐंड डेवलपमेंट (एलईएडी), पाकिस्तान द्वारा 'विकास, लोकतंत्र और शांति' पर आयोजित क्षेत्रीय वार्तालाप में 'पर्यावरणीय संकट, अंतरराष्ट्रीय तनाव और उग्रवाद' पर पैनल चर्चा में 'दक्षिण–दक्षिण' सहयोग की भूमिका पर पैनल के सदस्य के रूप में भाग लिया।
- 20 दिसंबर 2014 को इस्लामाबाद में साउथ एशिया सेंटर फ़ॉर पॉलिसी स्टडीज़ (एसएसीईपीएस) बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स की बैठक में भाग लिया।
- इंडियन चैंबर ऑफ़ कामर्स द्वारा 9 जनवरी 2015 को कोलकाता में ''लुक ईस्ट'' टु ''ऐक्ट ईस्ट'': न्यू फ्रंटियर्स इन ट्रेट इंवेस्टमेंट ऐंड बिज़नेस कोऑपरेशन पर वार्तालाप में ''लुक ईस्ट'' नीति को अधिक व्यापक बनानाः उभरती प्रवृत्तियां और नीतिगत विकल्प पर व्याख्यान दिया।
- 24 जनवरी 2014 को जकार्ता, इंडोनेशिया में आसियान और पूर्वी एशिया के आर्थिक शोध संस्थान (ईआरआईए) के लिए दूसरी शोध संस्थान संजाल बैठक (आईआईएनएन) में भाग लिया।
- 25 जनवरी 2015 को जकार्ता, इंडोनेशिया में आरआईएन एमईटीआई ईआरआईए वार्तालाप में भाग लिया।

- आईसीआरआईईआर द्वारा 2–3 फ़रवरी 2015 को नई दिल्ली में 'एन्हैंसिंग इंडिया पाकिस्तान ट्रेड' पर आयोजित संगोष्ठी में 'वीज़ा रेजीमः दि क्रिटिकल लिंक' सत्र की अध्यक्षता की।
- 4 फ़रवरी 2014 को नई दिल्ली में यूएन ईएससीएपी द्वारा आयोजित 'भारत और एमडीजीएसः सबके लिए वहनीय भविष्य की ओर' विषय पर विशलेषण के विमोचन के अवसर पर पैनल चर्चा में पैनलिस्ट की हैसियत से भाग लिया।
- 26 फ़रवरी 2015 को तिरुवनंतपुरम, केरल में जैवविविधता अभिगम और लाभ की भागीदारी विषय पर दूसरे राष्ट्रीय जैव विविधता सम्मेलन, 2015 के उद्घाटन सत्र में सम्मानित किए गए।
- 26 फ़रवरी 2015 को तिरुवनंतपुरम, केरल में 'जैव विविधता–अभिगम और लाभ की भागीदारी पर दूसरे राष्ट्रीय जैवविविधता सम्मेलन, 2015 में विकास के लिए जीव वैज्ञानिक संसाधनों की संभावना को मुक्त करना' विषय पर व्याख्यान दिया और 'अभिगम और विकास के लिए लाभ की भागीदारी' सत्र की अध्यक्षता की।
- 3–4 मार्च 2015 को रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए) द्वारा नई दिल्ली में आयोजित तीसरी भारत–अफ्रीका रणनीतिक वार्ता में 'दक्षिण–दक्षिण सहयोग का विकास और उत्पत्तिः भारत–अफ्रीका की भागीदारी के समक्ष समस्याएं' (अनुपस्थिति में) पर व्याख्यान प्रस्तुत किया।
- 4 मार्च 2015 को दक्षिण अफ्रीका में नेटवर्क ऑफ़ साउदर्न थिंक टैंक्स (एनईएसटी) अफ्रीका में आयोजित तकनीकी कार्यशाला में दक्षिण सहयोग को परिभाषित करना और लेखांकन करना पर व्याख्यान दिया।
- 10 मार्च 2015 को नई दिल्ली में नीति अध्ययन केंद्र और एशिया प्रतिशठान द्वारा 'दक्षेश देशों में द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करने वाले सीमा शुल्केतर अवरोधों' पर आयोजित कार्यशाला में 'दक्षिण एशिया और सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता के खाद्य पदार्थों का व्यापार समानता, एमआरएज़ और अन्य नीति विकल्प' पर व्याख्यान दिया।
- 16 मार्च 2015 को नई दिल्ली में पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परिचालन समिति (एनएससी) की तीसरी और परियोजना प्रबंधन और निगरानी समिति (पीएमएमसी) की छठी बैठक में 'एलएमओज़ के सामाजिक–आर्थिक मूल्यांकन के लिए दिशा–निर्देश और कार्यप्रणालियां विकसित करना प्रगति और भावी कार्य का कार्यक्रम' पर व्याख्यान दिया।

प्रो. एस. के. मोहंती

- 20 मार्च 2014 को टोकियो, जापान में 'आसियान की चुनौतियों से आगे और हिंद महासागर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की संभावनाएं और जापान के लिए उसके निहितार्थ' पर जापान रिसर्च इंस्टीट्यूट और एमईटीआई, जापान सरकार द्वारा आयोजित परिचर्या में (आईओआरए) में 'आर्थिक प्राथमिकताओं के बदलते रंगः व्यापार और क्षेत्र के वार्तालाप भागीदारों के निवेश हित' पर प्रस्तुतिकरण किया।

- 31 जुलाई 2014 को वित्त मंत्रालय में 'भारत के लिए व्यापक व्यापार रणनीति की दिशा में: अफ्रीका और चीन में व्यापार और अवसरों तक पहुंच' पर प्रस्तुतिकरण किया।
- एशियन फ़ाउंडेशन द्वारा 22–23 मई 2014 को 'इंडियाज़ साफ़्ट पावरः दि इमर्जिंग डायनामिक्स ऑफ़ इंडियन डेवलपमेंट कोऑपरेशन' पर आयोजित सम्मेलन में 'एक सैद्धांतिक ढांचे के अंतर्गत भारतीय विकास सहयोग के दृश्टिकोण को आकार देनाः मिशन का दृष्टिकोण' और 'टिप्पणियां: अपने पड़ोसी को समृद्ध करें: दक्षिण एशिया के साथ भारत का सहयोग' पर प्रस्तुतिकरण किया।
- ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट (एएसपीआई) द्वारा 8–9 सितंबर 2014 को कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन पर दूसरी त्रिपक्षीय वार्ता में 'आईओआरए में व्यापक फ़िशिंग प्रबंधन संस्थान के गठन की दिशा में' पर प्रस्तुतिकरण किया।
- 6–9 अक्तूबर को पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में आइओआरए के मंत्रिपरिषद की चौथी बैठक और अन्य संबंधित बैठकों में अकादमीय समूह के मुख्य भारतीय मुख्य केन्द्रीय बिन्दु के रूप में भाग लिया।
- पहले इंडिया फ़ाउंडेशन (पीआईएफ) द्वारा 20 अक्तूबर 2014 को नई दिल्ली में 'उभरते एशिया में भारत–वियतनाम के बीच सहयोग पर आयोजित गोल मेज चर्चा में 'भारत और वियतनाम के बीच सक्रिय व्यापारिक संबंध' पर प्रस्तुतीकरण दिया।
- 'चीन का रणनीतिक और आर्थिक उभारः एशिया में उसकी अनुगूंज' पर सेंटर फ़ॉर लैंड वारफ़ेयर स्टडीज़ (सीएलएडब्ल्यूएस) द्वारा 21 अक्तूबर 2014 को नई दिल्ली में आयोजित संगोष्ठी में 'चीन के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार असंतुलन की संवहनीयता का मुद्दा और चीन के व्यापार में क्षेत्रीय विषमता' पर भाषण दिया।
- एआईयू द्वारा 10 नवंबर 2014 को नई दिल्ली में आयोजित हिंद महासागर में यूनिवर्सिटी मोबिलिटी की बैठक में भाग लिया।
- 10–12 नवंबर 2014 को आईसीडब्लूए और एसआईएस, जेएनयू, द्वारा नई दिल्ली में 'उभरती विश्व व्यवस्था में भारतः राजनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक गतिशीलता' पर आयोजित बैठक में भाग लिया।
- राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एनबीए) द्वारा 13 नवंबर 2014 को हैदराबाद में सामान्य तिजारती जिन्सों की विशेषज्ञ समिति की आठवीं (पुनगर्ठित समिति की दूसरी) बैठक में भाग लिया।
- भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग द्वारा 20 नवंबर 2014 को नई दिल्ली में 'भारत सीओएमईएसए संयुक्त अध्ययन रिपोर्ट' पर आयोजित बैठक में भाग लिया।
- 'भारत प्रशांत में क्षेत्रीय एकीकरणः संभावनाएं और चुनौतियां' विषय पर आब्ज़र्वर शोध प्रतिष्ठान (ओआरएफ) द्वारा 25 नवंबर 2014 को आयोजित सम्मेलन में 'भारत प्रशांत में मेगा एफटीएज़ का उभारः भारत के लिए निहितार्थ' पर भाषण दिया।

- जेएनयू, नई दिल्ली के चीनी अध्ययन केंद्र में 21 जनवरी 2015 को 'भारत–चीन आर्थिक संबंध' पर व्याख्यान दिया।
- 5 फ़रवरी 2015 को नई दिल्ली में आईओआर सम्मेलन और भारत निर्माण के संबंध में सीआईआई के साथ चर्चा बैठक में भाग लिया।
- 3–4 मार्च 2015 को नई दिल्ली में रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए) द्वारा 'भारत अफ्रीकाः शांति, सुरक्षा और विकास के क्षेत्र में सहक्रियाओं का निर्माण' विषय पर तीसरी भारत–अफ्रीका रणनीतिक वार्तालाप में 'भारत–अफ्रीका आर्थिक गतिकीः वैश्विक अनिश्चिताओं के युग में द्विपक्षीय संबंधों के बदलते रंग' पर भाषण दिया।
- 11 मार्च 2015 को नई दिल्ली में वाणिज्य मंत्रालय में सीओएमईएसए पर भाषण दिया।
- 16 मार्च 2015 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की सामान्य तिजारती जिन्सों की विशेषज्ञ समिति की नौवीं (पुनगर्ठित समिति की तीसरी) बैठक में भाषण दिया।

प्रो. राम उपेंद्र दास

- 29 अप्रैल 2014 को भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग द्वारा नई दिल्ली में सहयोग के क्षेत्रों की पहचान, सहयोग मूल्य श्रृंखलाएं और सीएलएमवी के साथ एकीकरण के अध्ययन के लिए आयोजित बैठक में भाषण दिया।
- 18–21 जून 2014 को ईआरआईए द्वारा जकार्ता में जकार्ता स्थित आईआरआईए प्रायोजित अध्ययन कार्यशाला में 'ईएएस प्रक्रिया के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता का अर्थ' विषय पर भाषण दिया।
- 1–3 अगस्त 2014 को मुंबई में मेटल रिसाइकिलिंग असोसिएशन ऑफ़ इंडिया द्वारा आयोजित सम्मेलन में 'आरटीएज़ की समझ' पर व्याख्यान दिया।
- 16–19 सितंबर 2014 को एडब्ल्यूडब्ल्यू द्वारा बैंकॉक में 'एशिया प्रशांत एफटीएः अवरोध और संभावनाएं' पर आयोजित सम्मेलन में भाग लिया।
- ईयू–यूरोपिएन फ़ारेस्ट इन्स्टीट्यूट (ईएफटी) द्वारा 24 सितंबर 2014 को नई दिल्ली में 'दक्षिण एशिया में अंतः क्षेत्रीय लकड़ी व्यापार' पर आयोजित गोलमेज बैठक में भागीदारी की।
- भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 7 अक्तूबर 2014 को सीएलएमवी पर आयोजित बैठक में भाग लिया।
- 16 अक्तूबर 2014 को नई दिल्ली में भारतीय प्रबंधन संस्थान के संस्थापना दिवस में भाग लिया।
- 13 नवंबर 2014 को नई दिल्ली में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी) द्वारा आयोजित व्यापारिक फ़ोरम में 'एपीटीएः एशिया–प्रशांत व्यापार अनुबंध में सदस्यता विस्तार के महत्व और भावी कार्य योजना' पर व्याख्यान दिया।

- 10 दिसंबर 2014 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कानपुर में आयोजित क्यूआईपी संगोष्ठी में 'अर्थव्यवस्था के सीमांत और अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्त' पर उद्घाटन भाषण दिया।
- 11 दिसंबर 2014 को नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त महामहिम श्री पैट्रिक सकलिंग द्वारा 'पूर्वी एशियाई आर्थिक एकीकरण' पर आयोजित औपचारिक मध्यान्ह भोज बैठक में भाग लिया।
- 15–16 दिसबंर 2014 को बीजिंग में 'क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और एईएस' पर चीनी समाज विज्ञान अकादमी (सीएएसएस), चीन और एएसईएएन और पूर्वी एशिया के लिए आर्थिक शोध संस्थान (ईआरआईए) द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में 'भारत और क्षेत्रीय उत्पादन संजाल' पर भाषण दिया।
- कनाडा के उच्चायोग द्वारा 21 जनवरी 2015 को नई दिल्ली में 'दक्षिण एशियाई आर्थिक एकीकरण' पर आयोजित गोलमेज में भाग लिया।
- 2–3 फ़रवरी 2015 को आईसीआरआईईआर द्वारा नई दिल्ली में 'भारत–पाकिस्तान व्यापार के सामान्यीकरण' पर आयोजित तीसरे वार्षिक सम्मेलन में 'अनौपचारिक व्यापारः यह क्यों बना हुआ है' पर भाषण दिया।
- 4–6 जनवरी 2015 को मेटल रिसाइकिलिंग असोसिएशन ऑफ़ इंडिया (एमआरएआई) द्वारा आयोजित 'दूसरे अंतरराष्ट्रीय भारतीय धातु पुनर्चक्रण सम्मेलन' में भाषण दिया।
- 10–11 फ़रवरी 2015 को टीईपीएवी–सीईजीआई द्वारा इस्तांबुल में 'ज्वाइंट थिंक 20 टर्की' के अंतर्गत आयोजित 'थिंक टैंक नेटवर्किंग इन्सेप्शन मीटिंग अंडर जी 20' में भाग लिया।
- 27 फ़रवरी 2015 को नई दिल्ली में इंडियन रजिस्टर ऑफ़ शिपिंग द्वारा 'थिंक टैंक इनिशिएटिव' पर नौपरिवहन मंत्रालय में आयोजित बैठक में भाग लिया।
- 3 मार्च 2015 को नई दिल्ली में कनाडा के उच्चायोग द्वारा 'दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय आर्थिक समस्याओं' पर दक्षिण एशियाई देशों में कनेडियाई मिशनों के क्षेत्रीय प्रमुखों के साथ आयोजित गोलमेज में भाग लिया।
- 5 मार्च 2015 को नई दिल्ली में भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध शोध परिषद् (आईसीआरआईईआर) द्वारा 'भारत और व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी)' पर आयोजित गोलमेज में भागीदारी की।
- 23–24 मार्च 2015 को नई दिल्ली में भारतीय विश्व कार्य परिषद् (आईसीडब्ल्यूए) द्वारा 'एशियाई विदेश नीतियों में गैर परंपरागत विषय' पर आयोजित छठे वार्षिक एशियाई संबंध सम्मेलन में 'क्षेत्रीय समुदाय : महाद्वीपीय समाभिरूपता (कन्वर्जेंस) की ओर' पर पैनल के सदस्य के रूप में भाग लिया।
- सेंटर फ़ॉर डेवलमेंट ऐंड एंटरप्राइज़ (सीडीई) और सेंटर फ़ॉर पॉलिसी रिसर्च द्वारा 25 मार्च 2015 को नई दिल्ली में विकासशील देशों में निर्धनतर लोगों के लिए अवसर पर आयोजित चर्चा बैठक में भाग लिया।
- सेंटर फ़ॉर डेवलमेंट ऐंड एंटरप्राइज़ (सीडीई) द्वारा 26 मार्च 2015 को नई दिल्ली में 'आर्थिक सुधार और ग़रीब लोगों के लिए अवसर' पर आयोजित कार्याशाला में भाग लिया।

प्रो. टी सी जेम्स

सलाहकार

- 10 अक्तूबर 2014 को वैश्विक बौद्धिक संपदा संस्थान, नई दिल्ली में 'कॉपीराइट, संबंधित अधिकार, भौगोलिक संकेत, परंपरागत ज्ञान और व्यापारिक रहस्य' पर आयोजित सेमिनार में भाग लिया।
- 16 नवंबर 2014 को लायर्स कलेक्टिव द्वारा नई दिल्ली में भारत का बौद्धिक संपदा तंत्र–उभरती चुनौतियां पर आयोजित विचार–विमर्श सभा में रिसोर्स पर्सन के रूप में भाग लिया।
- 22 जनवरी 2015 को कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा अंबालावायल, वायनाड, केरल में 'वनस्पत्ति प्रजाति और किसानों के लिए किसान अधिकार अधिनियम' पर व्याख्यान दिया।
- 23 जनवरी 2015 को पनामारन, वायनाड, केरल में आयोजित केरल कृषि विश्वविद्यालय की कार्यशाला में भाग लिया और 'मार्केट एन्हैंसमेंट ऑफ़ ज्योग्रैफ़िकल इंडिकेशन्स टैग्ड पॉडक्ट्स– सेलेक्टेड बिजनेस मॉडल्स' पर भाषण दिया।
- 29 जनवरी 2015 को नेशनल ला यूनिवर्सिटी द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 'भारत के जैवविविधता अधिनियम की कार्य प्रणाली' सत्र की अध्यक्षता की और 'भारत में एबीएस रेजीम लागू करने के लिए आइपी नीति के विकल्प' पर भाषण दिया।
- 22 फ़रवरी 2015 को आईआईटी खड़गपुर में 'प्रोटेक्शन ऑफ़ कॉपीराइट ऐंड एन्नोवेशन' पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया और 'नवाचार और बौद्धिक संपदा अधिकारों की दार्शनिक आधार शिला' पर भाषण दिया।
- 13 मार्च 2015 को नई दिल्ली में गुरुगोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली द्वारा आईपीआर और टीके के बीच अंतःक्रियाः वैश्विक शासन– बौद्धिक संपदा का विश्लेषण' सत्र की अध्क्षता की।

डॉ. के. रवि श्रीनिवास

सलाहकार

- 25–26 फ़रवरी 2015 को तिरुअनंतपुरम, केरल में जैव विवधता– पहुंच और लाभ की भागीदारी पर आयोजित दूसरे राष्ट्रीय जैवविविधता सम्मेलन 2015 में भागीदारी की।
- 16 मार्च 2015 को एलएमओ (LMOs) के सामाजिक–आर्थिक मूल्यांकन पर पर्यावरण तथा वन मंत्रालय की परियोजना बैठक में भाग लिया।

डॉ सव्यसाची साहा
सहायक प्रोफेसर

18 दिसंबर 2014 को नई दिल्ली में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्त में अनुभवजन्य मुद्दों पर आयोजित सम्मेलन के व्यापार और विकास सत्र में 'विभाजित कारक बाज़ारों के साथ प्राद्यौगिकी प्रगति और शहरी ग़रीबों के लिए कल्याणकारी निहितार्थ' शीर्षक परचे पर चर्चा की।

डॉ. प्रियदर्शी दास
शोध सहयोगी

- 22 दिसंबर 2014 को सिचुआन एकैडमी ऑफ़ सोशल साइंसेज़ (एसएएसएस), चेंगडु, चीन में 'क्षेत्र और उप–क्षेत्र में चीन–भारत सहयोग', पर आयोजित संगोष्ठी में 'बढ़ते एशियाई क्षेत्रवाद के संदर्भ में भारत–चीन आरईसीपी और उससे परे', पर प्रस्तुतिकरण दिया।

IV

क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम

अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों और विकास नीति (IEIDP)पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम

आरआईएस ने 16 फ़रवरी से 13 मार्च 2015 के दौरान नई दिल्ली में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी)/(एससीएएपी) (ITEC/ SCAAP) कार्यक्रम के संयुक्त तत्वावधान में अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों और विकास नीति पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाया। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों और विकास नीति कार्यक्रम (आईईआईडीपी) में विकासशील देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। यह कार्यक्रम वैश्विक आर्थिक मुद्दों और सौदेबाजियों की बढ़ती जटिलताओं से भागीदारों का परिचय कराने और उनमें उनसे निपटने की विश्लेषणात्मक दक्षताएं विकसित करने के लिए तैयार किया गया है।

इस कार्यक्रम में दूसरे क्षेत्रों के अलावा वैश्विक व्यापार प्रणालियों, और डब्ल्यूटीओ, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणालियों, दक्षिण–दक्षिण सहयोग, क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और बहुराष्ट्रीय उद्यमों, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, और सुधारों के क्षेत्र में क्षमता निर्माण शामिल है। भागीदारों को राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्त्व के विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयों, विशेष रूप से विकास देशों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण विषयों पर चर्चा में व्यस्त रखा गया। यह काम आरआईएस के प्राध्यापकों के अलावा बाहर के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों और नीतिनिर्माताओं के सिलसिलेवार व्याख्यानों के माध्यम से किया गया। भागीदारों को दिल्ली और दिल्ली से बाहर के क्षेत्रों का भ्रमण कराकर भारत की आर्थिक गतिशीलता से परिचय कराया गया। आरआईएस के प्रो. राम उपेंद्र दास कार्यक्रम के निदेशक थे।

आरआईएस संकाय सदस्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों और विकास नीति (आईईडीपी)पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम के प्रतिभागी।

दक्षिण–दक्षिण सहयोग पर आईटीईसीध्एससीएएपी क्षमता निर्माण कार्यक्रम

आरआईएस ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटीईसी) अफ्रीका के लिए विशेष राष्ट्रकुल सहायता कार्यक्रम (एससीएएपी) के अंतर्गत 17 से 28 नवंबर 2014 के बीच नई दिल्ली में दक्षिण–दक्षिण सहयोग पर दो सप्ताह के क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया। दक्षिण–दक्षिण सहयोग की वृहत्तर संकल्पना से भागीदारों का परिचय कराना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था, ख़ासतौर से वैश्विक सहायता के स्थापत्य में देखे जा रहे प्रमुख बदलावों के बरक्स दक्षिण की अर्थव्यवस्थाओं के पुनरुत्थान के संदर्भ में विकास सहयोग से परिचय कराया गया। दूसरी चीज़ों के अलावा, इस कार्यक्रम ने संबंधित देशों की व्यक्तिगत उपलब्धियों के आधार पर औचित्य, संकल्पना और एसएससी (दक्षिण–दक्षिण सहयोग) के आकार–प्रकार पर ध्यान केंद्रित किया। इस तरह उनकी सामूहिक वचनबद्धताओं के लाभों और उनके अवरोधों को बताया गया। इसने सिद्धांतों, नीतियों, साधनों (जिनमें राष्ट्रीय संप्रभुता, राष्ट्रीय स्वामित्व, स्वतंत्रता, समानता, शर्तहीनता, हस्तक्षेपहीनता और पारस्परिक लाभ शामिल हैं) आदि को समाहित किया जो एसएससी में दिखाई देते हैं और विचार किया कि नीतिगत रुझानों या एसएससी की शक्तियों का व्यावहारिक उपयोग कैसे किया जा सकता है। इसमें इस तथ्य पर भी चर्चा की गई कि दक्षिण–दक्षिण सहयोग उत्तर–दक्षिण सहयोग (एनएससी) से एक अलग प्रतिमान कैसे है और एसएससी को स्वैच्छिक भागीदारी के रूप में कैसे देखा जाना चाहिए जिसने राजनीतिक एकता की प्रारंभिक आधारशिला का संक्रमण करके अब एक अधिक परिपक्व मंच का रूप ले लिया है, और जो किसी

आरआईएस संकाय के साथ दक्षिण–दक्षिण सहयोग पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम के प्रतिभागी।

महत्वपूर्ण रूप में एनएससी का स्थानापन्न नहीं है। इस कार्यक्रम में भाग लेने वालों में विदेश वित्त वाणिज्य मंत्रालयों या एसएससी–एनएससी से संबंध रखने वाले दूसरे मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी और संबधित मुद्दों से जुड़े नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल थे। इस कार्यक्रम में भाग लेने वालों को संबंधित स्थानों की यात्रा करा कर उनका एसएससी के विभिन्न आकार–प्रकारों से संक्षिप्त परिचय कराया गया।

म्यांमार में व्यापार और निवेश क्षमता का निर्माण

आरआईएस ने अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और समाज केंद्र (सीईएसएस), म्यांमार के संयुक्त तत्वावधान में यूनियन ऑफ़ म्यांमार फ़ेडरेशन ऑफ़ कामर्स ऐंड इंडस्टरि (यूएमएफसीसीआई) भवन यंगून में ट्रेड सिफ़्ट, एशिया–प्रशांत शोध और प्रशिक्षण तंत्र (एआरटीएनईटी)/(ARTNeT), आरआईएस के आसियान–भारत केंद्र, यूएमएफसीसीआई(UMFCCI), कोलकात्ता विश्वविद्यालय, जाधवपुर विश्वविद्यालय, और

यूएमएफसीसीआई इमारत, यानगोन में आयोजित व्यापार नीति और विश्लेशण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी।

जाडावपुर विश्वविद्यालय, कोलकता में आयोजित व्यापार नीति और विश्लेषण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी।

ससेक्स विश्वविद्यालय के सहयोग से 26 से 30 मई 2014 तक एक सप्ताह का गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस समारोह को आईपीई ग्लोबल, अंतरराष्ट्रीय विभाग (डीएफआईडी) और म्यांमार के वाणिज्य मंत्रालय का भी समर्थन प्राप्त था।

म्यांमार के वाणिज्य मंत्रालय के माननीय उप–वाणिज्य मंत्री डॉ. प्विंट सान ने उद्घाटन भाषण दिया। परियोजना की व्यवस्था कर रहे प्रो. प्रबीर डे ने आरंभिक वक्तव्य दिया। उद्घाटन सत्र में यूनियन म्यांमार फेडेरेशन ऑफ़ कामर्स ऐंड इंडस्ट्री (यूएमएफसीसीआई) के उपाध्यक्ष श्री जॉ मिन विन और यूएनईएससीएपी (UNESCAP) के व्यापार और निवेश संभाग के व्यापार और नीति खंड के प्रमुख डॉ. मिआ मिकिक शामिल थे। कार्यक्रम में भारत, यूके, यूएनईएससीएपी, और म्यांमार के जाने–माने शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं ने व्याख्यान और भाषण दिए। इस क्षमता निर्माण कार्यक्रम को जारी रखते हुए 16 सितंबर से 20 सितंबर 2014 तक जाधवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता में पांच दिवसी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जाधवपुर विश्वविद्यालय के प्रो. अजिताभ राय चौधरी ने स्वागत टिप्पणियां कीं। भारत सरकार के पूर्व वित्त और राजस्व सचिव और आईपीई ग्लोबल के निदेशक और दि नॉलेज पार्टनरशिप प्रोग्राम के टीम प्रमुख श्री सुनिल मित्रा और जाधवपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो अभिजीत चक्रवर्ती ने विशेष वक्तव्य दिए। आरआईएस के प्रो. प्रबीर डे ने उद्घाटन टिप्पणियां कीं। कोलकाता में म्यांमार के वाणिज्यिक दूत महामहिम श्री यान हत्वे ने उद्घाटन भाषण दिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में म्यामार के वरिष्ठ अधिकारी और विद्वान उपस्थित थे।

बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आरआईएस संकाय के दिए व्याख्यान

प्रो. सचिन चतुर्वेदी

महानिदेशक

- 30 मई 2014 को आईआईएफटी द्वारा नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के समसामयिक मुद्दों पर वरिष्ठ आईटीएस अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'भारत के बाहरी क्षेत्र और व्यापार सुगमीकरण की उभरती गतिकी' पर व्याख्यान दिया।
- 3 जुलाई 2014 को विदेश सेवा संस्थान, नई दिल्ली में 'भारत के विदेशी क्षेत्र और डब्ल्यूटीओः एक सिंहावलोकन' पर व्याख्यान दिया।

प्रो. टी सी जेम्स

सलाहकार

- इंडियन सोसायटी ऑफ़ इंटरनेशनल लॉ (आईएसआईएल), नई दिल्ली में 20 नवंबर 2014 को 'डब्ल्यूटीओ और भारतीय पेटेंट कानून' पर भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को विशेष व्याख्यान दिया।
- आईएसआईएल, नई दिल्ली में 3 दिसंबर 2014 को अंतरराष्ट्रीय उद्योग और व्यापार कानून में पीजी डिप्लोमा कोर्स के लिए 'पेटेंटः टीआरआईपीएस और भारतीय पेटेंट अधिनियम' पर विशेष व्याख्यान दिया। डब्ल्यूटीओ अध्ययन केंद्र, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान में 13 दिसंबर 2015 को 'भारत में स्वास्थ्य परिचर्या के परिणामों को सुधारने में बायोलाजिक्स की संभावनाओं और पहुंच के अवरोध' पर चर्चा की।
- वैश्विक बौद्धिक संपदा संस्थान (जीआईआईपी), नई दिल्ली में 14 फ़रवरी 2015 को 'स्वत्वाधिकार और संबंधित अधिकार' और 'भौगोलिक संकेत, व्यापारिक रहस्य और परंपरागत ज्ञान' पर राष्ट्रीय वेबिनारों का संचालन किया।
- 3–4 मार्च 2015 को बौद्धिक संपदा पर डब्लूआईपीओ समर स्कूल (इंडिया) में 'टीआरआईपीएस' और पेटेंट; स्वत्वाधिकार और संबंधित अधिकारों के अपवाद और सीमाएं; चल रही बहसें, स्वत्वाधिकार और लोकवृत्तः केस स्टडी' पर कक्षाएं चलाईं।
- जैव विज्ञान संस्थान (आईएलएस), भुवनेश्वर में 21 मार्च 2013 को 'प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण के लिए नवाचारों और बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) का अंतराफलन' पर व्याख्यान दिया।
- औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान (आईएसआईडी), नई दिल्ली में 26–27 मार्च 2015 को 'पेंटेंट का प्रशासन और औषधियों तक पहुंच' पर व्याख्यान दिया और 'राष्ट्रीय बौद्धिक नीति का मसविदा' पर पैनल चर्चा में पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।
- शहीद भगतसिंह कॉलेज, नई दिल्ली, के शिक्षकों को 27 मार्च 2015 को 'बौद्धिक संपदा अधिकार, स्वत्वाधिकार और साहित्यिक चोरी का परिहार' पर भाषण दिया।

डॉ. प्रियदर्शी दास

शोध सहयोगी

- 13–15 नवंबर 2015 के दौरान स्कूल ऑफ़ इंटरनेशनल स्टडीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ़ गुजरात (सीयूजी) गांधीनगर, गुजरात में 'अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था' पर एमफिल कोर्स के अंतरराष्ट्रीय वित्त मॉड्यूल पर व्याख्यान दिए।
- दक्षिण एशियाई अध्ययन संस्थान (आईएसएएस), सिचुआन विश्वविद्यालय चेंगदू, चीन में 23 दिसंबर 2014 को 'बढ़ते एशियाई क्षेत्रवाद के संदर्भ में भारत–चीन संबंधः आरसीईपी और उससे परे' पर अंतरराष्ट्रीय संबंधों के परास्नातक कार्यक्रम के छात्रों के लिए व्याख्यान दिया।

V

प्रकाशन कार्यक्रम

बुक्स/रिपोर्ट

दक्षिण एशिया विकास और सहयोग रिपोर्ट 2015
आरआईएस, नई दिल्ली, 2015

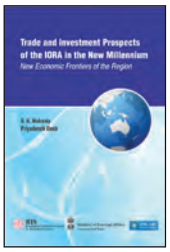

नई सहस्राब्दी में आईओआरए के व्यापार और निवेश की संभावनाएं: क्षेत्र के नए आर्थिक सीमांत
एसके मोहंती और प्रियदर्शी दास, आरआईएस, नई दिल्ली, 2015

भारत–आसियन संयोजकता: दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की चुनौतियां और अवसर: शिलांग गोलमेज का सारांश
आरआईएस का आसियन–भारत केंद्र, नई दिल्ली 2015

गौरव के क्षण

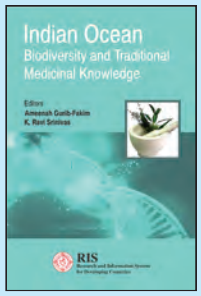

हिंद महासागर जैव विविधता और परंपरागत चिकित्सीय ज्ञान

डॉ. अमीना गुरीब–फ़ाकिम और के. रवि श्रीनिवास (संपादक), आरआईएस, नई दिल्ली, 2015

वर्तमान में माननीय डॉ. अमीना गुरीब–फ़ाकिम वर्तमान में मॉरीशस की राष्ट्राति हैं

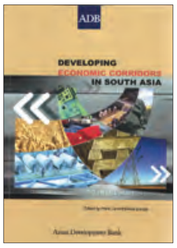

दक्षिण एशिया में आर्थिक गलियारे विकसित करना
प्रबीर डे और कविता आयंगर (संपादक), एशियाई विकास बैंक (एडीबी), मनीला और आरआईएस, नई दिल्ली, 2015

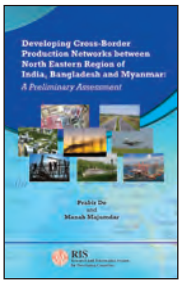

भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, बंगलादेश और म्यांमार के बीच सीमा पार उत्पादन संजाल विकसित करनाः एक प्रारंभिक मूल्यांकन
प्रबीर डे और मानव मजूमदार, आरआईएस, नई दिल्ली, 2014

पूर्वी एशियाआर्थिक एकीकरण प्रक्रिया के लिए भारत की आर्थिक गतिशीलता का अर्थ
राम उपेंद्र दास; ईआरआईए; जकार्ता; और आरआईएस नई दिल्ली, 2014

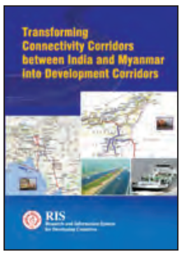

भारत और बर्मा के बीच के संयोजकता गलियारे का विकास गलियारे में रूपांतरण
राजदूत वी एस शेषाद्रि, आरआईएस, नई दिल्ली, 2014

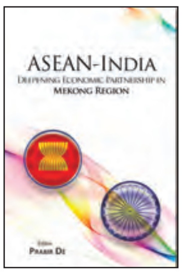

मेकांग क्षेत्र में आसियन- भारत की गहराती आर्थिक भागीदारी
प्रवीर डे (संपादक), आरआईएस, नई दिल्ली, 2014

एशिया- प्रशांत में जैव प्रोद्योगिकी क्षमता पर सर्वेक्षण रिपोर्टः राष्ट्रीय पहलें और क्षेत्रीय सहयोग के अवसर
युनेस्को, जकार्ता के लिए तैयार की गई रिपोर्ट, 2014

आसियन-भारत समुद्री संयोजकता रिपोर्ट

आरआईएस का आसियन–भारत केंद्र, नई दिल्ली 2014

आसियन-भारत रणनीतिक भागीदारी की गतिकी

आसियन–भारत प्रबुद्ध मंडल संजाल (एआईएनटीटी) पर गोलमेज की कार्रवाई, आरआईएस का आसियन–भारत केंद्र, नई दिल्ली, 2014

परिचर्चा पत्र

#195 भारत में खाद्य प्रौद्योगिकी पर बहसः शोध-परिवर्धन की प्राथमिकताएं, उत्पादन के रुझान और बढ़ती अपेक्षाएं

सचिन चतुर्वेदी और साहिल अरोड़ा

सारांशः प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों ने पैदावार और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने में योगदान किया है। विविधतापूर्ण आवश्यकताओं और लक्ष्यों को देखते हुए नीति नियामकों को खाद्य और कृषि में तरह–तरह की प्रौद्योगिकियों और रणनीतियों का उपयोग करना पड़ता है। यह परिचर्या पत्र भारतीय कृषि में तीन अलग–अलग प्रौद्योगिकीय विकल्पों के उपयोग की पड़ताल करता है। यह दर्शाता है कि जैविक खेती के लिए समर्थन बढ़ रहा है लेकिन इस स्थिति में नवाचार संबंधी आगत बहुत कम है। कृषि में पंरपरागत वनस्पति जनन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। विज्ञान और टेक्नॉलॉजी में नैतिकता के संदर्भ में पड़ताल करने पर ये अनुप्रयोग बताते हैं कि उपयुक्त नीतियों का मिश्रण खाद्य सुरक्षा बढ़ा कर और किसानों की अरक्षितता कम करके लाभ दायक परिणाम दे सकता है। नवाचार, जोखिम, ऊर्जा और नियंत्रण के अर्थों में तार्किक विश्लेषण से पता चलता है कि नवाचार की चर्चा नीतिगत फ़ैसलों को औचित्य प्रदान करने में अहम भूमिका निभाती है जबकि जोखिम और नियंत्रण की चर्चा आलोचक करते हैं। भारतीय संदर्भ में एस ऐंड टी नीति में आचार नीति के आयामों की पड़ताल पहुंच, समावेशन और समानता (एआईए) ढांचे के अंतर्गत की जा सकती है। इस पर चर्चा करना महत्त्वपूर्ण है कि भारत ऐसे प्रभावी ढांचे के विकास में कहां तक सक्षम रहा है जो कृषि क्षेत्र में उभर कर सामने आई चुनौतियों और एआईई की समस्याओं का समाधान कर सके। यह परचा भारत के कृषि और खाद्य क्षेत्र में इस ढांचे के उपयोग की रूप–रेखा प्रस्तुत करता है।

#194 भारत में संश्लेषित जीव विज्ञानः जोखिम, शक्ति और अभिशासन के मुद्दे

कृष्णा रवि श्रीनिवास द्वारा

सारांशः संश्लेषित जीवविज्ञान उभरती प्रौद्योगिकी है जो ऐसे सूक्ष्म जीवों की 'डिज़ाइन' और 'सृजन' को सुगम बना सकती है जो प्रकृति में नहीं पाए जाते। संश्लेषित जीवविज्ञान को अभियांत्रिकी और जीवविज्ञान का मिश्रण माना जाता है। पिछले दशक में दुनिया भर में संश्लेषित जीवविज्ञान ने तेज़ी से प्रगति की है; बहरहाल, भारत में अभी यह सद्यःजात अवस्था में है। इस परिचर्चा पत्र में भारत में संश्लेषित जीवविज्ञान पर चल रहे विचार–विमर्श का भी विश्लेषण किया गया है। हालांकि भारत में संश्लेषित जीव विज्ञान को अभी बड़े प्रोत्साहन की ज़रूरत है लेकिन जैव ईंधन की पहलें और शोध केंद्रों की स्थापना इस बात का संकेत है कि भारत में यह तेज़ी से विकसित हो सकता है। योजना आयोग द्वारा गठित कार्यबल ने नियामक मुद्दों सहित विभिन्न मुद्दों की पड़ताल की और भारत में संश्लेषित जीवविज्ञान के लिए भावी मार्ग सुझाया। दुहरे उपयोग, नियंत्रण ढांचे का अभाव और विनियमों की आवश्यकता भारत के लिए अनूठी नहीं है। जैव औषधि, कृषि, ऊर्जा, और अन्य क्षेत्र में संश्लेषित जीव विज्ञान की संभावना को देखते हुए यह महत्त्वपूर्ण है कि संश्लेषित जीव विज्ञान को वह प्राथमिकता मिले जिसका वह हक़दार है। यह परचा भारत में संश्लेषित जीवविज्ञान के भावी मार्गों की भी पड़ताल करता है और सुझाव देता है कि संश्लेषित जीवविज्ञान के लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि निधीयन और नियामक, नैतिक, कानूनी और सामाजिक समस्याओं के समाधान के अर्थों में इसे पर्याप्त समर्थन दिया जाए।

#193 भारत में अतिसूक्ष्म प्रौद्योगिकी (नैनोटेक्नालॉजी) एक सिंहावलोकन

अमित कुमार

सारांशः दुनिया भर में बहुत से विद्वानों ने क्रंतिकारी प्रौद्योगिकी के रूप में नैनोटेक्नॉलॅजी का महिमागान किया है। समर्थकारी प्रौद्योगिकी होने के नाते यह विभिन्न अनुशासनों में शोध और परिवर्धन की नई संभावनाएं प्रदान करती है और स्वास्थ्य परिचर्या/औषधियों, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, कृषि, भवन निर्माण, जल संसाधन, और खाद्य संसाधन से प्रसाधन तक विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा सकता है। इन अनुप्रयोगों में से बहुत से अनुप्रयोग भारत जैसे विकासशील देश के लिए बहुत प्रासंगिक हैं। इस संदर्भ में सरकार 2000 के दशक से ही नैनोटेक्नोलॅजी के क्षेत्र में शोध और परिवर्धन को प्रोत्साहन देने में अग्रणीय भूमिका निभा रही है। यह परिचर्या पत्र नैनोटेक्नॉलॅजी के क्षेत्र में शोध और परिवर्धन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वार उठाए गए कदमों, इससे जुड़े प्रमुख किरदारों, और देशों में मौजूद नियामक ढांचे को रेखांकित करते हुए भारत में इसके विकास पर प्रकाश डालने के प्रयास करता है। यह इन पहलुओं के साथ–साथ कुछ ख़ास–ख़ास वैश्विक पहलोंध्रूझानों पर भी विचार करता है।

#192 सन 2000 से प्रगति–रोज़गार संबंध

शिप्रा निगम

सारांशः यह परिचर्चा पत्र पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में उभर कर आई रोज़गार की चुनौती का संक्षिप्त मूल्यांकन करता है। यह विभिन्न उपलब्ध आर्थिक संकेतकों का विश्लेषण करता है और ऐसे अनुमान पेश करता है जो उन सांगठनिक रूपांतरणों को दर्शाते हैं जो हुए हैं। यह परचा जिस महत्वपूर्ण विषय की पड़ताल करता है वह यह कि पिछले एक दशक में भारतीय अर्थव्यवस्थआ ने जो प्रगति दर्ज कराई है क्या रोज़गार में उसके आनुशांगिक वृद्धि हुई है। यह इस तथ्य को प्रकाष में लाता है कि कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले दशक में उन क्लासकीय विशेषताओं की अनुभूति करती जान पड़ती है, बड़े विकासशील देशों में रोज़गार की स्थिति की चर्चा करते हुए जिनका किताबों में उल्लेख किया गया है। कुल मिलाकर रोज़गार प्रत्यास्थता कम हुई है, पारिश्रमिक की असमानता बढ़ी है; श्रम का अनौपचारिकीकरण और नैमित्यीकीकरण बढ़ा है और बड़ी संख्या में कामकाजी ग़रीब मौजूद हैं। परचा यह भी दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था के विकासमान क्षेत्रों में रोज़गार वृद्धि दर और लोच में लंबे अरसे से गिरावट आ रही है। इससे बेरोज़गारों और बेरोज़गार श्रम शक्ति को अधिक उत्पादक और गतिशील रोज़गार अवसरों में समाहित करने की प्रक्रिया धीमी पड़ी है।

#191 योरपीय संघ की प्रस्तावित कार्बन समानीकरण की प्रणालीः भारतीय निर्यात के लिए कुछ निहितार्थ

विश्वजित घर

सारांशः 2009 में योरपीय संघ (ईयू) ने सीमा कार्बन माप का प्रस्ताव रखा था जो उसके भागीदार देशों से, जो उसके उत्सर्जन मानकों का पालन नहीं कर रहे थे, आयात पर प्रत्यक्ष या परोक्ष ''कार्बन कर'' का रूप ले सकती है। हालांकि इस प्रस्ताव का कथित उद्देश्य 'कार्बन रिसाव' को रोकना' या उद्योगों का तथाकथित प्रदूषण स्वर्गों में स्थानांतरण था, लेकिन इसका असली मकसद योरपीय संघ के देशों में स्थित उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना था। इस प्रस्ताव से व्यापक जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। क्योंकि यह ईयू के भागीदार देशों में उद्योगों के बहुत बड़े हिस्से की बाज़ार पैठ संभावनाओं को प्रभावित कर सकता था। यह परचा उपलब्ध आंकड़ों की गहन पड़ताल करके भारत पर प्रस्तावित माप के प्रभावों का विश्लेषण करता है।

नीति सार

64 इसका संबंध केवल चीन के आर्थिक विकास से नहींः पूंजी महत्वपूर्ण है अप्रैल 2014

65 जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत अभिगम और लाभ की भागीदारीः अधिक प्रभावी शासन की दिशा में, अप्रैल 2014

66 बल्क ड्रग्स के क्षेत्र में भारत की आयात पर बढ़ती निर्भरता, 5 फ़रवरी 2015

67 आईपी अधिकार, नवाचार और विकास प्राथमिकताएंः संतुलन की आवश्यकता, मार्च 2015

एफआइडीसी के नीति सार

#3 उत्तर–2015 विकास कार्यसूचीः एक भारतीय प्रिप्रेक्ष्य, अगस्त 2014

#4 डीएसी के सदस्य और सीएसओ के साथ अनुबंधः उभरते अनुभव और पाठ, जनवरी 2015

आरआईएस के जर्नल

- दक्षिण एशिया आर्थिक जर्नल, खंड 15, अंक 2, सितंबर 2014
- दक्षिण एशिया आर्थिक जर्नल, खंड 16, अंक 1, मार्च 2015
- एशियाई जैव प्रौद्योगिकी और विकास पुनरीक्षण, खंड 16, अंक 2, जुलाई 2014
- एशियाई जैव प्रौद्योगिकी और विकास पुनरीक्षण, खंड 16, अंक 3, जुलाई 2014
- एशियन बॉयोटेक्नॉलॉजी ऐंड डेवलपमेंट रिव्यू खंड 17, अंक 1, मार्च 2015

आरआईएस की डायरी

आरआईएस की डायरी खंड 9 और 10, अंक 4, अक्तूबर 2014

खंड 11 अंक 1 जनवरी 2015

बाहरी प्रकाशनों में आरआईएस के संकाय का योगदान

पुस्तकें/रिपोर्टें

चतुर्वेदी, सचिन. 2014. (संपादक) दि राइज़ ऑफ़ एशियन इमर्जिंग प्रोवाइडर्सः न्यू अप्रोचेज़ टु डेवलपमेंट कोऑपरेशन इन एशिया एएफडी–टीएएफ संगोष्ठी की कार्रवाइयां, नवंबर 2013 एएफडी–फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, सितंबर।

दास, राम उपेंद्र. 2015. सीएलएमवी के साथ एकीकरण की भारत की रणनीति। वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

शोध पत्र

चतुर्वेदी, सचिन. 2014. ''दक्षिण–दक्षिण सहयोग में बढ़ती गतिशीलता.'' विकास सहयोग रिपोर्ट–2014: वहनीय विकास के लिए संसाधन जुटाना. ओईसीडी, पेरिस, नवंबर।

चतुर्वेदी, सचिन और अन्य 2015। ''प्रस्तावना विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति में नैतिकता का समावेश–एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य; विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति में नैतिक बहसों का संस्थानीकरण''; यूरोप, भारत और चीन की तुलनाः सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास की तलाश–भारत से उभरते प्रमाण''; ''विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वैश्विक नैतिकता के अध्ययन का तुलनात्मक ढांचा''; 'यूरोप, भारत और चीन में नई खाद्य प्रौद्योगिकी और निष्कर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति में नैतिकता का समावेश, मिल्टोस लेडिकाज़, सचिन

चतुर्वेदी, वाई. झाओ, डी. स्टेमर्डिंग (संपादक) विज्ञान प्रौद्योगिकी अभिशासन और नैतिकता'' योरप, भारत और चीन से एक वैश्विक परिदृष्य स्प्रिंगर।

चतुर्वेदी, सचिन और शषांक, मेंदीरत्ता. 2015. ''दक्षिण–दक्षिण सहयोग के सिद्धांत और भारतीय संबंधों से प्राप्त प्रमाण, एशिया ऐंड दि वर्ल्ड इकॉनॅमी (खंड 4), 20 फ़रवरी 2015.

चतुर्वेदी, सचिन. 2015. ''निवेश और यथेष्ट प्रौद्योगिकी के स्रोत के रूप में उभरती अर्थव्यवस्थाए'' भारत से उभरते प्रमाण, एशिया ऐंड दि वर्ल्ड इकॉनॅमी, (खंड 4) 20 फ़रवरी 2014।

चतुर्वेदी, सचिन. 2015. ''दक्षिण–दक्षिण सहयोग के सिद्धांत और भारतीय अनुभव से उभरते प्रमाण और निवेष और यथेष्ट प्रौद्योगिकी के स्रोत के रूप में उभरती अर्थव्यवस्थाए'' भारत से प्रमाण, मनमोहन अग्रवाल और जॉन व्हाली (संपादित), विकास की संवहनीयता'' एशिया और विश्व व्यवस्था पर दुनिया के वैज्ञानिक संदर्भ के आर्थिक, प्रौद्योगिकीय और पर्यावरणी कारकों की भूमिका खंड 1। वर्ल्ड साइंटिफ़िक।

दास, राम उपेंद्र. 2014. भारत में व्यापार और निवेश उदारीकरण'' उत्पादकता उपलब्धियों के लिए निहितार्थ, अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य, अर्थशास्त्र और नीति जर्नल, खंड 5, अंक 3, अक्तूबर, वर्ल्ड साइंटिफ़िक।

दास, राम उपेंद्र और नित्या बत्रा. 2015. ''दक्षिण एशियाई संयोजकता को बढ़ाने के लिए नए परिदृष्य आवश्यक, ईस्ट एशिया फ़ोरम, आस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, कैनबेरा. 21 फ़रवरी 2015।

दास, पी. 2014. ''नए आर्थिक सीमांत''. आईओआरएफ की व्यापारिक डायरेक्टरी 2014.इंडियन ओशन रिम असोसिएशन (आईओआरए)।

दास,पी. 2014. भारत–अफ्रीकी व्यापार'' वर्तमान प्रवृत्तियां और नीति. जर्नल ऑफ़ स्टडीज़ इन डायनॅमिक्स ऐंड चेंज. खंड 1, अंक 7, पीपी 268–279।

डे, प्रवीर। 2014. 'डब्लूटीओ व्यापार सुगमीकरण अनुबंधः चिंताएं और समस्याएं.' इकॉनॉमिक ऐंड पोलिटिकल वीकली, खंड 49, अंक 28, जुलाई।

डे, प्रवीर। 2014. 'दक्षिण–पूर्व एशिया के साथ भारत की उभरती संयोजकताः एक अनुभूत छान–बीन' साउथ एशिया वाच ऑन ट्रेड इकोनॉमिक्स ऐंड एनवारनमेंट (एसएडब्लूटीईई), काठमांडु–पेपाल का परिचर्चा पत्र, दिसंबर।

डे, प्रबीर. 2014. 'संयोजकता और दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग : प्रगति और संभावनाएं'. एडीबीआई का कार्य पत्र रु 507। एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट (एडीबीआई) टोकियो, दिसंबर।

डे, प्रबीर. 2014. 'संयोजकता और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग, और भारत–पाकिस्तान आर्थिक सहयोग दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय एकीकरण के लिए निहितार्थ'. एम.रज़्ज़ाक़ और वाई बेसनेट (संपादित) रिजनल इंटीग्रेशन इन साउथ एशिया ट्रेंड्सः चैलेंजेज़ ऐंड प्रास्पेक्ट्स, राष्ट्रकुल सचिवालय, नवंबर

डे, प्रवीर. 2015. 'आसियन–भारत भागीदारी के तीन दशक का गुणगानः दिल्ली संवाद माला के लिए कार्यसूची', रूमेल दहिया और उदय भानु सिंह (संपादित) रीयलाइज़िंग दि आसियन–इंडिया विज़न फ़ॉर पार्टनरशिप ऐंड पॉस्परिटी। रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए), नई दिल्ली।

डे, प्रवीर. 2015. में 'दक्षिण एशिया में आर्थिक गलियारों की वकालत और आर्थिक गलियारे और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण', प्रवीर डे और कविता आयंगर (संपादित) डेवलपिंग इकोनॉमिक कॉरीडोर्स इन साउथ एशिया, एशियन डेवलॅपमेंट बैंक, मनीला।

डे, प्रवीर और अजिताभ राय चौधरी. 2015. 'दक्षिण एशिया में आर्थिक गलियारे, व्यापार की लागतें और क्षेत्रीय उत्पादन संजाल', प्रवीर डे और कविता आयंगर (संपादित) डेवलपिंग इकोनॉमिक कॉरीडोर्स इन साउथ एशिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला ।

मोहंती, एस. के. 2014. 'मंदी के दौरान आंशिक रूप से प्रभावित वैष्विक अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों में भारत के वैविध्यपूर्ण निर्यात की पड़ताल'. वित्त मंत्रालय के आर्थिक सर्वेक्षण, 2013–14 के लिए पृष्ठभूमि पत्र।

मोहंती, एस. के. 2014. 'भारत के व्यापार में पर्यावरणी दृष्टि से संवेदनशील मालः उभरती चुनौतियां और संभावनाएं.' किशाब दास (संपादित) ग्लोबलाइज़ेशन ऐंड स्टैंडर्ड्सः इश्यूज़ ऐंड चैलेंजेज़'. इंडियन बिज़नेस सिरीज़, स्प्रिंगर में ।

सहा, सव्यसाची. 2014. 'सार्वजनिक रूप से वित्तपोशित नवाचारों को बाज़ार तक ले जानाः जर्मनी से मिले सबक़'. करेंट साइंस, खंड 106, अंक 8, अप्रैल, ''सामान्य लेख के अंतर्गत प्रकाशित।

श्रीनिवास, के. रवि. 2014. 'नवाचार संकेतक और माप पुस्तिका' संपादक फ्रेड गॉल्ट (पुस्तक समीक्षा). साइंस ऐंड पब्लिक पॉलिसी, खंड 41, अंक 5, पृष्ठ 405।

लोकप्रिय स्तंभ/अभिमत

चतुर्वेदी, सचिन. 2014. 'बेहतर श्रम नीति निवेश आकर्षण की कुंजी.' मिंट 22 सितंबर।

चतुर्वेदी, सचिन. 2014. 'प्रधान मंत्री मोदी को जी20 में किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए?' सीएनबीसी, टीवी, 14 नवंबर.

दास, राम उपेंद्र. 2014. ''विदेश व्यापार नीति पटरी पर बनी रहेगी।'' दि हिंदू , 16 मई।

दास, राम उपेंद्र. 2014. सीमा पार के व्यापार को आसान बनाने के लिए ''बांगलादेशी वाहनों को इकतरफ़ा प्रवेश'', दि इकोनॉमिक टाइम्स, 26 मई।

दास, राम उपेंद्र. 2014. ''नरेंद्र मोदी की विदेश नीति दक्षेश संबंधों को मज़बूत करेगी।'' दि इकोनॉमिक टाइम्स, 26 मई।

दास, राम उपेंद्र. 2014. ''भारत के विदेशी आर्थिक कार्यों का मेनू।'' दि डिप्लोमेट, 30 मई।

दास, राम उपेंद्र. 2014. ''नरेंद्र मोदी की सरकार अब दक्षेश बैंक चाहती है।'' दि इकोनॉमिक टाइम्स 23 जुलाई।

दास, राम उपेंद्र. 2014. ''भारत ने विदेश सचिव की बैठक से पूर्व पाकिस्तान से मांगी एमएफएन की स्थिति।'' लाइवमिंट, 28 जुलाई।

सरन, श्याम. 2014. ''1962–बीजिंग के दश्य।'' बिज़नेस स्टैंडर्ड, 8 अप्रैल।

सरन, श्याम. 2014. ''भारत–चीन सीमा विवाद–असममिति के साथ निभाना।'' बिज़नेस स्टैंडर्ड, 14 अप्रैल।

सरन, श्याम. 2014. ''नाभिकीय संशोधनवाद के ख़तरे।'' बिज़नेस स्टैंडर्ड, 23 अप्रैल।

सरन, श्याम. 2014. ''क्या भारत के 'सख़्त' राज्य बनने में कोई लाभ है?'' बिज़नेस स्टैंडर्ड, 14 मई।

सरन, श्याम. 2014. ''मोदी को भारत के वैश्विक प्रभाव को अवश्य पुनर्स्थापित करना चाहिए.'' हिंदुस्तान टाइम्स, 19 मई।

सरन, श्याम. 2014. ''द मॉर्निंग ऑफ़्टर प्रिंसिपल'', बिज़नेस स्टैंडर्ड, 11 जून।

सरन, श्याम. 2014. ''पेरिस में नेतृत्व करना,'' बिज़नेस स्टैंडर्ड, 9 जुलाई।

सरन, श्याम. 2014. ''बीआरआईसीएस–वैश्विक पूंजी और आर्थिक व्यवस्था में पश्चिमी वर्चस्व का अंत'' मेनस्ट्रीम वीकली, 2 अगस्त।

सरन, श्याम. 2014. ''स्थायित्व का भारत–प्रशांत आश्रय।'' बिज़नेस स्टैंडर्ड, 12 अगस्त।

सरन, श्याम. 2014. ''फिर से जोड़–तोड़ की गुंजाइश।'' बिज़नेस स्टैंडर्ड, 12 सितंबर।

सरन, श्याम. 2014. ''भागीदारी के नवीनीकरण के लिए भारत–अमरीका संबंधों को ताज़ा चालक सेट की आवश्यकता है।'' हिंदुस्तान टाइम्स, 29 सितंबर।

सरन, श्याम. 2014. ''हिमालय को खसोटना।'' बिज़नेस स्टैंडर्ड, 12 नवंबर।

सरन, श्याम। 2014। ''ज्ञान महाशक्ति'' बिज़नेस स्टैंडर्ड, 12 नवंबर।

सरन, श्याम। 2014। ''काठमांडु में बिच्छू को पकड़ें।'' हिंदुस्तान टाइम्स, 21 नवंबर।

सरन, श्याम। 2014। ''आइए ड्रैगन के साथ बराबरी करें।'' हिंदुस्तान टाइम्स, 31 दिसंबर।

सरन, श्याम. 2015. 'दूरस्थ पड़ोसी', बिज़नेस स्टैंडर्ड, 14 जनवरी।

सरन, श्याम. 2015. ओबामा का आगमनः 'नेताओं के बारे में अधिक देशों के बारे में कम।' हिंदुस्तान टाइम्स, 27 जनवरी।

सरन, श्याम. 2015. ''यात्रा अपने–आपमें असली केक है।'' बिज़नेस स्टैंडर्ड, 10 मार्च।

सरन, श्याम. 2015. ''चीनी अर्थव्यवस्था का धीमा पड़ना एक ख़तरा।'' बिज़नेस स्टैंडर्ड, 10 मार्च।

सरन, श्याम. 2015. ''भारत और खंडित संसार।'' बिज़नेस स्टैंडर्ड, 10 मार्च

सरन, श्याम. 2015. ''एक सड़क जिस पर भारत को अवष्य चलना चाहिए।'' हिंदुस्तान टाइम्स, 19 मार्च।

शेषाद्रि, वी एस. 2015. ''प्रशांत के आर–पार की भागीदारीः यह क्या कहती है।'' इकोनॉमिक ऐंड पॉलिटिकल वीकली, 16 अगस्त।

शेषाद्रि, वी एस. 2014. 'पूर्व में करें' की नीति के निदर्षन का समय'. दि हिंदू, 13 नवंबर।

VI

आंकडे और सूचना केन्द्र

आरआईएस का अभिलेखन केंद्र विश्व अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, दुनिया की व्यापारिक प्रणालियों, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली, दक्षेश, आसियन, और आईओआर–एआरसी, जैसे क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सहित दक्षिण–दक्षिण सहयोग, पूंजी के प्रवाह, एफडीआई, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण, कृषि और खाद्य सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वहनीय विकास जैसे मुद्दों पर पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं, सरकारी प्रकाशनों, दूसरे शोध संस्थानों के मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ों के प्रचुर संग्रह के साथ अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, समाज विज्ञान के अग्रणी शोध संस्थान के रूप में काम करते हुए उसके काम–काज का अविभाज्य अंग रहा है। डेटा और सूचना केंद्र न केवल आरआईएस के शोधकर्ता संकाय को समर्थन प्रदान करता है बल्कि पूरे देश के नीति निर्मांताओं, प्रशासकों, सलाहकारों और छात्रों को भी समर्थन देता है। इस वर्ष से पुस्तकालय स्कूल छात्रों के लिए भी खुला है। अभिलेखन केंद्र की अभिलेख संग्रह नीति आरआईएस के शोध संकार की आवश्यकताओं से निर्देशित होने के साथ–साथ अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय पूंजी, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, जैव प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इत्यादि के क्षेत्र में इसे महत्त्वपूर्ण सूचना केंद्र बनाने की व्यापक नीति से संचालित होती है। विषेश संग्रह–सांख्यकीय प्रकाशनों में कृषि सांख्यकी, राष्ट्रीय लेखा सांख्यकी, बजट दस्तावेज़, श्रम सांख्यकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सांख्यकी, व्यापार और विकास सांख्यकी, आर्थिक दृष्टिकोण, एफएओ, आईएलओ, ओईसीडी, यूएन, यूएनसीटीएडी, वर्ल्ड बैंक, डब्लूटीओ इत्यादि शामिल हैं। इसमें विभिन्न मंत्रालयों और संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्टें शामिल हैं। दस्तावेज़ों में कामकाजी पर्चे, चर्चा पर्चे, पुनर्मुद्रण, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रसांगिक संगठनों के मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त पर्चे या तो नियमित रूप से पारस्परिक आदान–प्रदान के अंतर्गत प्राप्त होते हैं या संस्थानिक वेबसाइटों से डाउनलोड किए जाते हैं। ग्रंथालय के संग्रह में पंद्रह हज़ार से अधिक पुस्तकें शामिल हैं जिनमें विकास अध्ययन, अर्थशास्त्र, जनसांख्यकी, सांख्यकी, और दूसरे संबंधित विषयों की पुस्तकें हैं। यह इस समय 629 पत्र–पत्रिकाओं की नियमित ग्राहक है। इसके अलावा, इसे 40 से अधिक पत्र–पत्रिकाएं उपहार के रूप में या पारस्परिक आदान–प्रदान के तहत मिलती हैं। यह ग्रंथालय कई राष्ट्रीय–अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ प्रकाशनों के आदान–प्रदान का कार्यक्रम चलाता है।

अभिलेखन केंद्र 31 मार्च 2015 तक के ग्रंथालय का संग्रह

- पुस्तकें
- सांख्यकीय वार्षिक संदर्भ पुस्तिकें
- अभिलेख–डब्लूपी–ओपी–डीपी
- पत्र–पत्रिकाएं नियतकालिक (मुद्रित+ऑनलाइन+सीडी–रोम)
- अख़बार–भारतीय + अंतरराष्ट्रीय
- पिछले अंक
- सीडी रोम
- सीडी–रोम में डेटाबेस

आरआईएस का डेटाबेस

आरआईएस डेटा बैंक के पास अच्छी तरह से अनुरक्षित डेटाबेस हैं। हमारे पास घरेलू अंतरराष्ट्रीय व्यापार सहित व्यापर, निवेश, रोज़गार, पर्यावरण और उद्योगों के डेटाबेस हैं। अपनी परियोजनाओं के लिए डेटाबेस की उपयोगिता के मद्देनज़र हम उन्हें नियमित रूप से अपडेट करते रहते हैं।

वैश्विक डेटाबेस में शामिल हैं:

- व्यापारिक डेटाबेस, टैरिफ़ और नॉन टैरिफ़ उपाय
- देय भुगतान
- वित्त सांख्यकी
- विकास सांख्यकी
- औद्योगिक सांख्यकी
- बौद्धिक संपदा सेवाएं, नीति, सूचना और वित्तीय निष्पादन

भारतीय डेटाबेस में षामिल हैं:

- 8 दृडिजिटल स्तरों पर व्यापार पर टाइम सिरीज़ के डेटाबेस
- भारतीय कंपनियों के डेटाबेस और उनके वित्तीय निष्पादन
- सामाजिक–आर्थिक डेटाबेस
- सीमा शुल्क का डेटाबेस

आरआईएस की वेबसाइट और ऑनलाइन अभिलेखन केंद्र

आरआईएस के प्रकाशनों और उसके आयोजनों के अलावा वेबसाइट को वास्तविक समय के आधार पर अपडेट किया जाता है। शोध रिपोर्टों, नीति सारों, चर्चा पत्रों, सम्मेलन की रिपोर्टों, पत्र–पत्रिकाओं, सूचना पत्रों और समाचार पत्रों में आरआईएस के संकाय सद्स्यों के लेखों जैसे सारे विवरण मुक्त रूप से डाउनलोड किए जा सकते हैं। सामग्रियां ट्विटर, फ़ेसबुक, और लिंक्डइन जैसी प्रमुख लोकप्रिय सोशल नेटवर्क साइटों के माध्यम से साझा की जा सकती हैं। हिट्स की संख्या में वृद्धि के साथ आरआईएस की साइटों की लोकप्रियता दिनों–दिन बढ़ रही है। आरआईएस की वेबसाइट हमेशा गूगल द्वारा समर्थित तलाश परिणामों में सबसे ऊपर दिखाई देती है, जिसका आषय यह है कि वेबसाइट की दृश्यता सबसे अच्छी होती है।आरआईएस की वेब साइट के पास भाषा अनुवाद है जो इस वेबसाइट की समाग्री को दुनिया भर में ग्राहक के अनुकूल बना देता है।

आरआईएस यूट्यूब चैनल

आरआईएस पास यूट्यूब चैनल जिसमें टीवी पर आरआईएस का कवरेज और आरआईएस के प्रमुख हालिया आयोजन शामिल हैं।

आरआईएस फैसबुक और ट्विटर पर

आरआईएस फेसबुक और ट्विटर पर उपलब्ध है। फेसबुक एकाउंट https://www.facebook.com/RISIndia और ट्विटर हैन्डल @RIS_NewDelhi है।

VII

मानव संसाधन

प्रो. विश्वजीत धर, पीएचडी

महानिदेशक (30 मई 2014 तक)

विशेषज्ञता : व्यापार एवं विकास संबंधी मामलें, अंतर्राष्ट्रीय वित्त, बौद्धिक संपदा अधिकार परम्परागत जानकारी, जैवविविध्ता का संरक्षण एवं अनवरत प्रयोग कृषि तथा तकनीकी मानक एवं खाद्य पदार्थों विनियम व्यापार एवं पर्यावरण

प्रो. सचिन चतुर्वेदी, पीएचडी

महानिदेशक (10 सितंबर 2014 से)

विशेषज्ञता : अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामले, प्रौद्योगिकी एवं नवप्रवर्तन तथा विकास सहयोग

संकाय

प्रोफेसर एस के मोहंती, पीएचडी

विशेषज्ञता: वैश्विक एवं क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण तथा विकास संबंधी आर्थिक मामले

प्रोफेसर राम उपेन्द्र दास, एम फिल, पीएचडी

विशेषज्ञता: अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय एकीकरण एवं विकास संबंधी मामले

प्रोफेसर प्रबीर डे, पीएचडी

विशेषज्ञता : अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं परिवहन संबंधी सुविधाएं, सेवा क्षेत्र में व्यापार

डॉ. बीना पाण्डेय, पीएचडी
अनुसंधान एसोसिएट
विशेषज्ञता: सामाजिक क्षेत्र, जेंडर सशक्तिकरण एवं विकास संबंधी मामले

डॉ. साब्यासाची साहा, पीएचडी
सहायक प्रोफेसर
विशेषज्ञता: प्रौद्योगिकी एवं विकास, नवाचार और बौद्धिक संपदा अधिकार, आर्थिक विकास एवं विश्व व्यापार संगठन

डॉ. प्रियदर्शी दास, पीएचडी
अनुसंधान एसोसिएट
विशेषज्ञता: समष्टि अर्थव्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्त

सुश्री श्रेया पान
अनुसंधान सहायक
विशेषज्ञता: वैश्विक व्यापार

डॉ. अमित कुमार, पीएचडी
अनुसंधान सहयोगी
विशेषज्ञता–नवप्रवर्तन, दूरदर्षिता एवं नियंत्रण

श्री सुनंदो बासू, एम फिल
अनुसंधान सहयोगी
विशेषज्ञता–व्यावहारिक अर्थमित्तीय, विधि एवं अर्थशास्त्र तथा विकास

सुश्री अदिति झा
अनुसंधान सहायक

सलाहकार

प्रो. टी सी जेम्स
विशेषज्ञता : बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी (आईपीआर) कानून एवं संबद्ध नीति

डॉ. के रवि श्रीनिवास
विशेषज्ञता : बौद्धिक संपदा अधिकार एवं वैश्विक व्यापार

श्री सुशील कुमार
विशेषज्ञता : अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त

सुश्री आदिति गुप्ता
विषेषज्ञता: समष्टि अर्थव्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

डॉ. धुरैराज कुमारस्वामी
विषेषज्ञता: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवम एफडीआई

सलाहकार

सुश्री रमा अरूण कुमार

विशेषज्ञता : अंतर्राश्ट्रीय व्यापार एवं वित्त

श्री सायन सामंत

विशेषज्ञता : विकास अर्थव्यवस्था

सुश्री शिप्रा निगम

विशेषज्ञता: प्रगति एवं विकास की समष्टि अर्थव्यवस्था, आर्थिक नीति

श्री जय देव दूबे

विशेषज्ञता : अर्थषास्त्रा, माइक्रो–इकनॉमिक एवं एप्लाइड मैक्रो–इकनॉमिक्स

विजिटिंग फैलो

प्रो. मिलिंदो चक्रवर्ती

विशेषज्ञता: विकास अर्थव्यवस्था, परिवेक्षण एवम परिणाम निर्धारण

प्रो. चन्द्रा मोहन

विशेषज्ञता: आर्थिक एवंम् व्यापार व्याखयाकार

अनुसंधान सहायक

सुश्री पायल चटर्जी

श्री प्रत्युश

सुश्री नित्या बत्रा

सुश्री आस्था गुप्ता

सुश्री हरप्रीत कौर

सुश्री वृंदा सेकसरिया

अनुसंधान सहायक

श्री मनमीत सिंह अजमानी

सुश्री सुरभि अग्रवाल

सुश्री श्रुति शर्मा

श्री मोनू सिंह राठोर

सुश्री गमिका ठक्कर

श्री रोशन किशोर

श्री साहिल अरोड़ा

सुश्री सोनाक्षी जैन

श्री विनायक पांडे

श्री प्रतीक कुकरेजा

श्री कुनाल सिंह

सुश्री टी.एम. वासुप्रदा

सहायक वरिष्ठ अध्येता

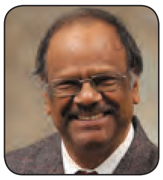

डॉ. मनमोहन अग्रवाल

डॉ. अमृता नरलिकर
राष्ट्रपति, वैश्विक और क्षेत्रीय अध्ययन के लिए जर्मन संस्थान (GIGA), हैम्बर्ग, जर्मनी हैम्बर्ग, हैम्बर्ग, जर्मनी के विश्वविद्यालय में प्राध्यापकीय चेयर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था, पोलिस, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में रीडर, डार्विन कॉलेज, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के लिए वरिष्ठ रिसर्च एसोसिएट, केंद्र सरकार, विश्वविद्यालय

प्रो. मुकुल अशर
प्रोफेसर, ली कुआन येव स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगाफर

डॉ. बालाकृष्णा पिसुपति
पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण, भारत सरकार

सहायक अध्येता

डॉ. केविन पी गालाघेर,
प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन्स, बॉस्टन यूनिवर्सिटी, सीनियर एसोसिएट, जीडीएई, टफ्रट्स यूनिवर्सिटी

डॉ. रामकिशन एस राजन
एसोसिएट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, जार्ज मैसॉन यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन डी.सी.

डॉ. सूमा अथरयी
रीडर, ब्रूनल बिज़नेस स्कूल, ब्रूनल यूनिवर्सिटी, अक्सब्रिज

डॉ. श्रीविद्या रागवन
एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा, कॉलेज ऑफ लॉ, नॉरमन, ओक्लाहोमा

स्टाफ के अन्य सदस्य

श्री महेश सी अरोड़ा
निदेशक, वित्त एवं प्रशासन

महानिदेशक कार्यालय
श्री तीश कुमार मल्होत्रा, प्रभारी, महानिदेशक कार्यालय
श्रे एन एन कृष्णन, निजी सचिव
श्रीमती रिंतु परनामी, निजी सहायक
श्री सचिन कुमार, सचिवीय सहायक

प्रकाशन विभाग
श्री तीश कुमार मल्होत्रा, प्रकाशन अधिकारी
श्री सचिन सिंघल, प्रकाशन सहायक
(वेब और डिजाइन)
सुश्री रूचि वर्मा, प्रकाशन सहायक (संपादकीय)

आंकड़ा एवं सूचना केन्द्र
श्रीमती सरिता कपूर, प्रलेखन अधिकारी
श्रीमती ज्योति, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
श्रीमती सुशीला, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
श्री सुधीर राणा, पुस्तकालय सहायक

सूचना प्रौद्योगिकी/डॉटाबेस एकक
श्रीमती सुषमा भट्ट, उपनिदेशक, आंकड़ा प्रबंधन
श्री चन्द्र शेखर फरी, उपनिदेशक, प्रणाली
श्रीमती पूनम मल्होत्रा, कम्प्यूटर सहायक
श्री सत्यपाल सिंह रावत, उवर डिवीजन कलर्क (हार्डवेयर)
श्रीमती गीतिका शर्मा, डाटा एट्री आपॅरेटर/इन्टरनेट
श्री राहुल भारती, वेब डिजाइनर

वित्त एवं प्रशासन
श्री वी कृष्णामणि, उपनिदेशक (वित्त एवं लेखा)
श्री डी पी काला, उपनिदेशक (प्रशासन एवं स्थापना
श्रीमती शीला मल्होत्रा, अनुभागअधिकारी(लेखा)
श्री हरकेश, सहायक
श्रीमती अनु बिष्ट, सहायक (प्रोग्राम
श्री सुरजीत, लेखाकार
श्री अनिल गुप्ता, सहायक
श्री पियूष वर्मा, अवर श्रेणी लिपिकं
श्रीमती शालिनी शर्मा, स्वागती

अनुसंधान सहयोग
सुश्री किरन वाघ, निजी सचिव
श्रीमती सुजाता तनेजा, निजी सचिव
श्री संजीव शर्मा, निजी सचिव
श्री सुरेन्द्र कुमार, निजी सहायक
श्री अलोक कुमार, सचिवीय सहायक
श्रीमती बिन्दु गंभीर, आषुलिपिक

सहायक स्टाफ
श्री सत्यवीर सिंह, वरिष्ठ स्टाफ कार चालक
श्री जे बी ठाकुरी, स्टाफ कार चालक
श्री बलवान, दफतरी
श्री प्रदीप
श्री राजू
श्री राज कुमार
श्री मनीष कुमार
श्री राज कुमार
श्री बिरजू
श्री प्रदीप नेगी

VIII

वितीय विवरण

सिंह कृष्णा एंड एसोसिएटस्
चार्टर्ड एकाउंटेंटस्
भूतल, कृष्णा मार्किट, कालकाजी, नई दिल्ली-110019
टेलीफोन नं0 32500444, टेलीफैक्स : 40590344, ई-मेल : skaca@airtelmail.in

लेखा परीक्षकों की निष्पक्ष रिपोर्ट

विकासशील देशों की अनुसंधन एवं सूचना प्रणाली की आम सभा के सदस्यों कोः

वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हमने संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1960 के अंतर्गत पंजीकृत समिति विकासशील देशों की शोध और सूचना प्रणाली (आरआईएस) के है जिसमें 31 मार्च 2015 की बैलेंस शीट, उस समय समाप्त हुए वर्ष के आय–व्यय का लेखा और प्राप्ति और भुगतान का लेखा और महत्त्वपूर्ण लेखा पालन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक सूचना का सारांश शामिल है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखापालन सिद्धांतों के अनुरूप समिति की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और उसकी प्राप्ति और भुगतान का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रदान करने वाले वित्तीय विवरण तैयार करना प्रबंधन का दायित्व है। इस दायित्व में सही और निष्पक्ष पर्यावलोचन प्रस्तुत करने वाले और जालसाजी या चूक वश सारभूत मिथ्या कथन से मुक्त वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन, कार्यान्वति और अनुरक्षण शामिल है।

लेखा परीक्षक का दायित्व

अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना हमारा दायित्व है। हमने अपनी लेखा परीक्षा इंन्सटीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की है। ये मानक मांग करते हैं कि नैतिक शर्तों और योजना का पालन करें और इसका तर्कसंगत आश्वासन पाने के लिए लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण सारभूत मिथ्याकथन से मुक्त हैं।

लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और उद्‌घाटनों के बारे में लेखा परीक्षा संबंधी प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल होता है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर होती हैं, जिसमें वित्तीय विवरण में जालसाजी के तहत या चूक वश सारभूत मिथ्याकथन के जोखिम का मूल्यांकन भी शामिल होता है। उन जोखिमों का मूल्यांकन करते समय लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा प्रक्रिया जो उन स्थतियों में उपयुक्त होता है लेकिन समिति के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता पर राय व्यक्त करने के अभिप्राय से उपयुक्त नहीं होता, डिजाइन करने के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने और निष्पक्ष रूप से उसके प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक समिति के आंतरिक नियंत्रण पर भी विचार करता है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा परीक्षा नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन भी शामिल होता है और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखा पालन संबंधी आकलनों के मूल्यांकन के साथ–साथ वित्तीय विवरण के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा प्रमाण जुटाए हैं वे लेखा परीक्षा संबंधी हमारी राय का आधार प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त और समुचित हैं।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और राय

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) हमने वे सारी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्त्म ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे।

(ii) हमारी राय में जहां तक प्रतीत होता है उसके अनुसार समति ने कानूनन वांछित सेवा बहियां तैयार की हैं।

(iii) बैलेंस शीट, आय–व्यय खाता और प्राप्ति और भुगतान खाता, इस रिपोर्ट में जिनका निपटारा किया गया है, लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

(iv) हमारी राय में बैलेंस शीट, आय और व्यय खाता और प्राप्ति और भुगतान खाता, इस रिपोर्ट में जिनका निपटारा किया गया है, इन्सटीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंन्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी प्रयोज्य लेखापालन मानकों का अनुपालन करते हैं।

(v) हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कथित विवरण आमतौर पर भारत में अपनाए जाने लेखापालन सिद्धांतों के अनुरूप सत्य और निष्पक्ष पर्यावलोकन प्रदान करते हैं।

   क) समिति के 31 मार्च 2015 के कामकाज की स्थिति के बैलेंस शीट के मामले में;

   ख) उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के अधिशेष के आय–व्यय के खाते के मामले में; और

   ग) उस तिथि पर समाप्त हुए वर्ष की प्राप्तियों और भुगतानों के प्राप्ति–भुगतान खाते के मामले में।

कृते सिंह कृष्णा एंड एसोसिएटस्
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण सं0 : 008714C

(कृष्ण कुमार सिंह)
साझेदार, सदस्य सं0 077494

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 28.09.2015

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली
(1860 के सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी)

31 मार्च 2015 को बैलेंस शीट

में धनराशि `

	अनुसूची #	को 31-Mar-15	को 31-Mar-14
देयताएं			
अनुसंधान एवं विकास निधि	1	92,643,533.70	92,270,422.84
अचल आस्तियों की निधि (गैर-एफसीआरए)	2	23,942,160.00	21,794,229.00
अचल आस्तियों की निधि (एफसीआरए)		230,362.00	456,533.00
प्रायोजित परियोजनाओं का खर्च नहीं किया गया बकाया (गैर-एफसीआरए)	3	9,447,691.00	12,069,473.00
प्रायोजित परियोजनाओं का खर्च नहीं किया गया बकाया (एफसीआरए)		8,484,119.00	8,345,185.00
वर्तमान देयताएं और प्रावधान (गैर-एफसीआरए)	4	35,395,171.00	21,034,720.00
वर्तमान देयताएं और प्रावधान (एफसीआरए)		210,061.00	1,315,819.00
कुल		**170,353,097.70**	**157,286,381.84**
ifjlifÙk;k			
अचल ifjlifÙk;k (गैर-एफसीआरए)	5	23,942,160.00	21,666,349.00
अचल ifjlifÙk;k (एफसीआरए)		7,275,067.00	978,998.00
निस्तारण के लिए रोकी गयी ifjlifÙk;k (गैर-एफसीआरए)		-	127,880.00
निस्तारण के लिए रोकी गयी ifjlifÙk;k (एफसीआरए)		-	110,798.00
प्रायोजित परियोजनाओं से वापस मिल सकने योग्य धनराशि (गैर-एफसीआरए)	3	13,097,790.00	4,940,681.00
प्रायोजित परियोजनाओं से वापस मिल सकने योग्य धनराशि (एफसीआरए)		1,122,702.00	1,588,412.00
वर्तमान ifjlifÙk;k ऋण, अग्रिम राशि आदि (गैर-एफसीआरए)	6	62,110,210.91	63,095,536.67
वर्तमान ifjlifÙk;k] ऋण, अग्रिम राशि आदि (एफसीआरए)		62,805,167.79	64,777,727.17
कुल		**170,353,097.70**	**157,286,381.84**

खातों पर उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां 15

1 से लेकर 15 तक की अनुसूचियां खातों के अभिन्न हिस्से का निर्माण करती है।

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न है

विकासशील देशों हेतु अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली के लिए

सिंह कृष्णा एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म की पंजीकरण संख्या 008714C है

Sd/-
(कृष्ण कुमार सिंह)
साझीदार
lnL;rk l 077494

Sd/-
महेश सी. अरोड़ा
निदेशक (वित्त एवं प्रशासन)

Sd/-
प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक

स्थान : नयी दिल्ली
तारीख: 28.09.2015

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली
(1860 के सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी)

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता

में धनराशि `

	Schl #	वर्ष समाप्त 31-Mar-15	वर्ष समाप्त 31-Mar-14
आय			
भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के पास से सहायता अनुदान	4 (a)	48,432,521.00	52,118,725.00
प्रायोजित परियोजनाओं का अनुदान कार्यक्रम के खर्चों को पूरा करने के लिए हस्तांतरित किया गया (गैर-एफसीआरए एफसीआरए)	3	39,672,955.00	21,226,891.74
प्रायोजित परियोजनाओं के पूरा होने पर हस्तांतरित की गयी बेशी धनराशि (गैर-एफसीआरए और एफसीआरए)		812,845.00	1,514,240.38
रायल्टी, प्रकाशनों आदि से आय (गैर-एफसीआरए)		110,507.00	114,162.00
अर्जित ब्याज:			
सावधि जमाओं पर (एफसीआरए)		5,214,042.46	5,055,311.69
सावधि जमाओं पर (गैर-एफसीआरए)		3,533,963.17	3,696,792.12
बचत खाते/ऑटो स्वीप खाते पर (एफसीआरए)		198,415.16	186,468.05
बचत खाते/ऑटो स्वीप खाते पर (गैर-एफसीआरए)		312,073.27	454,407.50
कर्मचारियों के लिए ऋण पर (गैर-एफसीआरए)		13,043.00	7,289.00
आयकर की वापसी पर (गैर-एफसीआरए)		-	860.00
अन्य फुटकर आय (गैर-एफसीआरए)		31,787.00	7,036.34
प्रायोजित परियोजनाओं (गैर-एफसीआरए) और (एफसीआरए) से बंधे खर्चों के लिए उगाहियां		610,481.00	-
अवधि पूर्व की आय		21,000.00	-
अचल आस्तियों की निधि से हस्तांतरित की गयी धनराशि - बेची गयी/lekIr dh x;h ifjlifÙk;k की डब्ल्यू.डी.वी (गैर-एफसीआरए और एफसीआरए)	2	431,208.00	178,628.00
अचल ifjlifÙk;k से हस्तांतरित धनराशि - भारत सरकार से सहायता अनुदान से हासिल की गयी अचल ifjlifÙk;k /प्रायोजित परियोजनाओं पर जमा (गैर-एफसीआरए और एफसीआरए)		2,114,180.00	1,910,434.00
कुल		**101,509,021.06**	**86,471,245.82**
व्यय			
कार्यक्रम के lc/kh 0;; - प्रायोजित परियोजनाएं (गैर-एफसीआरए एफसीआरए)	7	39,672,955.00	21,226,891.74
प्रतिष्ठान के 0;; (गैर-एफसीआरए)	8	41,580,210.00	41,319,256.00
प्रशासनिक एवं कार्यक्रम के अन्य 0;;(गैर-एफसीआरए)	9	15,582,464.20	15,497,729.89
प्रशासनिक एवं कार्यक्रम के अन्य 0;; (एफसीआरए)	10	192,789.00	260,566.13
अचल ifjlifÙk;k पर ह्रास (गैर-एफसीआरए)	5	3,205,145.00	1,966,093.00
प्रायोजित परियोजनाओं के पूरा होने पर हस्तांतरित की गयी धनराशि (गैर-एफसीआरए और एफसीआरए)	3	645,900.00	-
अवधि पूर्व के 0;;		256,447.00	-
D		-	171,202.00
अनुसंधान एवं विकास निधि को हस्तांतरित vfrfjDr ?kkV dh jkf'k@(घाटा)		373,110.86	6,029,507.06
कुल		**101,509,021.06**	**86,471,245.82**

खातों पर उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां 15

1 से लेकर 15 तक की अनुसूचियां खातों के अभिन्न हिस्से का निर्माण करती है।

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न है

सिंह कृष्णा एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटैंट्स
फर्म की पंजीकरण संख्या 008714C है

विकासशील देशों हेतु अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली के लिए

Sd/-
(कृष्ण कुमार सिंह)
साझीदार
lnL;rk l 077494

Sd/-
महेश सी. अरोड़ा
निदेशक (वित्त एवं प्रशासन)

Sd/-
प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक

स्थान : नयी दिल्ली
तारीखः 28.09.2015

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली
(1860 के सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी)

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रसीद और भुगतान खाता

में धनराशि `

	रसीदें	वर्ष समाप्त 31-Mar-15		वर्ष समाप्त 31-Mar-14	
	बकाया				
i)	हाथ में रोकड़ (गैर-एफसीआरए)	16,296.00		124,927.00	
ii)	बैंक में बकाया रकम :				
	बचत खातों में - आंध्रा बैंक	14,585.00		16,244.00	
	बचत खातों/ऑटो स्वीप में - बैंक ऑफ इंडिया (गैर-एफसीआरए)	8,845,428.90		15,716,539.95	
	बचत खातों/ऑटो स्वीप में - बैंक ऑफ इंडिया (एफसीआरए)	4,273,434.40		1,758,644.86	
	सावधि जमाओं में - बैंक ऑफ इंडिया (एफसीआरए)	53,486,085.00		50,157,302.77	
	सावधि जमाओं में - बैंक ऑफ इंडिया (गैर-एफसीआरए)	44,822,121.50		40,469,955.67	
iii)	डाक शुल्क के टिकट - फ्रैंकिंग मशीन में बकाया (गैर-एफसीआरए)	144,493.00		59,495.00	
	कुल ए		111,602,443.80		108,303,109.25
बी	**प्राप्त अनुदान**				
i)	भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के पास से	52,800,000.00		53,500,000.00	
ii)	विभिन्न प्रायोजित परियोजनाओं के पास से (गैर-एफसीआरए)	23,288,760.00		17,909,814.87	
iii)	विभिन्न प्रायोजित परियोजनाओं के पास से (एफसीआरए)	9,882,929.00		12,279,009.49	
	कुल बी		85,971,689.00		83,688,824.36
C	**प्राप्त ब्याज**				
i)	ऋणों, अग्रिम राशियों आदि पर ब्याज (गैर-एफसीआरए)	13,428.00		7,289.00	
ii)	बचत खाता/ऑटो स्वीप पर ब्याज (एफसीआरए)	183,336.16		186,468.05	
iii)	सावधि जमा खातों पर ब्याज (गैर-एफसीआरए)	3,196,548.26		1,452,165.83	
iv)	सावधि जमा खातों पर ब्याज (एफसीआरए)	4,545,779.53		3,328,782.23	
v)	बचत खाता/ऑटो स्वीप पर ब्याज (गैर-एफसीआरए)	292,231.27		453,730.50	
vi)	बचत खाता पर ब्याज -आंध्रा बैंक (गैर-एफसीआरए)	3,080.00		677.00	
vii)	आयकर वापसी पर ब्याज	-		860.00	
	कुल सी		8,234,403.22		5,429,972.61
	कुल आगे ले जाया गया		**205,808,536.02**		**197,421,906.22**

	भुगतान	वर्ष समाप्त 31-Mar-15		वर्ष समाप्त 31-Mar-14	
	व्यय (गैर-एफसीआरए)				
i)	प्रतिष्ठान के खर्चे (अनुसूची - 11)	36,564,081.00		41,615,824.00	
ii)	प्रशासनिक एवं कार्यक्रम के अन्य खर्चे (अनुसूची - 12)	13,079,802.20		15,340,992.89	
iii)	कार्यक्रम के खर्चे - प्रायोजित परियोजनाएं (अनुसूची - 14)	22,055,975.00		16,611,105.87	
iv)	अवधि पूर्व के खर्चे	256,447.00		-	
	कुल ए		71,956,305.20		73,567,922.76
बी	**व्यय (एफसीआरए)**				
i)	प्रशासनिक एवं कार्यक्रम के अन्य खर्चे (अनुसूची - 13)	555.00		240,186.13	
ii)	कार्यक्रम के खर्चे - प्रायोजित परियोजनाएं (अनुसूची - 14)	9,442,684.00		6,102,060.87	
	कुल बी		9,443,239.00		6,342,247.00
C	**अचल आस्तियों के लिए भुगतान**				
i)	अचल आस्तियों के लिए भुगतानस (गैर-एफसीआरए)	3,485,752.00		1,579,666.00	
ii)	अचल आस्तियों के लिए भुगतान (एफसीआरए)	5,327,407.00		3,091,558.00	
	कुल सी		8,813,159.00		4,671,224.00
डी	**अग्रिम राशियां और जमाएं**				
i)	अग्रिम राशियां (गैर-एफसीआरए)	464,396.00		55,163.00	
ii)	अग्रिम राशियां (एफसीआरए)	719.00		19,536.00	
iii)	प्राप्त होने योग्य टीडीएस (गैर-एफसीआरए)	328,229.00		128,071.00	
iv)	प्रतिभूति जमा (गैर-एफसीआरए)	3,500.00		-	
	कुल डी		796,844.00		202,770.00
ई	**अन्य**				
i)	वापस लौटाये गये अनुदान (गैर-एफसीआरए)	2,845,627.00		615,140.00	
ii)	वापस लौटाये गये अनुदान (एफसीआरए)	560,740.00		-	
iii)	आयकर	-		171,202.00	
iv)	आयकर - विवादित मांगें	-		899,050.00	
	कुल ई		3,406,367.00		1,685,392.00
	कुल आगे ले जाया गया		**94,415,914.20**		**86,469,555.76**

	रसीदें	वर्ष समाप्त 31-Mar-15		वर्ष समाप्त 31-Mar-14			भुगतान	वर्ष समाप्त 31-Mar-15		वर्ष समाप्त 31-Mar-14	
	कुल आगे yk;k x;k		**205,808,536.02**		**197,421,906.22**		**कुल आगे yk;k**		**94,415,914.20**		**86,469,555.76**
डी	**अन्य आय**										
i)	प्रकाशन की बिक्रियां (गैर-एफसीआरए)	9,210.00		22,055.00		**एफ**	**रोकड़ बाकी**				
ii)	रॉयल्टी (गैर-एफसीआरए)	93,372.00		79,911.00		i)	हाथ में रोकड़ (गैर-एफसीआरए)	30,987.00		16,296.00	
iii)	फुटकर आय (गैर-एफसीआरए)	31,787.00		7,036.34		ii)	बैंक में बकाया रकम :				
	कुल डी		134,369.00		109,002.34		बचत खातों में - आंध्रा बैंक (गैर-एफसीआरए)	87,412.00		14,585.00	
ई	**अग्रिम राशियां और जमाएं**						बचत खातों/ऑटो स्वीप में - बैंक ऑफ इंडिया (गैर-एफसीआरए)	24,103,735.28		8,845,428.90	
i)	ऋण/अग्रिम राशियों की पुनःप्राप्ति (गैर-एफसीआरए)	27,620.00		475,247.00			बचत खातों/ऑटो स्वीप में - बैंक ऑफ इंडिया (एफसीआरए)	2,829,948.96		4,273,434.40	
ii)	स्टाफ से वसूली गयी अग्रिम राशियां (गैर-एफसीआरए)	47,390.00		33,180.00			सावधि जमाओं में - बैंक ऑफ इंडिया (एफसीआरए)	54,475,828.13		53,486,085.00	
iii)	ऋण/अग्रिम राशियों की पुनःप्राप्ति (एफसीआरए)	15,147.00		5,639.00			सावधि जमाओं में - बैंक ऑफ इंडिया (गैर-एफसीआरए)	30,047,127.45		44,822,121.50	
iv)	पुराने चेक (गैर-एफसीआरए)	78,527.00		2,810.00		iii)	डाक शुल्क के टिकट - फ्रैंकिंग मशीन में बकाया (गैर-एफसीआरए)	156,248.00		144,493.00	
v)	टीडीएस की वापसी (गैर-एफसीआरए)	-		9,510.00			**कुल एफ**		111,731,286.82		111,602,443.80
vi)	अग्रिम रूप से प्राप्त की गयी धनराशि (गैर-एफसीआरए)	1,799.00		-							
	कुल ई		170,483.00		526,386.00						
एफ	**अन्य**										
i)	अचल ifjlifÙk;k की बिक्री	33,813.00		14,705.00							
	कुल एफ		33,813.00		14,705.00						
	कुल		**206,147,201.02**		**198,071,999.56**		**कुल**		**206,147,201.02**		**198,071,999.56**

खातों पर उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां (अनुसूची- 15)

1 से लेकर 15 तक की अनुसूचियां खातों के अभिन्न हिस्से का निर्माण करती है।

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न है

सिंह कृष्णा एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटैंट्स
फर्म की पंजीकरण संख्या 008714C है

Sd/-
(कृष्ण कुमार सिंह)
साझीदार
lnL;rk l% 077494

स्थान : नयी दिल्ली
तारीखः 28.09.2015

विकासशील देशों हेतु अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली के लिए

Sd/-
महेश सी. अरोड़ा
निदेशक (वित्त एवं प्रशासन)

Sd/-
प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक

अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यसूची को स्वरूप प्रदान करने के लिए नीतिगत अनुसंधान

आरआईएस
विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

कोर 4-बी, चौथा तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड,
नई दिल्ली - 110 003, भारत
दूरभाष: 91-11-24682177-80 फैक्स: 91-11-24682173-74
ई-मेल: dgoffice@ris.orgin वेबसाइट: http://www.ris.org.in